हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 मार्च, 2006

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 20 मार्च, 2006

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2) 33
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 37
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(2) 47
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :	(2) 48
पूरे राज्य में पहले ओस द्वारा तथा अब बेमौसमी वर्षा के कारण रबी फसलों विशेषकर गेहूं तथा सरसों की क्षति सम्बन्धी ।	
वाक आउट	(2) 49
वक्तव्य :	(2) 49
राजस्व मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	
वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा	(2) 55

HVS/Lib 9

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 20 मार्च, 2006

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (डा० रघुबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या-391

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राधे श्याम शर्मा अमर सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Construction/Upgradation of Sub-station

***430. Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Power be pleased to state the number of those Sub-stations construction/upgradation work of which was started during the year 2004 alongwith the number of Sub-stations commissioned/up-graded during the year 2004 and 2005 ?

Power Minister (Shri Vinod Kumar Sharma) : The work for construction of upgraded 33new sub-stations and upgradation of 7 No. sub-stations was started during the year 2004. 35 No. new sub-stations were commissioned and 14 No. sub-stations upgraded in the year 2004 and 20 No. new sub-stations were commissioned and 3 No. sub-stations were upgraded during 2005.

डा0 सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मार्च, 2005 के बाद कितने नये सब-स्टेशनों पर काम शुरू किया गया है। उनमें से कितनों पर अब काम चल रहा है और कितने पूरे हो चुके हैं ? इसके साथ-साथ दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि मार्च, 2005 में ट्रांसफार्मर खरीदने के कितने आर्डर दिए गए हैं और कितने ट्रांसफार्मर खरीदे गये हैं तथा इस समय कितने ट्रांसफार्मरों की स्टेट में कमी है? इसकी पूरी जानकारी मंत्री जी दें।

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि 2005 में 20 नये सब-स्टेशन लगाये गये और 83 एग्जिस्टिंग सब-स्टेशंज का आगुमैंटेशन का कार्य किया गया। जो दूसरा सवाल मेरे माननीय साथी ट्रांसफार्मर्ज के बारे में पूछ रहे हैं यह सवाल का हिस्सा नहीं है कि कितने ट्रांसफार्मर खरीदने के आर्डर दिए गए और कितने खरीदे गये। इस बारे में मेरे माननीय साथी अलग से लिखकर दे दें उनको पूरी जानकारी दे दी जायेगी।

डा0 सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मार्च 2005 के बाद में यह सरकार बनी है उसके बाद जो सब-स्टेशन नये लगाये गये या लगाने का काम शुरू हुआ उनके बारे में मैं जानना चाह रहा था। मंत्री जी ने जो जानकारी दी है वह तो पिछली सरकार के समय में जिन पर काम शुरू हुआ था उनकी जानकारी दी है। मेरे सवाल का इन्होंने अधूरा जवाब दिया है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार के बनने के बाद कितने नये सब-स्टेशन बनाने का काम शुरू किया गया है ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 में जितने सब-स्टेशन्ज़ आगुमैंट हुऐ हैं अगर माननीय साथी उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इनको सारी डिटेल भी बता सकता हूं। सब-स्टेशन का नाम और उसकी कैपेसिटी भी इनको बता सकता हूं। अगर ये सुनना चाहते हों तो मैं सारी डिटेल हाउस में पढ़ देता हूं। (विघ्न)

डा0 सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय के रिप्लाई से सन्तुष्ट नहीं हूं, जिन सब-स्टेशन्ज़ का ये जिक्र कर रहे हैं उन सब स्टेशन्ज़ को पिछली सरकार ने कमीशन किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनके रिप्लाई से सन्तुष्ट नहीं हूं।

Shri Vinod Kumar Sharma : During the year 2005, 23 No. new sub-stations were commissioned and 83 existing sub-stations were augmented during the year 2005 are as follows :—

New Sub-stations Commissioned during 2005

Sr. No.	Name of Sub-Station	Capacity added	Cost (Rs. in Lacs)	Date of commissioning	Name of District
I.	**132 KV**				
1.	Shahpur Begu (New) (upgraded)	25 MVA	276	27-1-2005	Sirsa
2.	Julana (New) (upgrated)	16 MVA	347	11-4-2005	Jind
	Total (I)		**623**		
II.	**66 KV**				
1.	Talakaur	16 MVA	155	22-2-2005	Yamunanagar
2.	Harsaru	16 MVA	300	7-4-2005	Gurgaon
3.	Hasanpur (New) (upgraded)	16 MVA	331	20-5-2005	Faridabad

डा० सीता राम : डिस्ट्रिक्ट सिरसा में जिन सब-स्टेशन्ज़ का ये जिक्र कर रहे हैं वे सारे हमारी सरकार के समय के बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये सब-स्टेशन्ज़ किस-किस डेट को शुरू किए गए इनके कमीशनिंग में कितना टाईम लगा और मार्च, 2005 के बाद कितने सब-स्टेशन ऑगुमैंट किए गए हैं और कितने अभी अधूरे हैं जिन पर काम चल रहा है ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि वर्ष 2005 में कितने सब-स्टेशन्ज़ कमीशन हुए हैं। सप्लीमैंट्री में भी इन्होंने यही पूछा है और मैंने इनको कमीशन किए गए सब-स्टेशन्ज़ के बारे में बताया है। जो सब स्टेशन कमीशन किए गए हैं मैं यह इनको बता देता हूं। नवम्बर, 2005 में जीन्द में, एक 66 के0वी0ए0 का हरसुक में किया गया है और इस पर 300 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसी प्रकार से गुड़गांव हसनपुर में न्यू 16 के०वी०ए० का 20-5-2005 को ऑगुमैंट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये चाहें तो मैं यह सारी लिस्ट यहां पर हाउस में पढ़ देता हूं लेकिन इसमें काफी समय लगेगा।

डा0 सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि मार्च, 2005 के बाद कितने शुरू किए गए हैं, कितने सब स्टेशन्ज़ अधूरे पड़े हुए हैं, 2005 के बाद कितने कमीशन किए गए हैं और कितनों पर काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सब स्टेशन बनने में 5-6 महीने से लेकर करीब एक साल का समय कम से कम लग जाता है। (विघ्न) इस साल के पहले कितने सब-स्टेशन्ज कमीशन्ड हुए हैं। और इसके अलावा क्या यह तय है कि कितने सब स्टेशन्ज़ कब तक शुरू हो जाएंगे ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इनके सवाल का जवाब इनको लिखित में दे दिया जाएगा।

चौ0 धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो गांव सब-स्टेशन लगाने के लिए अपनी पंचायत की जमीन मुफ्त में देंगे क्या उनके लिए प्रॉयोरिटी पर सब-स्टेशन लगाने का अलग से कुछ प्रावधान है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि खानपुर कलां गांव की पंचायत ने सब स्टेशन के लिए मुफ्त जमीन दी है क्या इस गांव को सब स्टेशन से जोड़ दिया जाएगा ? अब तक ऐसा नहीं किया गया है और खानपुर कलां गांव में डायरैक्ट लाईन से इस गांव को नहीं जोड़ा गया है। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खानपुर कलां को डायरैक्ट लाईन से कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी श्री मलिक साहब को यह बताना चाहूंगा कि केवल मुफ्त जमीन देने वाले गांव में सब-स्टेशन लगाने की प्रॉयोरिटी नहीं बनती है। सब-स्टेशन के लिए वहां की प्रायोरिटी उसकी जरूरत के मुताबिक तय करते हैं और जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर ही प्रॉयोरिटी दी जाएगी।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मार्च, 2005 को जिला महेन्द्रगढ़ खासतौर पर अटेली के चार पांच सब-स्टेशन्ज़ के बारे में इन्होंने आश्वासन दिया था। क्या वहां पर किसी सब-स्टेशन का काम शुरू किया गया है ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में विभाग से विवरण लेकर विधायक जी को भेज दिया जाएगा ।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 3.6 तक पब्लिक हैल्थ के सभी कनैक्शन जोड़ दिए जाएंगे।

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह पिछला प्रश्न है।

Mr. Speaker : Radhey Shyam Ji, this question is not pertaining to public health. You were absent when your question was called. अगर आपका कोई सवाल है then you can ask a supplementary.

Encroachment on Panchayats Land

***345. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any Panchayat land in district Gurgaon has been encroached upon or in illegal possession of private Colonizers/Builders and Private persons; and

(b) if so, the detail of such Panchayat lands alongwith the names of encroachers and action taken or proposed to be taken to evict the aforesaid lands from them ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir.

(b) The information is laid on the table of the House.

Information

The details of encroachment on Panchayats land by colonizers and builders are as follows :—

Sr. No.	Name of Village	Area	Type of Land	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Nathupur	3 Acre 4 Kanal	Nala	A colony has been set up in the name of Garden Estate in Hadbast of village Nathupur, Block Gurgaon and the Gram Panchayat land is divided into two parts by Gair Mumkin Nala in between. Illegal possession has been made by Garden Estate by way of

1	2	3	4	5
				construction of Pulia and Park etc. on this Nala. To remove this illegal possession, Gram Panchayat issued notice under section 24 of the Panchayati Raj Act. Garden Estate got stay order against the gram Panchayat by filing a civil suit in Civil Court. Gram Panchayat has filed RSA/writ in the Hon'ble High Court against the said order which is fixed for hearing on the 12-7-2006.
2.	Nathupur	about 5 Acres	Nala & Rasta	The Gram Panchayat Nathupur has passed resolution No. 1 dated 19-6-85 to enter into agreement that the DLF Company can construct the culvert, drain, sewer line, water line and roads on the land of Panchayat. Against the said agreement a complaint was filed by Udmi Ram etc. under section 10A in the Court of Assistant Collector 1st grade who set aside this agreement after finding it detrimental to the interest of the Panchayat. The case was remanded to Assistant Collector, 1st Grade by the order of Collector dated 26-9-89. The application under Section 10A was dismissed on 22-5-92. On appeal the Collector vide order dated 20-7-92 remanded the case to D.R.O. Meanwhile DLF Company filed CWP No. 674 of 1993 in the Hon'ble High Court against the order of Collector dated 20-7-92 and written statement has been filed and the CWP has been admitted on 16-11-2004.
3.	Gawal Pahari	632 Acres	Gair Mumkin Pahar	Revision/appeal filed on 3-2-2006 in the Hon'ble High Court has been admitted and next date of hearing has not been given.

(Sh. Randeep Singh Surjewala)

1	2	3	4	5
4.	Bandhwari	about 1200 Acres	Gair Mumkin Pahar & Nala	Stay order has been granted by the Divisional Commissioner, Gurgaon on 6-2-06 and next date of hearing is on 24-3-2006.

Note : The following thoroughfare of the Gram Panchayats have been paved by various companies and are being used by the villagers and companies, regarding which legal action has been ordered by the Deputy Commissioner, Gurgaon.

1.	Sarai Alavardi	4 Bigha 3 Biswa	Rasta Kabristan	These roads have been paved by the Ansal company and in use by the general public and the company.
2.	Kanhai	26 Kanal 2 Marla	Gair Mumkin Rasta	-do-
3.	Karterpuri	-	Rasta	-do-
4.	Silokhara	5 Acres	Gair Mumkin Rasta	These roads have been paved by the South City and in use by the general public and the company.
5.	Jhadsa	37 Bighas 14 Biswas	Rasta	-do-
6.	Tikri	2 Kanals	Rasta	These roads have been paved by the Malvi Town and in use by the general public and the company.
7.	Ghata	-	Rasta	These roads have been paved by the colonizers and in use by the general public and the company.
8.	Samaspur	5Acres	Rasta	These roads have been paved by the Masfield and in use by the general public and the company.
9	Tigra	2 Acres	Rasta	These roads have been paved by the Ansal/Unitech companies and in use by the general public and the company.
10.	Baigampur Khatola	1 Acre	Rasta Jaat	These roads have been paved by the Automake company and in use by the general public and the company.
11.	Mohammad Heri	1 Acre	Rasta Jaat	These roads have been paved by the Palam Vihar/Ansal and in use by the general public and the company.

The details of cases of encroachments by private persons are as follows : —

Sr. No.	Name of Court	Title of Case	Institution of case	Area	Next Date
1	2	3	4	5	6
1.	Assistant Collector, 1st Grade, Gurgaon/ Sub-Divisional Officer (Civil)	Gram Panchayat Jatola versus Satpal	13-9-04	0-1	30-3-06 Evidence
2.	-do-	Ram Kanwar versus Matadin, Gram Panchayat Fazilwas	6-4-04	0-4	27-3-06 Evidence
3.	-do-	Satpal versus Jaipal, Gram Panchayat Kukdola	13-8-01	Rasta Aam	8-5-06 Evidence
4.	-do-	Gram Panchayat Kukdola versus Dara Singh	5-6-03	Rasta	30-3-06 Evidence
5.	-do-	Gram Panchayat Kukdola versus Suresh	5-6-03	Rasta	17-4-06 Evidence
6.	-do-	Gram Panchayat Kukdola versus Bijender	5-6-03	Rasta	17-4-06 Evidence
7.	-do-	Gram Panchayat Kukdola versus Balraj	5-6-03	Rasta	17-4-06 Evidence
8.	-do-	Gram Panchayat Kukdola versus Rishipal	5-6-03	Rasta	17-4-06 Evidence
9.	-do-	Gram Panchayat Abhaypur versus Ramu	3-1-02	1-3	30-3-06 Evidence
10.	-do-	Gram Panchayat Jatshahpur versus Surajbhan	22-10-02	0-7	4-4-06 Evidence
11.	-do-	Gram Panchayat Jatshahpur versus Hoshiar	22-10-02	4-7	4-4-06 Evidence
12.	-do-	Gram Panchayat Jatshahpur versus Ratan	22-10-02	3-14	4-4-06 Evidence
13.	-do-	Dhanpati versus Gram Panchayat Bhagrola	21-8-03	100 Sq. yard	20-3-06 Evidence
14.	-do-	Surender versus Dharam Singh Gram Panchayat Balewa	3-7-01	0-7	21-3-06 for argument
15.	-do-	Surender versus Ram Kanwar, Gram Panchayat Daboda	15-7-03	1-1	27-3-06 for argument
16.	-do-	Om Parkash versus Dhir Singh, Gram Panchayat Samplka	26-3-02	Shamlat Chowk	30-3-06 for argument

(Sh. Randeep Singh Surjewala)

1	2	3	4	5	6
17.	-do-	Ratanpal versus Gram Panchayat Islampur	22-10-01		27-3-06 Evidence
18.	-do-	Mange versus Shiv Narayan, Gram Panchayat Khedla	8-1-01	22-12	17-4-06 Evidence
19.	-do-	Gram Panchayat Dhanawas versus Raj Kumar	12-6-03	0-3	27-3-06 Evidence for petitioners
20.	-do-	Gram Panchayat Sherpur versus Ram Kanwar	25-9-01	Map	28-3-06 Evidence for Panchayat
21.	-do-	Begraj versus Matadin, Gram Panchayat Bhagrola	22-7-04	0-5	20-4-06 Evidence for Panchayat
22.	-do-	Lal Chand versus Ram Avtar, Gram Panchayat Mushedpur	25-2-02	Intkal No. 1022	20-3-06 Report awaited
23.	-do-	Sh. Parkash versus Budh Ram, Gram Panchayat Daulatabad	7-3-03	0-10	28-3-06 to be filed written statement
24.	-do-	Gram Panchayat Nathupur versus Shyam Kak	10-12-01	Map	3-4-06 for argument
25.	-do-	Jai Singh versus Hazari, Gram Panchayat Bastpur	25-3-04	8 feet Rasta	10-4-06 for argument
26.	-do-	Gram Panchayat Siwari versus Umed	8-6-99	2-16	3-4-06 for argument
27.	-do-	Gram Panchayat Sultanpur versus Nainpal	19-6-01	Rasta No. 74	28-3-06 Evidence
28.	-do-	Rajender versus Dayaram, Gram Panchayat Badha	15-12-04	2x33	28-3-06 written statement
29.	-do-	Zile Singh versus Kalu Ram, Gram Panchayat Badha	16-12-04	Gair Mumkin Rasta	3-4-06 written statement
30.	-do-	Ram Chander versus Zile Singh, Gram Panchayat Baspadamka	25-10-01	0-4	8-5-06 written statement
31.	-do-	Dewki Nandan versus Gram Panchayat Mohmadheri	19-3-02	1-19	28-3-06 written statement

1	2	3	4	5	6
32.	-do-	Gram Panchayat Dualatabad versus Parkash etc.	30-6-05	0-10	30-3-06 written statement
33.	-do-	Sawant Singh versus Agnaram, Gram Panchayat Gudana	12-8-04	26-10	3-4-06 for argument
34.	-do-	Sheonath versus Badlu Ram, Gram Panchayat Kherki Daula	22-1-02	0-16	13-4-06 evidence petitioner
35.	-do-	Gram Panchayat Hazipur versus Duli Chander	14-6-91	1-3	24-4-06 written statement
36.	-do-	Suraj Bhan versus Sheo Ram, Gram Panchayat Kasan	29-11-01	Rasta Aam	4-4-06 argument
37.	-do-	Narpat versus Dharam Singh Gram Panchayat Uncha Majra	1-4-03	11x5 Rasta	25-4-06 for argument
38.	-do-	Narpat versus Chandgi, Gram Panchayat Uncha Majra	16-1-03	11 feet	24-4-06 for argument
39.	-do-	Shankar Bhagwan versus Mam Chand, Gram Panchayat Mandawar	22-12-98	7275-3	21-3-06 for argument
40.	-do-	Chiranji versus Gram Panchayat Narhera	25-9-03	10x10 Chabutra	3-4-06 written statement
41.	-do-	Mahender versus Ram Kawa Gram Panchayat Birhera	17-5-01	2-1	3-4-06 Evidence
42.	-do-	Gram Panchayat Bilaspur versus Pehlad	13-2-04	2-16	24-4-06 written statement
43.	-do-	Gram Panchayat Bilaspur versus Mahender	13-2-04	2-16	24-4-06 written statement
44.	-do-	Ran Singh versus Sheo Dutt, Gram Panchayat Paldi	4-10-01	14-17	24-4-06 written statement
45.	-do-	Gram Panchayat Kanhai versus Hari Singh	22-8-03	Gair Mumkin Rasta	27-3-06 Evidence Panchayat
46.	-do-	Gram Panchayat Kanhai versus Ram Mehar	22-8-03	Gair Mumkin Rasta	27-3-06 Evidence Panchayat
47.	-do-	Gram Panchayat Kanhai versus Rishi Pal	22-8-03	-do-	27-3-06 Evidence Panchayat

(Sh. Randeep Singh Surjewala)

1	2	3	4	5	6
48.	-do-	Gram Panchayat Kanhai versus Jai Pal	22-8-03	Gair Mumkin Rasta	27-3-06 Evidence Panchayats
49.	-do-	Gram Panchayat Kanhai versus Kishan	22-8-03	-do-	27-3-06 Evidence Panchayats
50.	-do-	Gram Panchayat Kanhai versus Zile Singh	22-8-03	-do-	27-3-06 Evidence Panchayats
51.	-do-	Gram Panchayat Dhorka versus Om Parkash	25-10-04	18 Sq. Yard	8-5-06 Evidence
52.	-do-	Gram Panchayat Dhorka versus Narender	25-10-94	0-4	8-5-06 Evidence
53.	-do-	Gram Panchayat Dhorka versus Parkash etc.	25-10-04	0-1	8-5-06 Evidence
54.	-do-	Gram Panchayat Dhorka versus Rameshwar	25-10-04	0-18	8-5-06 Evidence
55.	-do-	Gram Panchayat Dhorka versus Bhup Singh	25-10-04	0-2	8-5-06 Evidence
56.	-do-	Gram Panchayat Dhorka versus Om Parkash	25-10-04	0-7	8-5-06 Evidence
57.	-do-	Gram Panchayat Dhorka versus Phulwati	25-10-04	0-6	8-5-06 Evidence
58.	-do-	Gram Panchayat Dhorka versus Randhir	25-10-04	0-5	8-5-06 Evidence
59.	-do-	Gram Panchayat Dhorka versus Ram Kishan	25-10-04	0-6	8-5-06 Evidence
60.	-do-	Gram Panchayat Dhorka versus Ved Parkash	25-10-04	24 Sq. yard	8-5-06 Evidence
61.	-do-	Nanak versus Ramesh Gram Panchayat Hassanpur	5-7-04	5-7	3-4-06 Evidence
62.	-do-	Gram Panchayat Sikandarpur Dhoshi versus Attar Singh	19-1-04	10-2	13-4-06 Argument
63.	-do-	Gram Panchayat Sikandarpur Dhoshi versus Ram Kanwar	19-1-04	10-2	13-4-06 Argument
64.	-do-	Gram Panchayat Sikandarpur Dhoshi versus Mahipal	19-1-04	10-2	13-4-06 Argument
65.	-do-	Gram Panchayat Sikandarpur Dhoshi versus Ramesh	19-1-04	10-2	13-4-06 Argument
66.	-do-	Uday Singh versus Lakhmi, Gram Panchayat Kasan	2-6-03	Rasta Aam	25-4-06 written statement
67.	-do-	Partap versus Shobha Chand Gram Panchayat Duma	2-2-04	40x27	25-4-06 written statement

1	2	3	4	5	6
68.	-do-	Hazari versus Mahavir, Gram Panchayat Tatarpur	23-4-02	90 sq. yard	17-4-06 Evidence Panchayat
69.	-do-	Narender versus Gram Panchayat Kanhai	2-6-03	To cancel the plot	27-4-06 Evidence Panchayat
70.	-do-	Ramphal versus Om Parkash Gram Panchayat Patlihoji	20-2-03	Illegal possession on path	13-4-06 Evidence Panchayat
71.	-do-	Uday Singh versus Magtu, Gram Panchayat Kasan	22-9-04	-do-	3-4-06 Evidence Panchayat
72.	-do-	Ram Phal versus Jagan Gram Panchayat Mokalwas	15-10-01	0-16	30-3-06 Evidence Panchayat
73.	-do-	Gram Panchayat Rampur versus Lakhi Ram	7-10-03	11-0	21-3-06 Evidence Panchayat
74.	-do-	Dharmbir versus Mangal, Gram Panchayat Mau	12-10-04	20-3	21-3-06 Evidence Panchayat
75.	-do-	Nand Kishore versus Gram Panchayat Chandha Dungarwas	23-4-02	Rasta Aam	20-3-06 Evidence Panchayat
76.	-do-	Mahender versus Nand Kishore Gram Panchayat Chandla Dungarwas	2-6-03	On Rasta No. 23	20-3-06 Evidence Panchayat
77.	-do-	Gram Panchayat Sukhrali versus Chunni	30-9-02	Section 45 & 7 of PP Act,	27-4-06 Evidence Panchayat
78.	-do-	Moti versus Desraj, Gram Panchayat Bhangrola	13-8-01	69-11	28-3-06 Evidence Panchayat
79.	-do-	Harpal versus Gabar, Gram Panchayat Kasan	17-8-04	Rasta	27-4-06 Evidence Panchayat
80.	-do-	Mangat versus Bijender Gram Panchayat Aklimpur	14-2-02	6x6 Sq. yard	2-5-06 Evidence Panchayat
81.	-do-	Harparsad versus Chailu, Gram Panchayat Kasan	10-9-02	On Plot	21-3-06 Evidence Panchayat
82.	-do-	Gram Panchayat Pahari versus Parishat	1-12-04	67-17	30-3-06 written statement

(Sh. Randeep Singh Surjewala)

1	2	3	4	5	6
83.	-do-	Gram Panchayat Sampka versus Jai Lal	18-7-04	Plot No. 14/1/10	30-3-06 Argument
84.	-do-	Mansa versus Gram Panchayat Alipur	26-4-05	8 sq. feet	4-4-06 written statement
85.	-do-	Jagan versus Gram Panchayat Basunda	2-6-03	17-1	27-4-06 written statement
86.	-do-	Gram Panchayat Nanukala versus Rajpal	12-3-01	0-5	11-5-06 written statement
87.	-do-	Mamdin versus Gram Panchayat Rahka	26-8-04	Section 10A	28-3-06 Argument
88.	-do-	Gram Panchayat Sarhol versus Pawan Kumar	8-8-03	1-13	30-3-06 Evidence
89.	-do-	Gram Panchayat Tatarpur versus Mamraj	15-7-03	4-3	4-4-06 Evidence
90.	-do-	Nar Singh versus Surjan Gram Panchayat Kasan	19-10-04	Ahata No. 186	21-3-06 Evidence
91.	-do-	Anand Parkash versus Gram Panchayat Dhorka	22-2-01	Section 77 (d) (3)	17-4-06 Evidence
92.	-do-	Rang Rao versus Dharm Singh Gram Panchayat Sikanderpur Badha	12-8-03	Gair mumkin Rasta	27-3-06 Evidence
93.	-do-	Gram Panchayat Natupur versus Mahesh	29-4-04	1-10	27-4-06 Evidence
94.	-do-	Gram Panchayat Natupur versus Balwanta	1-6-2000	1-10	27-4-06 Evidence
95.	-do-	Naresh versus Zile, Gram Panchayat Kadipur	26-5-05	0-13	13-4-06 Evidence
96.	-do-	Yagender versus Ishwari Gram Panchayat Kadipur	26-5-05	Gair mumkin Johar	13-4-06 written statement
97.	-do-	Gram Panchayat Turkapur versus Naresh	27-8-03	2-12	4-4-06 Argument
98.	-do-	Gram Panchayat Gairatpurbas versus Delhi Tower	7-11-05	about 100 Acre	10-4-06 written statement
99.	-do-	Gram Panchayat Nathupur versus Ramkaka	22-2-01	3-10	3-4-06 Evidence

In the Court of Assistant Collector, 1st Grade, Gurgaon, D.R.O.

1	2	3	4	5	6
1.	D.R.O.	Gram Panchayat Nimoh versus Jiwan	12-6-01	7-3	4-4-06 PWS
2.	-do-	Gram Panchayat Hazipur versus, Sube.	12-11-01	4-1	12-4-06 PWS
3.	-do-	Karan Singh versus Hari Ram, Gram Panchayat Abhaypur	11-6-01	Gair mumkin Johar	10-4-06 PWS
4.	-do-	Ram Kishan versus BDPO, Gram Panchayat Naharpur Kasan	27-11-05	Revision Remanded Plots	20-3-06 PWS
5.	-do-	Gram Panchayat Birhera versus Chandgi	7-8-2000	3-11	10-4-06 DWS
6.	-do-	Gram Panchayat Gakarpur versus Shyo Narayan	24-9-2001	1-10	20-3-06 DWS
7.	-do-	Gram Panchayat Alipur versus Shiri Lal	11-6-2001	Gair mumkin Pahar	10-4-06 PWS
8.	-do-	Gram Panchayat Schrawan versus Ram Phal	1-10-99	Abadi Deh	28-3-06 PWD
9.	-do-	Gram Panchayat Sarmathla versus Jai Pal	14-6-01	Abadi Deh	30-3-06 PWD
10.	-do-	Gram Panchayat Gwalpahari versus Vinod Kumar	4-7-01	139-1	3-4-06 DWS
11.	-do-	Gram Panchayat Hazipur versus Duli Chand	14-6-01	1-3	12-4-06 PWS
12.	-do-	Charan Singh versus Gram Panchayat Lakhuwas	24-4-01	22-0	12-4-06 PWS
13.	-do-	Tej Ram versus Gram Panchayat Turakpur	21-5-01	18-5	14-3-06 PWS
14.	-do-	Gram Panchayat Nakhroda versus Hira Lal	4-9-01	29-14	12-4-06 PWS
15.	-do-	Gram Panchayat Hazipur versus Rati Ram	4-6-01	0-7	12-4-06 DWS
16.	-do-	Gram Panchayat Bilhaka versus Samey Singh	13-9-02	31-6	28-3-06 PWS
17.	-do-	Pat Ram versus Gabdu, Gram Panchayat Baspudmka	9-12-02	11 feet Rasta	28-3-06 DWS
18.	-do-	Gram Panchayat Kherla versus Babu	17-8-2000	7-1	28-3-06 DWS
19.	-do-	Ratan Singh versus Dharmo Gram Panchayat Behrampur	16-9-04	Rasta Chinai	12-4-06 PWS
20.	-do-	Gram Panchayat Narsinghpur versus Ratti Ram	12-6-01	5-3	10-4-06 PWS

(Sh. Randeep Singh Surjewala)

1	2	3	4	5	6
21.	D.R.O.	Om Pal versus Mahender, Gram Panchayat, Ghamroz	31-3-05	Rasta	5-4-06 PWS
22.	-do-	Babu Singh versus Ramji Lal, Gram Panchayat, Ghamroj	5-4-05	Rasta	4-4-06 DWS
23.	-do-	Vikram versus Babu, Gram Panchayat Ghamroj	5-4-05	Rasta	4-4-06 DWS
24.	-do-	Gram Panchayat Ghoshgarh versus Om Parkash	17-5-95	74-2	17-3-06 PWS
25.	-do-	Gram Panchayat Langra versus Bhagmal etc.	1-12-04	2-16	4-4-06 DWS
26.	-do-	Gram Panchayat Gudhana versus Chiraji	24-3-03	10 Sq. yard	17-3-06 PWS
27.	-do-	Gram Panchayat Gudhana versus Suraj Bhan	24-3-03	33 Sq. yard	17-3-06 PWS
28.	-do-	Gram Panchayat Gudhana versus Dharam Singh	24-3-03	29 Sq. yard	17-3-06 PWS
29.	-do-	Madan versus Gram Panchayat Gwalpahari	29-9-04	20-16	4-4-06 PWS
30.	-do-	Ho Ram versus Gram Panchayat Gwalpahari	29-9-04	15-17	4-4-06 PWS
31.	-do-	Gram Panchayat Mubarikpur versus Chander	11-9-02	24-14	30-3-06 DWS
32.	D.D.P.O.	Gram Panchayat Dinokhari versus Panna Lal	11-9-02	-	4-4-06 Dakhal warrant intezar
33.	-do-	Bhartu versus Gram Panchayat Narsinghpur	24-5-01	8 Kanal	30-3-06 PWS
34.	-do-	Sham Singh versus M/s Pondri Industry etc. Gram Panchayat Jharsa.	24-5-01	21-13	20-3-06 DWS
35.	-do-	Gram Panchayat Patli Hazipur versus Ram Kumar	13-9-2000	-	12-4-06 DWS
36.	-do-	Gram Panchayat Fazipur Badli versus Sawal Singh	8-7-96	45Sq.karam	30-3-06 DWS
37.	-do-	Shiv Singh versus Gram Panchayat Dola	17-4-97	Rasta saream	30-3-06 PWS
38.	-do-	Ved Pal versus Gram Panchayat Dola	4-10-01	24 Kanal	30-3-06 PWS
39.	-do-	Ajay Pal versus Gram Panchayat Dola	16-4-01	24 Kanal	30-3-06 PWS
40.	-do-	Gram Panchayat Unchamajra versus Bishamber Dayal	28-5-03	6 Marla	17-3-06 PWS

1	2	3	4	5	6
41.	D.D.P.O.	Jai Ram versus Mohan Lal, Gram Panchayat Narsinghpur	28-5-03	Rasta Saream	4-4-06 DWS
42.	-do-	Pahlad versus Rameshwar, Gram Panchayat Johri Khurd	27-1-05	Rasta Saream	17-3-06 PWS
43.	-do-	Pehlad versus Raghubir	27-1-05	Rasta Saream	17-3-06 PWS
44.	-do-	Pehlad versus Mahabir	27-1-05	Rasta Saream	17-3-06 PWS

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सूचना इन्होंने सदन के पटल पर मेरे सवाल के जवाब में रखी है और जिस तरह से इन्होंने बताया है कि गुड़गांव जिले में जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्ज़ बहुत बड़ी-बड़ी मिल्ज़,कामर्शियल बिल्डिंग्ज़ बड़े-बड़े पैसों वालों ने बनाई हैं। उन्होंने जानबूझ कर गवाल पहाड़ जैसी पंचायतों की कीमती जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, सड़कों पर कब्जा किया हुआ है और यह सब गैर कानूनी तरीके से हुआ है। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी उन अधिकारियों और बिल्डर्ज के खिलाफ जिनकी मिली भगत से बिना पैसे दिए पंचायतों की ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, क्या उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्यवाही करवाएंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जिन दो केसिज़ की चर्चा की है वे दोनों मामले सब-ज्यूडिश हैं। पहले वाले मामले में हाईकोर्ट में 12 जुलाई की डेट लगी हुई है। दूसरा मामला सिविल रिट पैटिशन के तहत हाईकोर्ट में पैण्डिंग है। इसके अलावा स्टार्ड प्रश्न में तीसरा और चौथा मामला है उसमें से तीसरा केस हाईकोर्ट में है और चौथा केस गुड़गांव में डिविजनल कमिशनर के पास सब-ज्यूडिश प्रोसीडिंग में रटे दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि जैसे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज का फैसला होगा उसके अनुसार हम उन व्यक्तियों को नहीं बख्शेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने सड़कों की बात की है तो इस बारे में मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वे रास्ते पंचायतों के कब्जे से बाहर नहीं गए हैं वहां पर जो कोई भी कच्चे रास्ते थे, प्राईवेट कम्पनियों ने उनको पक्का कर दिया है। आज उन रास्तों को पंचायतें और वे कम्पनियां दोनों ही प्रयोग कर रही हैं। हां यह बात सही है कि उन कम्पनियों ने उन सड़कों को बिना इजाज़त के पक्का किया है और उन्होंने ऐसा क्यों किया है इस बारे में डी०सी० ने उन कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही चालू कर दी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि मुकद्दमें हाईकोर्ट और विभिन्न अदालतों में पैण्डिंग है और उन पर जो निर्णय आएगा उस बारे में मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि वे इस बारे में भी जांच करें कि क्या उन अधिकारियों के मिलीभगत से उन अदालतों में कोई जवाब दायर हुआ है या नहीं। जैसे आप जानते हैं कि पिछले सालों में एक षडयंत्र के तहत इस तरह की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने का अभियान चलाया गया था। क्या कोई मिलीभगत के जबावदावें कोर्ट में दायर हुए हैं और क्या उनकी भी जांच करवाएंगे ?

डा0 सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, चूंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का नाम वोल्कर रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है इसलिए हमारा इनके खिलाफ प्रोटैस्ट है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, आप बैठिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, ये फिर उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। (विघ्न) मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसमें जो भी मामले हाई कोर्ट के अंदर पैंडिंग हैं उनके बारे में अगर माननीय सदस्य कोई बात बताएंगे तो हम उन पर विचार अवश्य करेंगे। अगर यह लिखकर देंगे तो जो वकीलों की टीम है उनको हम निर्देश देंगे कि अमुख मामलों के अंदर गडबड़ी है इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम इसकी भी जांच करवाएंगे। (विघ्न) स्पीकर सर, डा० साहब को चिन्ता यह हो रही है कि कहीं इनके समय के मुकद्दमें न खुल जाएं लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि इनको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि पूरी जांच के बाद ही इनको सजा दी जाएगी। (विघ्न) स्पीकर सर, दूसरे माननीय सदस्य ने यह पूछा कि जो भी इस प्रकार के मामले डिवीजनल कमिश्नर या दूसरे अधिकारियों के पास विचाराधीन हैं उनका क्या करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनका फैसला हो जाए।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, *****

श्री अध्यक्ष : अब डा० सुशील इंदौरा की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर,*****

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, जब मंत्री जी जवाब दे रहे थे उस समय आप तो लौबी में गए हुए थे। आप बैठिए।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, *****

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, ये तो इंस्ट्रक्शंज लेने के लिए गए हुए थे कि आज कान पकड़ने हैं या नहीं पकड़ने हैं। इनको टेलीफोन आ गया है कि कान पकड़ने हैं इसलिए ये अब वापस आये हैं। डा० साहब, जब आपका विरोध उसी प्रकार का है तो आप हाथ क्यों दिखा रहे हैं आप अपने कान क्यों नहीं पकड़ रहे हैं।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, *****

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, आप बैठिए। Sukhbir Singh Jaunapuria Ji, please ask your supplementary.

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : स्पीकर सर, अभी दलाल साहब ने क्वैश्चन किया था और मंत्री जी ने उसका जवाब दिया था तो मैं भी उसी के बारे में बताना चाहता हूं।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, *****

Mr. Speaker : Indora ji, please understand the seriousness of the question hour. Please take your seat. Jaunapuria Ji, please ask your supplementary.

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : स्पीकर सर, जहां तक कम्पनियों के रास्ते की बात है उस रास्ते को सिर्फ नीचे सिवरेज और ड्रिनेज पाईप के लिए यूज किया है उसकी आनरशिप तो पंचायत के पास है और उसके बदले में हर गांव में कम्पनियों ने एक-एक, दो-दो करोड़ या पचास पचास हजार रूपयों के काम करवाए हैं, सारे रास्ते ड्रेनेज और पाईप को निकालने के लिए यूज किए गए

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

हैं और सबके लिए पक्के बना दिये गये हैं । गांव का आम आदमी भी वहां से निकलेगा। इस तरह से इनका यह यूज होगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जो माननीय सदस्य ने बताया है उसको मैंने पहले ही बता दिया है। जो भी इस प्रकार के रास्ते हैं वह पक्के कर दिये गये हैं लेकिन अभी वह सम्पत्ति पंचायत के पास ही है। (विघ्न) स्पीकर सर, डा० साहब को पूरे हरियाणा से माफी मांगनी चाहिए। ये लोग कान पकड़ने से छूटने वाले नहीं हैं।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, *****

Mr. Speaker : Dr. Sahib, please take your seat. Don't waste the time of the House. You should maintain the decency and decoram of the House. You are senior most member of the House.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हालत तो मैंने बताये ही हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ भ्रष्टाचार के केसिज की इंक्वायरी सी०बी०आई० कर रही है। जब ओम प्रकाश चौटाला हाउस में आये तो ये उनका बायकाट कर लें।

डा० सीताराम : अध्यक्ष महोदय, इनको मंत्री जी के खिलाफ भी इंक्वायरी करवानी चाहिए।

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, जो एनक्रोचमेंट प्राईवेट आदमियों ने की है यह मुकम्मल नहीं है। सिकन्दरपुर में पंचायत की जमीन के अन्दर एक मार्किट बनी हुई है वह इन्फलुन्शियल आदमियों ने बना रखी है। नाथूपुर में प्रापर्टी डीलर का एक बहुत बड़ा दफ्तर है जिसका वे किराया खा रहे हैं। अगर मंत्री जी इसके बारे में और जानकारी चाहे तो मैं वह भी दे सकता हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर दे देंगें तो हम अवश्य ही उन लोगों के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करवायेंगे और उनसे कब्जा भी छुड़वायेंगे।

Misappropration of Red Cross Fund

***397. Shri Naresh Yadav :** Will the Minister for Revenue be please to State :—

(a) whether the Government is aware of the fact that the funds of the Red Cross Society is being misappropriated on large scale in disctrict Mahendergarh;

(b) if so, whether Government intends to conduct any enquiry in this regard and to take strict action against the officials found responsible in the said matter; and

(c) the details of the total amount received from various sources to the Red Cross Society of the aforesaid district during the last one year togetherwith the manner in which the said amount has been spent?

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

स्वास्थ्य मन्त्री (बहन करतार देवी) :

(क) जी नहीं, श्रीमान ;

(ख) जी नहीं, श्रीमान;

(ग) वर्ष 2005-06 (1-4-2005 से 10-3-2006 तक) प्राप्त राशि तथा व्यय सम्बन्धी विवरण अनुबन्ध " क" पर संलग्न है।

अनुबन्ध-" क"

जिला रैडक्रास सोसायटी, महेन्द्रगढ़ को गत एक वर्ष के दौरान प्राप्त राशि तथा उसे खर्च करने के तरीके सम्बन्धी विवरण।

क्र० सं०	पिछले एक वर्ष में आय के स्रोत	राशि (रुपयों में)
1.	1-4-2005 को उपलब्ध राशि	21,24,509.69
2.	सदस्यता शुल्क से आय	1,35,330.00
3.	विभिन्न परियोजनाओं जैसे हैरिस, फार्म स्टाल, एक्स-रे लैब, मैडिकल स्टोर व एम्बुलैंस आदि।	34,18,880.00
4.	डिस्क, हरसिस, वाहन सारथी से आय	21,83,150.00
5.	जन साधारण से प्राप्त चन्दा व दान राशि	12,42,151.00
6.	दुकान/स्टाल के किराये/पट्टा, बैंक ब्याज व ऋण की वसूली आदि	3,88,966.00
7.	विकलांगों को नि:शुल्क वितरित कृत्रिम अंगों की प्रतिपूर्ति राशि	39,920.00
	आय का कुल योग :	**95,32,906.69**

पिछले एक वर्ष में हुये खर्चे का विवरण

1.	कार्यालय खर्च: (ए) स्टाफ का वेतन	22,71,855.00
	(बी0) रोगी सेवा वाहन का रख-रखाव, पी०ओ०एल० खर्च, जिसमें एक नए रोगी सेवा वाहन तथा कार्यालय जीप की खरीद का खर्च शामिल है तथा पोस्टेज, लेखन सामग्री, टेलीफोन, पीने का पानी, बिजली व अन्य फुटकर खर्चे।	15,18,720.00
2.	निर्धन व बेसहरा लोगों को नकद व दवाईयां, कम्बल	9,02,238.00

	आदि के रूप में आर्थिक सहायता, कुशाग्र बुद्धि बच्चों को व निर्धन परिवार के बच्चों को आगे पढ़ाई के लिये वित्तीय सहायता तथा विधवा पुनर्वास के लिये सिलाई मशीनें व विकलांगों को कृत्रिम अंग आदि देना।	
3.	रक्त दान, विकलांग कैम्प, फल वितरण एस०एस०ए० कैम्प तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आदि।	5,25,378.00
4.	पुनर्वास केन्द्र, अन्ध विद्यालय, गुरूकुल, बाल कल्याण समिति आदि को अनुदान व ऋण।	7,12,218.00
5.	राज्य शाखा को रैडक्रास सदस्यता शुल्क, एफ०सी०आर० व जिला आई०टी० सोसायटी को हैरिस का अंशदान।	4,63,577.00
6.	विभिन्न केन्द्रों के लिये आवश्यक सामग्री की खरीद व लैंड रिकार्ड के लिये कम्प्यूटर की खरीद व ट्रायल बैलेंस (3,026/-) के साथ।	15,52,601.00
	खर्चे का कुल योग :	79,46,587.00
	10-3-2006 को रैडक्रास समिति के पास उपलब्ध राशि :	15,86,319.69

उपरोक्त दर्शाये व्यय का विवरण :

जिला रैडक्रास समिति, नारनौल समाज के दलित वर्ग को सहायता उपलब्ध करवाने के लिये समर्पित है। समिति द्वारा आर्थिक रूप में गरीब परिवारों के 432 व्यक्तियों को वित्तीय, चिकित्सीय एवं शैक्षणिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। समिति द्वारा ऐसे गरीब परिवारों के कुशाग्र बच्चों को वित्तीय सहायता उपब्ध कराई जाती है, जो फीस का भार वहन करने में असमर्थ हैं। गत वर्ष के दौरान समिति द्वारा विधवाओं तथा निर्धन परिवारों को आजीविका अर्जित करने हेतु 35 सिलाई मशीनें वितरित की गई। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा निराश्रित तथा निर्धन व्यक्तियों को भीषण ठंड से बचाने के लिये 200 रजाईयां तथा कम्बल वितरित किये गये। समिति द्वारा विकलांग व्यक्तियों को उनके पुनर्वास हेतु 16 तिपहिया साईकिलें, 10 श्रवण यन्त्र तथा 340 कृत्रिम अंग मुफ्त वितरित किये गये। समिति द्वारा अपने भौतिक चिकित्सा विभाग में 1318 व्यक्तियों को भौतिक चिकित्सा सुविधायें भी प्रदान की गई। समिति द्वारा 9 सफल रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। गत वर्ष के दौरान, जिला रैडक्रास समिति नारनौल की आय रुपये 95,32,906.69 पैसे थी, जिसमें गत वर्ष की शेष राशि रुपये 21,24,509.69 पैसे शामिल है। वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याण गतिविधियों जैसे एम्बुलैंस सेवायें, कुशाग्र विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई आदि जारी रखने हेतु 79,46,587.00 रुपये की राशि खर्च की गई जिसमें उपरोक्त योजनाओं में नियुक्त अमले का वेतन भी शामिल है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी एश्वर्य मद पर कोई खर्चा नहीं किया गया।

यद्यपि, उपायुक्त, नारनौल द्वारा पूर्व पृष्ठ के अनुबन्ध " क" में दर्शाये आईटम संख्या-1(ए), 1(बी) तथा 2 के विरूद्ध दर्शाये गये खर्चे का ब्रेक-अप निम्न प्रकार से दिया है :--

(बहन करतार देवी)

आईटम संख्या 1(ए) अमले का वेतन 22,71,855/- रुपये की राशि का ब्रेक-अप

क्र० सं०	संख्या तथा पद का नाम	एक वर्ष के लिये वेतन पर कुल खर्चा (राशि रुपयों में)
1.	1 सचिव (नियमित)	2,,62,664/-
2.	1 लेखाकार (नियमित)	1,41,042/-
3.	1 लेखालिपिक (नियमित)	1,08,239/-
4.	5 लिपिक (नियमित)	4,65,696/-
5.	2 कम्प्यूटर प्रोग्रामर (नियमित)	1,78,739/-
6.	2 चालक (नियमित)	1,79,094/-
7.	1 फार्मासिस्ट (नियमित)	95,026/-
8.	6 सेवादार (नियमित)	4,24,412/-
9.	11 हरिस कर्मचारी कन्सोलिडेटिड वेतन पर	2,43,984/-
10.	4 कर्मचारी कन्सोलिडेटिड वेतन पर	83,929/-
11.	बर्खास्त कर्मचारियों का सैटेलमेंट वेतन	25,548/-
12.	सी०पी०एफ०	22,264/-
13.	टी०ए०/डी०ए०	41,218/-
		कुल योग 22,71,855/-

आईटम संख्या 1(बी) 15,18,720/- रुपये के खर्चे का ब्रेक-अप

क्र० सं०	व्यय का मद	राश (रुपयों में)
1.	नई एम्बुलैंस की खरीद	5,07,308/-
2.	नई कार्यालय जीप की खरीद	4,14,803/-
3.	पी०ओ०एल० तथा एम्बुलैंस का रख-रखाव	81,891/-
4.	पी०ओ०एल० तथा कार्यालय कार का रख-रखाव	1,41,704/-
5.	पी०ओ०एल० तथा पंजीकरण व बीमा खर्चे सहित कार्यालय जीप का रख-रखाव	31,462/-
6.	बकाया अदायगी तथा जनरेटर का रख-रखाव	27,093/-
7.	फर्नीचर आदि की खरीद	94,800/-
8.	आडिट फीस	8,600/-

9.	आडिट फीस, विज्ञापन, डाक, लेखन सामग्री तथा कानूनी मामलों जैसे विविध खर्चे	1,23,940/-
10.	टेलीफोन बिल	68,018/-
11.	पानी तथा विद्युत खर्चा	19,101/-
	कुल योग	**15,18,720/-**

आईटम संख्या 2: 9,02,238/- रुपये के खर्चे का ब्रेक-अप

1.	नि:शुल्क ईलाज हेतु चिकित्सीय सहायता (कुल 139 व्यक्ति)	2,77,654/-
2.	शिक्षा तथा खेल सामग्री हेतु सहायता (61 व्यक्ति)	2,02,722/-
3.	वित्तीय सहायता (232 व्यक्ति)	3,67,417/-
4.	विकलांगों को नि:शुल्क वितरण हेतु तिपहिया साईकिल तथा श्रवण यन्त्रों की खरीद (16+10=26 व्यक्ति)	54,445/-
	कुल योग	**9,02,238/-**

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय; जिला महेन्द्रगढ़ के उपायुक्त ने रेड क्रास के नाम पर पिछले 6-7 महीने से कभी शाम-ए-गजल, कभी चांद गाने के नाम पर तरह-तरह की पर्चियां छपवाकर लोगों से पैसे इक्ट्ठे किए हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Yadav, ask your specific supplementary.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, कभी कवि सम्मेलन के नाम पर और कभी रागनियों के नाम से नाजायज तरीके से पैसे का दुरूपयोग हो रहा है।

Mr. Speaker : Mr. Yadav, ask your specific supplementary.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय,करोड़ों रुपया इस प्रकार से महेन्द्रगढ़ जिले में इकट्ठा किया गया है लेकिन इसकी डिटेल माननीय मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में नहीं दी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो करोड़ों रुपया रेड क्रास के नाम से इकट्ठा किया गया है, क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ? इस तरह के इकट्ठे किए हुए पैसे की कुछ रसीदें मेरे पास है। दक्षिणी हरियाणा के कई माननीय सदस्य बैठे हैं उनको भी इस बारे में पता है । क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में कोई जांच करवायेंगे ? मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रेवाड़ी की एट होम कार्यक्रम में बताया था कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार उपायुक्त के माध्यम से महेन्द्रगढ़ जिले में हो रहा है। आज कोई भी व्यक्ति उपायुक्त के कार्यालय में पैट्रोल पम्प के लिए एन0ओ0सी0 लेने जाता है तो उससे डेढ लाख रुपये लिए जाते हैं। कोई लाईसैंस लेने जाता है तो ग्यारह हजार रुपये लिये जाते हैं कोई दूसरे कार्य के लिए जाता है तो कम से कम 200 रुपये तो लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस पैसे की डिटेल मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में नहीं दी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या जो करोड़ों रुपया इन रसीदों के माध्यम से इक्ट्ठा किया गया है इस बारे में कोई जांच करवायी जायेगी?

बहन करतार देवी : माननीय स्पीकर सर, वैसे तो रैड क्रास एक स्वायत्त संस्था है और इस संस्था पर सोशल वेल्फेयर डिपार्टमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन डिप्टी कमिशनर महेन्द्रगढ़ से जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से कुल 95,32,966.69 रुपये की रेड क्रास से आमदनी हुई है और 79,46,587 रुपये खर्च हुए हैं तथा 10-3-2006 तक 15,86,319.10 रुपये उनके पास बैलेंस हैं। जो डिटेल मैंने सदन में बताई है उसमें जो खर्चा किया गया है वह जायज खर्चा किया गया है उसमें कोई लग्जरी आईटम नहीं है। ये जो रागनी की बात कर रहे हैं इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम करवाये जाते हैं इन प्रोग्राम में कोई खर्चा नहीं होता बल्कि उनसे तो कुछ न कुछ आमदनी ही होती है। उसके बारे में पूरी डिटेल डिप्टी कमिशनर की तरफ से हमें प्राप्त हुई है और जो अभी डिटेल बाकी है वह वर्ष खत्म होने पर प्राप्त हो जायेगी। इसमें ऐसा होता है कि पहले तो पैसा खर्च किया जाता है लेकिन बाद में उस पैसे से आमदनी भी हो जाती है। इस पैसे में से ही गरीबों को ट्राई साईकिल दी जाती है, ब्लड बैंक के कैम्प लगाने के लिए, कवि सम्मेलन करवाने के लिए या महिला सम्मेलन आदि करवाने के लिए ही यह पैसा खर्चा किया गया है।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। जो कार्ड छापे गये थे वे मेरे पास हैं और लोगों की 200-200 रुपये की जो रसीदें काटी गई हैं वे भी मेरे पास हैं। किसी रसीद पर नम्बर है किसी पर नहीं है। ग्राम पंचायतों की भी 300-300 रुपये की पर्चीयां काटी गई हैं। वहां पर लोगों में इस बात को लेकर बुहत नाराजगी है।

श्री अध्यक्ष: यादव साहब, आप प्रश्न पूछिये।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे वहां डी0सी0 ने रैडक्रास के नाम पर करोड़ों रुपये इकट्ठे किए हैं। जब भी कोई मीटिंग हुई उसमें डी0सी0 ने किसी प्रकार का जन हित का कार्य नहीं किया बल्कि रैडक्रॉस के नाम पर पर्चीयां काटी गई। हमें इसका हिसाब चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यादव साहब, मंत्री महोदया ने अभी जवाब दिया तो है कि मार्च के अंत तक बैलैंस-शीट तैयार होने के बाद सारे आंकड़े डी0सी0 की तरफ से दे दिए जायेंगे।

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी के पास इस बारे में जो भी रसीदें वगैरा हैं वे हमें अलग से दे दें। मेरे साथी को अच्छी तरह मालूम है कि हमारी सरकार किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को नहीं छोड़ेगी। अगर वाकई में वहां गलत काम हुआ है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। मेरे साथी इस बारे में अलग से लिखकर हमें दे दें।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, ----(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यादव साहब, प्लीज अब, आप बैठें। आपके सवाल का जवाब आ गया है। (विघ्न)

डा0 सीताराम : अध्यक्ष महोदय, -----(विघ्न)

डा0 सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, इनको अपना पूरा सवाल तो पूछने दें।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप सीनियर मैंबर हैं। Please maintain the decorum of the House.

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने अपने जवाब में कहा है कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। ऐसा आश्वासन पहले किसी ने नहीं दिया। ये लिखकर दे दें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। (विघ्न)

Mr. Speaker: Indora ji, please understand the seriousness of the Questions Hour. No running commentary while sitting.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है यह बात सभी को मालूम है । हमने प्रदेश की जनता को स्वच्छ प्रशासन दिया है। आज तक कोई भी शिकायत विपक्ष की तरफ से लिखित में हमारे पास नहीं आई है। इनके नेता के खिलाफ सी0बी0आई0 की कार्यवाही हो रही है यह बात भी इनको मालूम है। अध्यक्ष महोदय, जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यही रिप्लाई हैल्थ मिनिस्टर ने दी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई देने के बाद भी ये इस तरह की बातें करें यह तो हमारी समझ से बाहर है।

डा0 सीताराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आश्वासन आ गया, ठीक है।

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, please sit down and maintain the decency of the House.

प्रो0 छत्तरपाल सिंह : इस प्रश्न पर हैल्थ मिनिस्टर महोदया रिप्लाई कर रही हैं इसलिए मैं हैल्थ मिनिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिला हिसार के अंदर बहुत बड़ा सिविल हास्पिटल है। उस हास्पिटल में पिछले एक-डेढ़ साल से अल्ट्रासाउंड मशीन आऊट ऑफ आर्डर है।

Mr. Speaker : Prof Sahib, it does not relate with this question. Please sit down.

Financial Position of Municipal Committees

***353. Major Narpender Singh Sangwan :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that the Municipal Committee Charkhi Dadri & other towns are not in this position to pay the salaries of their employees because their financial position is not good; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to give the share in the amount realized by the State Government from VAT to the Municipal Committees ?

शहरी विकास राज्य मन्त्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) :

(क) यह सत्य है नगरपालिका चरखी दादरी तथा कुछ अन्य नगरपालिकाएं अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन की अदायगी करने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं।

(ख) मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वैट) से वसूल की जा रही राशि का हिस्सा नगरपालिकाओं को दिये जाने का कोई विशेष प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है तथापि, राज्य सरकार कुल राजस्व से वसूल की गई राशि में से, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगरपालिकाओं को अनुदान देती है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कमेटियों के बकाया आज की तारीख में एक करोड़ 84 लाख रुपये है। यह ऐरियर सिर्फ पे कमीशन और महंगाई भत्ता, भविष्य निधि वगैरह-वगैरह का है। म्यूनिसिपिल कमेटीज में जो पैसा आता है उससे मुश्किल से कर्मचारियों का वेतन पूरा होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल कमेटीज की जो बकाया राशि है उसका इन्तजाम कब होगा? अगर हमारे पास रैगुलरली पैसा नहीं आता और हमारी प्रॉब्लम यह हो जाती है कि जितने भी कर्मचारी हैं वे अपने वेतन के लिए हाय-हाय करने लग जाते हैं और काम पूरा नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि म्यूनिसिपिल कमेटीज की बकाया राशि कब पूरी की जाएगी ?

वित्त मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हमने इस बजट में अभी अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो ऐलोकेशन की है अर्बन लोकल बॉडीज में अभी पिछले साल यह राशि 184 करोड़ थी और इस बार हमने इस राशि को बढ़ाकर 197 करोड़ से ज्यादा की ऐलोकेशन की है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें जो म्यूनिसिपिल कमेटीज की अपनी पैंशन और तनख्वाह देने में प्रॉब्लम थी। यह प्रॉब्लम खासतौर से उन सालों में आई जब बौटाला साहब का राज आया (विघ्न) डेढ़-डेढ़ साल से पैंशन की राशि जमा नहीं हुई थी उनकी कमेटीज की तरफ छः छः, आठ-आठ महीने या साल भर से तन्ख्वाह नहीं मिली थी हमने उन सभी म्यूनिसिपिल कमेटीज को लिखा था कि आज से 3-4 महीने से लेकर पहले जिसकी पैंशन और सैलरी में दिक्कत है या एक्युमुलेटिड कोई एमाउंट बनता है तो वह हमें इन्फोर्म करें। इसी मदद के अण्डर हमने 9 करोड़ रुपये रिलीज किया था जो केवल हमने उन म्यूनिसिपिल कमेटीज को दिया था जो यह चाहती थी कि हम अपनी तनख्वाहें अदा कर सकें। मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकता हूं कि हमारी गर्वनमैंट की यह पॉलिसी है कि किसी भी म्यूनिसिपिल कमेटी के इम्पलोई का चाहे रिटायर्ड हो चाहे सर्विंग, उनको सैलरी तथा पैंशन के भुगतान में कभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे।

Memorial in the name of Freedom Fighter

***435. Shri Dharampal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to establish any memorial in the name of freedom fighter in the State ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir.The construction work of the State level Freedom Fighter Memorial at Rohtak has been completed.

इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे (विघ्न एवं शोर)

चौ0 धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर सर, किसी चीज की हद होती है, किसी बात की कोई सीमा होती है। (विघ्न एवं शोर) किसी नेता को राजी करने की कोई हद होती है। इन लोगों ने उनको राजी कर लिया है (विघ्न एवं शोर) इनका इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है। (विघ्न एवं शोर) इनके इसी व्यवहार पर मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं सप्लीमैंटरी बाद में पूछूंगा। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, मेरा शेर सुन लीजिए उसके बाद मैं अपनी सप्लीमैंटरी पूछूंगा। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे यह रिक्वैस्ट करता हूं कि ये अपनी अपनी सीटों पर बैठें। यह क्वैश्चन ऑवर है (विघ्न एवं शोर) क्वैश्चन आवर में इतना इन्ट्रप्शन नहीं होता है क्योंकि क्वैश्चन ऑवर एक फिक्स टाईम के लिए होता है। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इनसे कहिए कि ये लोग बैठ जाएं। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, यह जीरो आवर नहीं है इन्हें अपना मुद्दा जीरो आवर में उठाना चाहिए और उस वक्त शोर करें but not in question hour. This is not proper time (Interruptions) अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब सीनियर मैम्बर हैं इनको क्या कहें। (विघ्न एवं शोर) इनसे कहिए कि ये अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। चौटाला साहब को इनकी सारी बातों का ब्यौरा भी मिल रहा है उनको पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप बैठें, मन्त्री जी जवाब देंगे।

चौ0 धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक शेर सुनाने की इजाजत दीजिए। यह एक लाईन का शेर है और इनसे बहुत ही रैलेवैन्ट शेर है-

सर झुका कर सलाम करने में कोई गुनाह नहीं
लेकिन इतना भी मत झुको कि सरताज गिर पड़े।

Mr. Speaker : Sadhaura ji, please understand the seriousness of the questions hour. You should maintain the decency of the House.

श्री बलवन्त सिंह : सर, ये हमें कहते हैं कि झुक कर सलाम करो। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram ji, you are a senior member. (Interruption)

आप भले आदमी हो। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, हमने आपको पहले ही कहा था कि इनको ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। (शोर एवं व्यवधान)

डा0 सीता राम : मैडम जी, आप बैंचों पर चढ़ जाती थीं, क्या आपको वह याद नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing to be recorded whatever they are speaking without my permission.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि दिल्ली के नेता हों या इन्टरनैशनल लैवल के नेता हों, उनके जीवन से रिलेटिड चैप्टर तो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हरियाणा के जिन लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में पार्टीसिपेट किया था और अपनी कुर्बानियां दी थीं क्या उनकी जीवनी के बारे में हरियाणा के पाठ्यक्रम में डालने का विचार करेंगे ताकि हमारे बच्चे उनके बारे में भी जान सकें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह विषय शिक्षामंत्री जी का है। हमारी सरकार इस विषय में विचार करेगी और शिक्षा मंत्री जी से इस बारे में विचार करने के लिए हम निवेदन करेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि क्या हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में स्कूलों में अध्याय जोड़ा जाएगा। मैं इनको इस बारे में बताना चाहूंगा कि जब भी कोई हरियाणा का जवान शहीद होता है तो उसके नाम से स्कूलों आदि का नाम रखा जाता है। जहां तक पाठ्यक्रम में अध्याय जोड़ने की बात है तो इस बारे में विचार कर लिया जाएगा।

Number of Cases of Theft of Canal Water Registered

***361. Dr. Sushil Indora :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state the number of cases of theft of canal water registered in the State during the year 2005-06 alongwith the steps taken or proposed to be taken to check the theft of canal water ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, 19968 cases of theft of canal water have been registered in the State during the year 2005-06. To check the theft of canal water, special watch and ward staff is deployed by the Irrigation Department during sowing seasons. Night raids are conducted with the help of police party. Tawan cases are launched against the culprits and penalty of up to 30 times the normal water charges are levied.

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने जवाब में कहा है कि 19 हजार 968 थैफ्ट के केसिज़ हैं। अध्यक्ष महोदय, कैनाल वाटर को लेने के लिए हमारे इन्टर स्टेट में भी लड़ाईयां होती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो पानी चोरी होता है। तो इस बारे में मंत्री जी बताएं कि कितने लोगों को पानी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है और कितनों को नहीं किया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तार करना तो पुलिस का काम है। (शोर एवं व्यवधान) इस बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 27 हजार से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए थे और इसमें से 26 हज़ार 917 केस डिसाईड हो चुके हैं और 4998 केसिज बैलेंस रह गए हैं। ये केस तभी रजिस्टर होते हैं जब थैफ्ट की शिकायत मिलती है। तावान के केसिज हमने लगाये हैं।

जितने इस तरह के केसिज हमने लगाये हैं उनमें 26917 केसिज डिसाइड हो चुके हैं और 4998 केसिज अभी पैंडिंग हैं।

डा० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, जब नहरी पानी चोरी होता है तो नैचुरली पानी जहां पहुंचना चाहिए वहां वह नहीं पहुंच पाता है जिससे फसल को नुक्सान होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नहरी पानी की चोरी से फसलों को कितना नुक्सान हुआ है क्या मंत्री जी इसकी असैसमैंट बताएंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीनियर मैम्बर हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कितनी फसलों का नुक्सान हुआ है। (विघ्न) क्या यह कोई इनकी सप्लीमैंट्री है ? इनको इस बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये पार्लियामैंन्ट में भी रहे हैं।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी खुद तो तैयारी करके आते नहीं हैं। इनको तैयारी करके आना चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इन भाई साहब को बताना चाहूंगा कि जो नहरी पानी की चोरी है यह एक सोशल प्राब्लम है। इस चोरी का मुख्य कारण यह है कि जो अबेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वह आप जानते ही हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं खासतौर से साउथ हरियाणा के जैसे रिवाड़ी, भिवानी और नारनौल जहां पर पानी की बहुत भारी कमी है और साथ ही वहां पर वाटर कोर्सिज भी नहीं बन पाए हैं। इसलिए ऐसे एरियाज में किसान सीधे ही अपने पाईप लगा लेता है जिसकी वजह से यह समस्या आ रही है। हम कई केसिज काडा डिवीजन में रिवाड़ी में और महेन्द्रगढ़ एरिया में लेकर आये हैं । इस तरह से कई जगह काडा ऑफिस काम कर रहे हैं और वाटर चैनल्ज बना रहे हैं। कई जगह पर चैनल नहीं है जिसकी वजह से यह दिक्कत आती है । जो इस तरह से नहरी पानी की चोरी करते हैं उन पर हम तीस गुणा अधिक तावान लगाते हैं लेकिन नोर्मली ट्यूबवैल्ज पर जो बिजली के चार्जिज लगते हैं उनसे भी नहरी पानी की चोरी के चार्जिज सस्ते पड़ते हैं जिसकी वजह से लोग परवाह नहीं करते हैं और वे नहरों के पानी की चोरी करते हैं। स्पीकर सर, आप कितना ही तावान लगा दो, केसिज बना दो लेकिन नहरी पानी की चोरी तो होती ही रहती है। स्पीकर सर, इनके समय में हैड के ऊपर मोगों के साईज बहुत बड़े कर दिये गये थे लेकिन हमने उनको भी ऐज पर स्पेसिफिकेशंज करके उन पर भी कंट्रोल किया है और टेल एंड तक पानी पहुंचाया है। इसी तरह से थैफ्ट केसिज में पुलिस भी रेड लगाती है। हम वाटर यूजर्ज ऐसोसिएशन बनाने के बारे में भी स्ट्रैस कर रहे हैं । जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बिजली बोर्ड के अंदर मीटर्ज चैक करने के लिए ऐक्स सर्विसमैन को इस्तेमाल किया तो उसी तरह से सरकार विचार कर रही है कि इस मामले में भी एक्स सर्विस मैन को लगाया जाए ताकि नहरी पानी की चोरी पर कंट्रोल हो सके।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर सर, मंत्री जी ने नहरी पानी की चोरी के 19968 केसिज बताये हैं । स्पीकर सर, अगर मंत्री जी के पास रिकार्ड हो तो बताएं कि क्या इन सारे केसिज में जुर्माना हुआ है, सजा हुई है ? जब किसान के नहरी पानी की चोरी हो जाती है तो इसकी वजह से उसकी फसल का भी नुक्सान हो जाता है तो क्या सरकार उस किसान को भी कोई मुआवजा देगी जिसका नहरी पानी चोरी हो गया है और जिसकी फसल का नुक्सान हो गया है ? इसके अलावा क्या मंत्री महोदय यह भी बताएंगे कि इस नहरी पानी की चोरी को रोकने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं। ताकि इसका परमानैन्ट हल निकाला जा सके।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जैसे कि मैंने पहले बताया है। इनके हिसार के अंदर टोटल 4817 केसिज पानी की चोरी के उस दौरान हुए थे और 275 केसिज पहले के थे जिनमें से 5070 केसिज डिसाईड हो चुके हैं और 22 केसिज बैलेंस हैं। कई केसिज में एफ०आई०आर० भी दर्ज की गयी है और लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। माननीय सदस्य ने मुआवजा देने की बात भी की है तो इस प्रकार की बात नहीं हो सकती क्योंकि उन किसानों को नहरी पानी मिल गया है।

श्री आनन्द सिंह डांगी : स्पीकर साहब, जैसा सवाल किया गया है वैसा उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है क्योंकि जिन किसानों ने पानी की चोरी की उन के बारे में तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जुर्माना लगाया है लेकिन पानी के तोड़ने से जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई उन किसानों को मंत्री जी ने क्या दिया है ?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

Number of Coaches

***370. Shri Ranbir Singh Mahendera :** Will the Minister for Sports & Youth Affairs be pleased to state the number of coaches and District Sports Officers posted at one place since the last five years ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mulana) : Sir, the number of coaches and District Sports Officers posted at one place since last five years is as follows :

1.	Coaches	90
2.	Jr. Coaches	44
3.	Assistant Coaches	02
4.	District Sports Officer	01

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो टीचर लम्बे रूटे पर बैठे हैं या जिनकी जैनूयन दिक्कतें हैं क्या उनकी स्वीट विल पर बदली की जाती है ?

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, बदली करना सरकार की कोई पौलिसी नहीं है। जब भी कोई भर्ती की जाती है तो बदली या तो जरूरत के मुताबिक होती है या कर्मचारी की रिक्वैस्ट पर होती है या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर होती है या फिर रिक्वायरमैंट के मुताबिक होती है।

श्री अध्यक्ष : महेन्द्रा जी, आपकी सप्लीमैंटरी का जवाब मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से यह सवाल पूछा था कि बदली जैनूयन केस में होती है या स्वीट विल से होती है ?

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि सरकार की जो नीति है उसके हिसाब से बदली या तो जरूरत के मुताबिक होती है या किसी शिकायत पर होती है या रिक्वैस्ट पर होती है। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्ज पर होती है। जैसा जैनूयन केस होता है उस हिसाब से बदली की जाती है।

Repair of School Buildings

*387. **Shri Ramkishan Fauji** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the buildings of the schools of the Kungar, Bhaini Kungar and Kheri Daulatpur of Bawani Khera Constituency are in dilapidated condition; and

(b) if so, the time by which the aforesaid school buildings are likely to be repaired ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mulana) : (a) &(b) Sir, it is a fact that the buildings of Govt. Senior Secondary School, Kungar, Govt. Girls High School Kungar, Govt. High School, Bhaini Kungar and Govt. Middle School, Kheri Daulatpur require repairs. Necessary repair is being carried out and it is expected to be completed by July 2006.

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हरियाणा के इतिहास में इतने स्कूल के कमरों की रिपेयर कभी नहीं हो पायी जितनी इस बार करवाई गई है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारा एरिया सेम का एरिया है इसलिए स्कूलों के जो कमरे बनाये जायें उन कमरों को ऊपर उठाकर बनाया जाये ताकि जब बरसात में पानी भरता है तो कमरों के अन्दर पानी न भर सके।

श्री फूलचन्द मुलाना : स्पीकर साहब, यह तो टैक्नीकल काम है। कुंगड़ भैणी जो गवर्नमेंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल हैं उसके लिए सरकार ने 3.44 लाख रुपये मन्जूर किये हैं, गवर्नमेंट गर्ल्ज हाई स्कूल कुंगड़ के लिए 1.20 लाख रुपये मन्जूर किए गये हैं, कुंगड़ भैणी स्कूल के लिए 4.9 लाख रुपये और खेड़ी दौलतपुर के लिए 92 हजार रुपये दिए गये हैं। इन सब स्कूलों में रिपेयर का काम चल रहा है और जरूरत के मुताबिक उनको पूरा कर दिया जायेगा।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, रिपेयर के लिए तो पैसा सरकार ने दे दिया लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि यह टैक्नीकल काम है। अगर यह टैक्नीकल काम है तो हम इस टैक्नीकल काम के लिए किसके पास जाएं, इसके बारे में भी मंत्री जी बता दें ?

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो शिक्षा विभाग में भी अपने जे०ई० होते हैं। माननीय सदस्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क करें और जिस भी चीज की जरूरत होगी उसको पूरा कर दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो स्कूलों की बिल्डिंग्ज हैं उनकी हालत पिछली सरकार के समय क्या थी यह सभी जानते हैं । हमारी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद 68 करोड़ रुपये स्कूलों की बिल्डिंग्ज की रिपेयर पर खर्च किये हैं। जिसमें से 44 करोड़ रुपये की पूर्ति एच०आर०डी०एफ० से की है। इतनी ज्यादा स्कूलों की बिल्डिंग्ज की रिपेयर राज्य में पहली दफा हो रही है।

Construction of a By-Pass from G.T. Road to Karnal Kaithal Road.

*375. **Sh. Tejendera Pal Singh Maan :** Will the Minister for P.W.D.(B&R) be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a by-pass from G.T. Road to Karnal-Kaithal road; and

(b) if so, upto what time the aforesaid proposal is likely tobe materialized?

Power Minster (Sh. Vinod Kumar Sharma) :

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, नैशनल हाई वे जी०टी० रोड़ से करनाल-कैथल जाने वाली सड़क स्टेट हाई वे है, जिस पर बहुत हैवी ट्रैफिक चलता है। यह ट्रैफिक माल रोड़ और कचहरी की तरफ से होता हुआ जाता है जिसके कारण वहां लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ता है। दस साल पहले जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी और मैं उसमें वजीर था उस समय वहां हाई वे बनाने का प्रपोजल बनाया गया था। उस समय से ही वहां पर बाई पास बनाना बहुत जरूरी थी लेकिन आज तक नहीं बना है। अब वहां पर ट्रैफिक को ठीक तरह से चलाने के लिए और शहर की जनता को नौइज पोल्यूशन से बचाने के लिए बाई पास बनाना बहुत जरूरी है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर बाई पास बनवाया जाये क्योंकि पब्लिक की यह रिक्वायरमैंट है और यह एक टाईम फ्रेम में बनाया जाये। मंत्री जी ने ना में जवाब दिया यह ठीक बात नहीं है। कृपया मन्त्री जी इस बारे में पुनर्विचार करें।

Shri Vinod Kumar Sharma : Sir, the total length of metalled P.W.D. (B&R) roads in Karnal Constituency (mainly urban areas) is 8.15 Kms. It comprises of 18.00 kms. State Highways, 5.00 kms. major District Roads and 59.15 kms. other District Roads. G.T. Road passes through the Karnal City, which is under the charge of the National Highway Authority of India. Kunjpura-Karnal-Kaithal road (State Highway No. 08) crosses the G.T. Road near I.T.I. Chowk. The reach from Km. 6.00 to 14.20 of this State Highway passes through Karnal City. The metalled width of this road is from 8.50 mtrs. to 10.00 mtrs. at various stretches. The traffic coming/going to Assandh/Jind side also passes through this road in RD 10.00 to 17.20 (upto Chirao Mor). There is no proposal under consideration of the Government for the construction of bye pass from G.T. Road to Karnal-Kaithal Road. But keeping in view the traffic congestion, the Department has conducted special survey and lot of works have to be taken up.

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अम्बाला से हिसार को जी०टी० रोड़ जाता है, बहुत पुराना है। वहां पर हर रोज कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। अम्बाला मंत्री जी का चुनाव क्षेत्र भी है। क्या सरकार के पास चण्डीगढ़ से हिसार रोड़ पर अम्बाला के पास कोई बाई पास बनाने की प्रपोजल सरकार के विचारधीन है ?

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हिसार रोड़ को वाईडनिंग करने की प्रपोजल सरकार के अंडर कंसीडरेशन है।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अम्बाला के पास बाई पास बनाने की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सढौरा साहब, प्लीज आप बैठें। आपके सवाल का जवाब मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, नारनौल शहर से होते हुए महेन्द्रगढ़ से कोटपूतली को रोड़ जाता है। और नारनौल शहर के अंदर उस रोड़ के वाईडनिंग का काम भी नहीं हो सकता।

Mr. Speaker : It is not possible to reply. You may ask separate question.

Completion of Madhogarh Minors

***406. Shri Somvir Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that more than 25 years have passed for the construction of minors emanating from Madhogarh on the Mahendergarh Canal system but neither the said minor have been completed so far nor the water has ever been released therein; and

(b) if so, the time limit by which these canal and minors will be completed and water will be released therein togetherwith the time limit by which the construction work of the bridge thereon will be completed?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : (a)and (b) Sir, it is a fact that madhogarh Branch and its off-taking channels were constructed more than 25 years ago. Water has been released in Madhogarh Branch only upto Pump House MB 2. The minors and Pump Houses in the system were completed, but the required Railway bridges have not been constructed. The required amount for construction of Railway bridges stand deposited with Railway authorities. Energisation of Pump Houses can be taken up only after construction of the Railway bridges. The matter is being pursued with the Ministry of Railways for early construction of the bridges. No definite time frame can be given as the matter relates to the Ministry of Railways.

श्री सोमवीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि करीब 1977 में 25 साल पहले यह माईनर बना था। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि शीघ्र ही इसकी रेल मंत्रालय से पैरवी करने की कोशिश की जा रही है। मंत्री जी ने टाईम के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि रेल मंत्रालय से किस-किस समय क्या-क्या कार्यवाही की गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय से कब-क्या कार्यवाही की गई और उनकी तरफ से क्या जवाब आया। इस बारे में हमें बताया जाये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री सोमवीर सिंह जी को बताना चाहूंगा कि वर्ष 1984 में यह काम शुरू हुआ था। काम के बारे में मैं इनको पूरी डिटेल दे देता हूं। (विघ्न) रेलवे कि०मी० 8.368 माधवगढ़ ब्रान्च के ऊपर उस समय 1984 में 11 लाख, 1987 में एक लाख, 1999 में 45.96 लाख रुपये सरकार की तरफ से जमा करवाए गए। अध्यक्ष महोदय, उस समय इनकी सरकार थी और उसके बाद सिमिलरली कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ब्रिज जो कि०मी० 6.990 सतनाली के पैसे वर्ष 2003 में भी जमा हुए और वर्ष 1987 में भी जमा हुए हैं। इसके अलावा हमारी सरकार आने के बाद मैंने स्वयं अधिकारियों की मीटिंग ली और जब मुझे यह बात पता लगी तो दिनांक 13-1-2006 को मैंने डी०ओ० लैटर श्री लालू प्रसाद यादव जी को लिखा। इस डी०ओ० लैटर का नं० 198-2 एल०सी०यू० है। जो पत्र इनने श्री लालू प्रसाद यादव जी को लिखा था अभी तक उस पत्र का जवाब नहीं आया है। इसके अलावा मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि मैंने फाईनैंशियल कमिशनर, इरिगेशन को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं जा कर जी०एम० और रेलवे अथौरिटी से बात करें। मैंने इस बारे में निर्देश दे दिये हैं और हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यह पुल बने। इस प्रकार का प्रयास पहले होना चाहिए था। हमारी सरकार बने तो अभी केवल एक वर्ष का समय ही हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मुझे जब इसके बारे में पता लगा तो मैंने उस वक्त डी०ओ० लैटर लिखा है और हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि यह ब्रिज जल्दी से जल्दी बन सके। एस०ई० इरिगेशन और अन्य अधिकारियों से मिलकर कोशिश करेंगे ताकि इनके ये ब्रिजिज बन सकें।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं 1996 के अन्दर एम०एल०ए० बना था और 1999 में मैंने इसकी पैरवी की थी और प्रयास किया था कि इसको बनाने के लिए सरकार से निवेदन किया था कि इसको शीघ्र बनाने की कार्यवाही कीजिए। उस समय के बाद इस बारे में कोई लम्बी-चौड़ी कार्यवाही नहीं हुई है और अब हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रोजेक्ट जल्दी ही बन जाएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह जो बात कह रहे हैं हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। वहां के लोग पहले यह कार्य नहीं कर पाए जबकि वहां के लोग रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं और उन्हें उस वक्त इसे देखना चाहिए था। (विघ्न)

Share of Water in Haiderpur Treatment Plant

***449. Shri Mahender Partap Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the details of share of allocation of water in cusecs to the States of Uttar Pradesh, Haryana and Delhi from Wazirabad and Haiderpur Treatment Plant as per latest agreement; and

(b) the cusecs of water being made available to Haryana and Delhi at present ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : (a) & (b) Sir, there is no such agreement.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने शायद शब्दों की टैक्नीकलिटी के आधार पर जवाब लिख दिया। सवाल लिखने पर कहां पर क्या कमी रही यह अलग बात हो सकती है लेकिन सवाल की मूल भावना को माननीय मन्त्री महोदय समझते हैं। मेरे सवाल का तात्पर्य यह है कि जो नया एम०ओ०यू० यमुना के पानी के बंटवारे को लेकर यू०पी०, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा 5 स्टेटस के बीच में हुआ है उसके मुताबिक हमारा और दिल्ली का अलग अलग कितना शेयर रहा और क्या वह शेयर हमें उतना ही मिलेगा या अवेलेबल पानी के आधार पर मिलेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इनका क्वैश्चन टैक्नीकली गलत था लेकिन इसके बावजूद भी माननीय सदस्य की भावना को समझते हुए मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह जो शेयरिंग ऑफ यमुना वाटर का हमारा एम०ओ०यू० हुआ था वह स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एण्ड राजस्थान के बीच 12 मई, 1994 में हुआ था और उसके बाद यहां पर दूसरी सरकारें आईं। हमारी कांग्रेस सरकार 1996 में चली गई थी उसके बाद कई सरकारें आईं लेकिन किसी ने भी किसाऊ डैम को बनाने के बारे में कोई प्रयास नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, यह पानी का बंटवारा तब होगा जब किसाऊ डैम बने लेकिन उसके लिए पिछली किसी भी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। इसके बारे में मुख्य मन्त्री जी स्वयं सैवरल सोर्सिज से मिले हैं और उनसे कहा है कि किसाऊ डैम को बनाने की जरूरत है। इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। जहां तक शेयरिंग की बात है, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वह शेयर तब बनता है जब कि किसाऊ डैम बनता है। उसमें हरियाणा का शेयर 4.78 एम०ए०एफ०, उत्तर प्रदेश 3.36 एम०ए०एफ०, राजस्थान का .93 एम०ए०एफ०, हिमाचल प्रदेश का .31 एम०ए०एफ०, तथा दिल्ली का .60 एम०ए०एफ० है। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के एक आर्डर की वजह से मुश्किल खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश पास हुआ है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन जस्टिस श्री कुलदीप सिंह ने एक ऐसा आर्डर पास कर दिया जिसकी वजह से.........

Mr. Speaker : Now the questions hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Utilization of HRDF

*443. **Sh. Jai Singh Rana :** Will the Chief Minister be pleased to State
Sh. Naresh Yadav : the district-wise details of allocation and utilization of HRDF Funds in the State year-wise since 2000-2001 to till date ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

Information

Haryana Rural Development Funds administration Board

Year wise Summary and District wise report of funds allocated and utilised amount (2000-2006 till 28-2-06)

Rs. in lacs

S. No.	District	2000-2001 (from 1-4-2000 to 31-3-2001)		2001-2002 (from 1-4-2001 to 31-3-2002)		2002-2003 (from 1-4-2002 to 31-3-2003)		2003-2004 (from 1-4-2003 to 31-3-2004)		2004-2005 (from 1-4-2004 to 31-3-2005)		2005-2006 (Till) (from 1-4-2005 to 28-2-2006)		2000-2006 (till 28-2-06) (from 1-4-2000 to 28-3-2006)	
		Allocated Amount	Utilised Amount	Allocated Amount	Utilised Amount	Allocated Amount	Utilised Amount	Allocated Amount	Utilised Amount	Allocated Amount	Utilised Amount	Allocated Amount	Utilised Amount	Allocated Amount	Utilised Amount
1.	Ambala	186.23	162.74	1290.46	112.25	277.06	248.12	1271.87	1150.08	1439.66	782.39	359.35	118.25	4824.63	2573.83
2.	Bhiwani	684.36	592.11	1714.93	1430.79	973.83	811.22	2467.76	1942.68	2568.79	2069.01	779.08	233.47	9188.75	7079.28
3.	Faridabad	149.71	144.56	1141.61	983.90	346.89	296.90	2082.57	1620.11	688.15	514.95	636.49	202.62	5045.42	3763.03
4.	Fatehabad	326.22	298.36	776.88	682.16	1008.31	806.07	1734.72	1506.90	1777.57	1585.15	292.97	12.19	5916.67	4890.85
5.	Gurgaon	1668.11	1502.01	1490.27	930.43	1301.89	159.61	2531.31	133.78	1686.92	0.00	469.69	0.00	8948.19	2725.83
6.	Hissar	561.33	547.64	771.34	744.04	463.22	397.17	1497.63	966.30	1206.12	1024.63	658.20	152.00	5157.84	3831.78
7.	Jhajjar	321.84	291.57	522.01	386.82	1758.69	1174.57	955.91	683.15	1795.83	1329.94	896.35	92.00	6252.63	3960.05
8.	Jind	681.20	601.55	1003.31	954.70	1205.45	561.73	1887.06	1334.13	2465.65	1334.13	564.43	88.42	7807.10	5174.66
9.	Kaithal	291.91	291.91	1024.54	959.29	1028.12	686.57	1314.27	1126.94	1483.54	616.65	990.18	132.71	6132.56	3814.07
10.	Karnal	168.58	168.58	988.84	898.80	234.43	204.00	1160.71	1026.94	879.98	343.66	137.07	0.00	3569.61	2641.98
11.	Kurukshetra	412.81	358.97	1413.60	1293.05	332.62	260.00	1026.26	855.23	1143.24	791.38	341.52	46.20	4670.05	3604.83
12.	Mewat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.61	32.10	251.61	32.10
13.	Mohindergarh	48.30	47.05	672.46	590.30	410.53	306.75	540.71	339.61	829.63	391.78	258.22	249.13	2759.85	1924.62
14.	Panchkula	10.91	10.91	315.00	304.71	441.54	418.31	205.09	192.78	250.41	90.86	186.67	0.00	1409.62	1017.57
15.	Panipat	30.55	30.55	436.52	390.13	544.57	407.08	188.76	142.40	668.29	387.40	141.57	6.58	2010.26	1364.14
16.	Rewari	29.61	29.61	318.02	299.85	767.14	634.69	1092.61	681.60	905.86	663.96	557.31	50.25	3670.55	2359.96
17.	Rohtak	175.90	175.90	350.51	264.41	647.23	464.04	608.07	427.55	808.16	530.80	3128.13	420.05	5718.00	2282.75
18.	Sirsa	4157.04	3282.50	1603.17	1406.91	3823.00	2743.69	752.96	606.79	3134.96	2514.33	314.55	0.00	13785.78	10554.22
19.	Sonipat	207.76	182.34	684.35	627.70	570.63	490.20	943.59	820.81	2002.32	1334.41	783.18	65.92	5191.83	3521.38
20.	Yamunanagar	331.79	277.55	1892.30	1739.75	761.98	698.91	774.00	657.99	962.12	712.43	422.87	16.43	5165.06	4103.06
District Total		**10444.16**	**8996.42**	**18410.12**	**15001.99**	**16897.13**	**12069.63**	**23035.86**	**16215.77**	**26517.20**	**17017.86**	**12171.54**	**1918.32**	**107476.01**	**71219.99**
Public Health		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**
Irrigation		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1000.00**	**0.00**
Grand Total		**10444.16**	**8996.42**	**18410.12**	**15001.99**	**16897.13**	**12069.63**	**24035.86**	**16215.77**	**26517.20**	**17017.86**	**12671.54**	**1918.32**	**108976.01**	**71219.99**

Total Amount Allocated = 1089.76 Crores

Total Amount Utilised = 712.20 Core

Construction of Hospital in Pillukhera

*458. **Shri Bachan Singh Arya :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a 15-20 beds hospital in Pillukhera Mandi near future in Safidon Constituency ?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहन करतार देवी) : जी नहीं, श्रीमान।

Reinstatement of IAS/IPS/HCS Officers

*414. **Prof. Chhatar Pal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of IAS, IPS, HCS and HPS officers reinstated so far by the Government who remained suspended during the tenure of Sh. Om Prakash Chautala Government ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : सरकार द्वारा अब तक 10 अधिकारियों जिनमें चार आई०ए०एस० दो आई०पी०एस०,तीन एच०सी०एस० एवम् एक एच०पी०एस० अधिकारी हैं, को सेवा में बहाल किया गया है जो पूर्व सरकार के कार्यकाल में निलम्बित थे।

Developing of Housing Board Colony of Indri

*423. **Shri Rakesh Kamboj :** Will the Minister of State for Housing be pleased to State :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to develop the Housing Colony at Indri district Karnal ; and

(b) if so, upto what time the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

शहरी विकास राज्य मन्त्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Reducing the size of Mogas

*419. **Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that the size of all outlets (Mogas) of canals have been reduced specially in Bass, Puthi, Mohla, Badala, Bedchhaper, Hasatpur and almost in all villages of Narnaund Constituency ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : जी नहीं, श्रीमान जी।

Flood in Yamuna

*462. **Shri Arjun Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Kharif Crops of village Lakar, Bhilpura, Malimajra, Nawajpura, Kanyawala, Jairumpur, Haldri, Rampur and Mandoli etc. of tehsil Chhachhrauli was damaged completely and the Rabi Crops could not be sown due to the flood of Yamuna and the cultivable and residential land of the said villages was ruined on account of it; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to save the aforesaid villages from the Yamuna flood in future ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) श्रीमान जी, वर्ष 2005 में यमुना की बाढ़ से छछरौली तहसील के गांव लाकड़, भीलपूरा, बेलगढ़, बाड़ा दामोपुर, मेहर माजरा, अलीपुरा, नवाजपुर, कन्यावाला, हल्दरी रामपुर, खादर और मंडौली नागर के आबादी क्षेत्र व 2551 एकड़ खरीफ की फसल हो हानि हुई। 750 एकड़ के क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक, 206 एकड़ के क्षेत्र में 51 से 75 प्रतिशत तक और 1595 एकड़ के क्षेत्र में 76 से 100 प्रतिशत तक हानि हुई थी। 2268 एकड़ के क्षेत्र में रबी की फसल की बीजाई की गई तथा केवल 283 एकड़ भूमि में रबी की फसल की बीजाई नहीं की जा सकी थी।

(ख) भविष्य में उपरोक्त गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए बाढ़ बचाव कार्यों को स्वीकृत किया गया है और उन पर निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है।

Agreement between Haryana Government and Reliance Group.

*429. **Shri Naresh Yadav :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether any agreement has been reached between the State of Haryana and the Reliance Group of Industries to allot Agricultural land in the State particularly in district Mahendergarh and Rewari; if so, when; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to allot the barren/non-fertile land instead of fertile Agricultural land to the Reliance Industries; if so, the details thereof togetherwith the steps proposed to be taken to rehabilitate those persons/families whose lands to be acquired for the aforesaid purpose ?

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) :

(क) नहीं श्रीमान। परन्तु हरियाणा में विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम और रिलांयस वैन्चर लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (मैमोरैंडम आफ अण्डरस्टैन्डिंग) हस्ताक्षरित किया गया है।

(ख) बड़े आकार की इस प्रस्तावित परियोजना के मध्यनजर, लगातार भूमि का होना जरूरी है, इसलिए यह अनिवार्य नहीं कि इस परियोजना निर्धारण के लिए भूमि केवल बंजर व अनउपजाऊ ही हो। इस परियोजना को सुसाध्य बनाने के लिए जिन लोगों की भूमि अधिग्रहण की जायेगी, उनके हितों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विस्तृत नीति लागू करने का प्रस्ताव है। यह नीति राज्य सरकार और रिलांयस इण्डस्ट्रीज के बीच होने वाले विस्तृत समझौते का आधार होगी।

Memorial in the name of Pt. Lakhmi Chand

*436. **Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to establish any memorial in the name of Pt. Lakhmi Chand of village Janti and Sh. Mehar Singh Jat of village Barona, district Sonepat who were renowned singer of Haryanavi songs ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Cases of Rape/Murder etc. registered in the State

37. **Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of criminal cases registered in the State during the period from March, 2005 to 31 st January, 2006; and

(b) the district -wise and month wise detail of the cases of murder, rape, looting, dacoity registered in the State during the period from March, 2004 to 31st January, 2005 and March, 2005 to 31st January, 2006 Separately ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : (क) एवं (ख) वांछित सूचना सदन के पटल में रखी जाती है।

(क) राज्य में मार्च, 2005 से 31 जनवरी, 2006 तक भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 40353 मुकदमें दर्ज हुये।

(ख) राज्य में मार्च, 2005 से 31 जनवरी, 2006 तक स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत 21576 मुकदमें दर्ज हुये।

(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)

हत्या

सूचना
मार्च 2004 से 31 जनवरी 2005 तक

जिला	मार्च 2004	अप्रैल 2004	मई 2004	जून 2004	जुलाई 2004	अगस्त 2004	सितम्बर 2004	अक्तूबर 2004	नवम्बर 2004	दिसम्बर 2004	जनवरी 2005	कुल
पंचकूला	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	6
अम्बाला	6	1	3	3	1	5	3	3	2	0	0	27
यमुनानगर	5	1	3	2	2	1	2	2	0	3	2	23
कुरूक्षेत्र	3	2	2	2	2	3	2	2	3	1	0	22
कैथल	2	1	1	4	4	2	0	2	4	0	1	21
हिसार	2	5	1	7	9	3	8	4	4	9	6	58
सिरसा	2	4	3	2	3	0	3	1	0	3	1	22
भिवानी	5	9	3	4	4	2	5	5	2	4	3	46
जीन्द	0	4	4	2	4	2	3	4	3	1	3	30
फतेहाबाद	2	1	4	3	4	1	3	3	2	2	0	25
गुड़गांवा	4	2	4	7	4	7	10	6	2	4	7	57
फरीदाबाद	8	2	9	4	6	5	6	9	6	2	5	62
नारनौल	0	1	2	2	3	3	1	1	1	1	2	17
रिवाड़ी	2	1	2	3	4	1	1	1	2	1	2	20
मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
रोहतक	6	4	0	8	9	5	5	3	3	7	2	52
सोनीपत	5	6	4	3	7	3	10	5	4	8	6	61
करनाल	4	5	4	4	2	3	6	1	1	2	2	34
पानीपत	4	0	4	5	5	2	2	3	5	3	1	34
झज्जर	7	7	2	3	6	3	5	0	5	1	6	45
रेलवेज	3	3	1	0	4	2	5	1	0	3	0	22
कुल	**71**	**60**	**56**	**68**	**83**	**56**	**81**	**56**	**49**	**55**	**52**	**687**

(ख) हत्या

मार्च 2005 से 31 जनवरी 2006 तक

जिला	मार्च 2005	अप्रैल 2005	मई 2005	जून 2005	जुलाई 2005	अगस्त 2005	सितम्बर 2005	अक्तूबर 2005	नवम्बर 2005	दिसम्बर 2005	जनवरी 2006	कुल
पंचकूला	0	1	1	0	0	1	1	3	0	1	1	9
अम्बाला	0	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	16
यमुनानगर	3	0	3	0	0	1	2	2	1	1	0	13
कुरूक्षेत्र	2	5	1	2	2	4	4	4	0	1	1	26
कैथल	2	0	3	4	3	2	2	3	0	2	1	22
हिसार	2	1	6	1	5	1	0	6	0	2	1	25
सिरसा	2	3	1	0	2	5	1	3	3	2	2	24
भिवानी	9	1	1	1	3	0	0	2	1	2	4	24
जीन्द	1	1	2	1	4	3	2	3	5	3	0	25
फतेहाबाद	0	0	2	0	2	2	0	3	3	4	2	18
गुडगांवा	4	1	3	2	1	1	1	6	3	2	6	30
फरीदाबाद	5	2	3	5	4	5	5	8	4	8	2	49
नारनौल	1	4	1	1	1	2	1	0	0	0	2	13
रिवाड़ी	2	0	1	3	0	0	2	2	3	3	1	17
मेवात	0	4	3	2	3	0	4	1	2	1	0	20
रोहतक	5	0	1	4	4	2	3	5	3	3	2	32
सोनीपत	8	1	3	3	2	4	1	9	8	6	7	52
करनाल	5	2	7	8	7	4	3	3	7	1	1	48
पानीपत	1	6	10	2	5	3	7	2	3	2	0	41
झज्जर	5	2	1	1	1	2	2	9	4	4	1	32
रेलवेज	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	6
कुल	**57**	**35**	**55**	**42**	**50**	**44**	**43**	**79**	**52**	**48**	**37**	**542**

(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)

(ख)
बलात्कार

सूचना

मार्च 2004 से 31 जनवरी 2005 तक

जिला	मार्च 2004	अप्रैल 2004	मई 2004	जून 2004	जुलाई 2004	अगस्त 2004	सितम्बर 2004	अक्तूबर 2004	नवम्बर 2004	दिसम्बर 2004	जनवरी 2005	कुल
पंचकूला	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7
अम्बाला	1	2	0	0	1	1	0	1	1	0	1	9
यमुनानगर	0	1	1	0	4	1	5	1	0	0	0	13
कुरुक्षेत्र	1	1	0	1	4	4	1	1	2	2	3	20
कैथल	2	0	3	0	3	2	4	2	0	1	1	16
हिसार	4	1	5	5	1	4	3	0	2	0	0	25
सिरसा	2	3	4	3	0	1	1	1	0	1	1	17
भिवानी	6	0	2	1	6	4	0	0	2	1	5	27
जीन्द	0	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	7
फतेहाबाद	1	0	1	0	4	0	1	1	0	1	0	9
गुडगांवा	7	2	1	5	4	1	1	4	3	2	0	30
फरीदाबाद	5	1	3	6	4	7	3	2	3	2	3	39
नारनौल	0	1	0	1	1	1	3	2	1	5	0	15
रिवाड़ी	2	2	2	4	1	2	2	2	0	1	0	16
मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
रोहतक	0	4	3	3	0	3	4	0	3	3	4	27
सोनीपत	1	2	1	2	3	0	0	0	0	0	2	11
करनाल	3	2	2	3	1	5	0	4	2	2	2	26
पानीपत	3	0	2	2	4	3	5	4	4	7	0	34
झज्जर	1	1	1	0	0	3	0	1	3	0	0	10
रेलवेज	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
कुल	39	24	35	38	44	43	33	26	28	29	28	367

(ख) बलात्कार

मार्च 2005 से 31 जनवरी 2006 तक

जिला	मार्च 2005	अप्रैल 2005	मई 2005	जून 2005	जुलाई 2005	अगस्त 2005	सितम्बर 2005	अक्तूबर 2005	नवम्बर 2005	दिसम्बर 2005	जनवरी 2006	कुल
पंचकूला	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	6
अम्बाला	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	19
यमुनानगर	2	0	3	0	0	1	2	0	0	2	1	11
कुरुक्षेत्र	1	5	1	2	2	4	4	0	1	1	2	23
कैथल	3	0	3	4	3	2	2	1	1	1	0	20
हिसार	1	1	6	1	5	1	0	0	1	3	2	21
सिरसा	1	3	1	0	2	5	1	0	0	1	0	14
भिवानी	0	1	1	1	3	0	0	1	1	1	3	12
जीन्द	0	1	2	1	4	3	2	0	1	0	4	18
फतेहाबाद	0	0	2	0	2	2	0	1	0	1	2	10
गुडगांव	4	1	3	2	1	1	1	0	3	0	2	18
फरीदाबाद	7	2	3	5	4	5	5	2	2	0	3	38
नारनौल	3	4	1	1	1	2	1	0	0	0	0	13
रियाड़ी	2	0	1	3	0	0	2	2	1	0	0	11
मेवात	0	4	3	2	3	0	4	5	2	0	4	27
रोहतक	2	0	1	4	4	2	3	2	2	1	1	22
सोनीपत	1	1	3	3	2	4	1	0	4	4	2	25
करनाल	3	2	7	8	7	4	3	2	5	4	3	48
पानीपत	2	6	10	2	5	3	7	9	5	3	3	55
झज्जर	1	2	1	1	1	2	2	2	1	0	0	13
रेलवेज	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
कुल	37	35	55	42	50	44	43	29	33	24	34	426

(ख) लूट (392/394/382 भा०द०सं०)

मार्च 2004 से 31 जनवरी 2005 तक

जिला	मार्च 2004	अप्रैल 2004	मई 2004	जून 2004	जुलाई 2004	अगस्त 2004	सितम्बर 2004	अक्तूबर 2004	नवम्बर 2004	दिसम्बर 2004	जनवरी 2005	कुल
पंचकूला	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4
अम्बाला	0	0	2	0	0	1	2	3	0	0	2	10
यमुनानगर	4	2	0	2	1	3	0	1	0	1	1	15
कुरूक्षेत्र	1	1	0	0	2	3	4	2	2	4	0	19
कैथल	2	4	2	0	1	1	0	0	0	2	1	13
हिसार	3	1	2	5	2	3	2	1	3	2	1	25
सिरसा	1	0	3	2	2	1	1	2	1	3	1	17
भिवानी	3	4	5	3	4	1	3	1	1	4	2	31
जींद	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
फतेहाबाद	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	6
गुडगांवा	3	2	0	1	2	6	5	5	1	3	1	29
फरीदाबाद	4	3	4	1	2	1	0	3	4	3	3	28
नारनौल	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	6
रिवाड़ी	3	2	0	5	0	2	2	0	1	2	2	19
मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रोहतक	1	3	0	2	5	1	4	3	2	4	4	29
सोनीपत	0	3	0	3	3	4	2	4	6	4	9	36
करनाल	2	2	1	2	0	1	2	2	1	3	1	17
पानीपत	2	2	4	1	0	3	1	3	1	3	3	23
झज्जर	1	0	1	1	3	2	2	1	1	2	3	17
रेलवेज़	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	5
कुल	32	30	25	29	30	35	31	33	28	45	35	354

(ख) लूट (392/394/382 भा0द0स0)

मार्च 2005 से 31 जनवरी 2006 तक

जिला	मार्च 2005	अप्रैल 2005	मई 2005	जून 2005	जुलाई 2005	अगस्त 2005	सितम्बर 2005	अक्तूबर 2005	नवम्बर 2005	दिसम्बर 2005	जनवरी 2006	कुल
पंचकुला	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	5
अम्बाला	2	3	1	2	3	5	2	0	2	0	1	21
यमुनानगर	1	1	0	1	3	3	0	1	1	2	1	14
कुरूक्षेत्र	2	4	1	2	2	4	1	5	0	2	0	23
कैथल	1	0	0	1	0	2	1	1	1	0	1	8
हिसार	2	2	7	0	2	4	3	4	2	2	4	32
सिरसा	3	3	1	0	0	2	0	2	0	1	3	15
भिवानी	2	3	2	3	5	4	2	3	1	1	0	26
जीन्द	0	3	2	0	0	1	0	1	0	0	1	8
फतेहाबाद	0	1	1	0	1	1	3	1	1	3	1	13
गुडगांवा	5	9	3	3	6	5	8	3	2	5	8	57
फरीदाबाद	3	0	4	2	2	0	2	3	6	5	4	31
नारनौल	1	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	7
रिवाड़ी	1	2	0	2	2	1	3	1	0	0	2	14
मेवात	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
रोहतक	3	9	3	3	3	3	5	3	3	2	4	41
सोनीपत	3	3	1	4	2	7	4	4	3	4	2	37
करनाल	1	5	3	2	3	1	3	1	4	4	7	34
पानीपत	4	1	5	3	7	1	3	3	3	5	3	38
झज्जर	1	5	8	5	4	4	3	0	0	1	1	32
रेलवेज	1	2	0	0	4	0	1	2	0	0	0	10
कुल	56	58	49	35	51	50	45	40	30	38	44	470

(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)

(ख) डकैती

मार्च 2004 से 31 जनवरी 2005 तक

जिला	मार्च 2004	अप्रैल 2004	मई 2004	जून 2004	जुलाई 2004	अगस्त 2004	सितम्बर 2004	अक्तूबर 2004	नवम्बर 2004	दिसम्बर 2004	जनवरी 2006	कुल
पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
यमुनानगर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
कुरूक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
कैथल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
हिसार	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
सिरसा	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
भिवानी	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
जीन्द	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
गुड़गांवा	0	1	1	1	0	1	3	1	1	2	0	0
फरीदाबाद	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	11
नारनौल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
रिवाड़ी	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
रोहतक	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
सोनीपत	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
करनाल	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	3
पानीपत	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	3
झज्जर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
रेलवेज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**2**	**4**	**5**	**6**	**2**	**6**	**4**	**3**	**3**	**4**	**1**	**40**

(ख) डकैती

मार्च 2005 से 31 जनवरी 2006 तक

जिला	मार्च 2005	अप्रैल 2005	मई 2005	जून 2005	जुलाई 2005	अगस्त 2005	सितम्बर 2005	अक्तूबर 2005	नवम्बर 2005	दिसम्बर 2005	जनवरी 2006	कुल
पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अम्बाला	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
यमुनानगर	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3
कुरुक्षेत्र	0	0	0	1	2	3	1	2	2	3	0	14
कैथल	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
हिसार	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
सिरसा	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
भिवानी	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
जींद	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुडगांवा	3	0	0	1	1	0	1	0	1	2	1	10
फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
नारनौल	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
रिवाड़ी	1	4	0	0	0	0	0	1	2	1	1	11
मेवात	0	1	1	1	2	1	1	4	1	0	0	12
रोहतक	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
सोनीपत	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
करनाल	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	5
पानीपत	1	1	1	0	0	1	1	0	2	1	0	8
झज्जर	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
रेलवेज	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
कुल	**7**	**11**	**6**	**8**	**7**	**9**	**7**	**8**	**10**	**10**	**3**	**86**

Strength of the Members of H.P.S.C.

***33. Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state total strength of members of the Public Service Commission, Haryana, togetherwith the number and names of its present members with their qualifications alongwith the date of their appointment and retirement ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हरियाणा लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं आठ सदस्य है। वर्तमान सदस्यों के नाम, योग्यता, नियुक्ति की तिथि तथा सेवानिवृति की तिथि के बारे सूची नीचे रखी है :--

क्र० सं०	नाम	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	सेवा निवृति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री मेहर सिंह सैनी, अध्यक्ष	बी०ए०एस०एस०	1-12-2004	30-11-2010
2.	श्री डूंगर राम, सदस्य	एम०ए० (अंग्रेजी)	5-7-2004	9-6-2009
3.	श्री छतर सिंह, सदस्य	बी०ई० (इलैक्ट्रीकल)	5-7-2004	4-7-2010
4.	श्री युद्धवीर सिंह, सदस्य	बी०ए०	5-7-2004	4-7-2010
5.	श्री सतबीर सिंह, अधिवक्ता, सदस्य	बी०ए० (आनर्स) एल० एल०बी०	5-7-2004	4-4-2010
6.	श्री ओम प्रकाश, सदस्य	बी०ए०एल०एल०बी०	10-8-2004	9-8-2010
7.	श्री रणबीर सिंह हुड्डा, सदस्य	बी०एस०सी०(एग्रोनोमी) एम०एस०सी० (एग्रोनोमी) पी०एच०डी०, एल०एल०बी०	10-8-2004	9-8-2010
8.	श्रीमति संतोष सिंह, सदस्य	एम०एस०सी०, बी०एड०	1-12-2004	30-11-2010
9.	श्री राम कुमार कश्यप, सदस्य	एम०ए० (अर्थशास्त्र) एल०एल०बी०	15-12-2004	14-12-2010

Generation of Electricity

***40. Dr. Sushil Indora :** Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) the total quantum of electricity being generated in the State from all resources;

(b) the demand of electricity of the State; and

(c) the quantum of electricity being supplied in the State ?

बिजली मन्त्री (श्री विनोद कुमार शर्मा) :

(क) राज्य में स्थित विद्युत उत्पादन स्टेशनों की कुल उत्पादन क्षमता 1587.4 मैगावाट है, इसके अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से जैसे बी०बी०एम०बी० तथा केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन स्टेशनों से दीर्घकालीन विद्युत क्रय समझौते के अन्तर्गत 2445.6 मैगावाट की उत्पादन क्षमता हरियाणा राज्य के पास उपलब्ध है। इन स्त्रोतों से बिजली की उपलब्धता ऋतु अनुसार 500 लाख यूनिट प्रतिदिन से 700 लाख यूनिट प्रतिदिन तक रहती है। इन स्त्रोतों से उच्चतम उपलब्धता 3200 से 3400 मैगावाट के बीच रहती है।

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान बिजली की उच्चतम मांग 3500 से 4500 मैगावाट के बीच रही तथा औसत मांग 564 से 857 लाख यूनिट प्रतिदिन तक रही । वर्ष 2006-07 के दौरान अपेक्षित उच्चतम मांग 3800 से 4900 मैगावाट तक होनी सम्भावित है तथा पिछले वर्ष की तुलना में अनुमानित 8% बढ़ौतरी के आधार पर वर्ष 2006-07 में औसत मांग 598 से 902 लाख यूनिट प्रतिदिन होनी अपेक्षित है।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान 28-2-2006 तक 557 से 775 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली की आपूर्ति की गई तथा अगस्त, 2005 में उच्चतम 3980 मैगावाट की मांग को पूरा किया गया।

Registration Fee of Tractor

***38. Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Transport be pleased to state the registration fees of the tractors in the year 2004-2005 and at present ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : वर्ष 2004-2005 में ट्रेक्टरों की पंजीकरण फीस 200/-रुपये थी। चालू वित्तिय वर्ष में दिनांक 31-8-2005 से किसानों को पंजीकरण फीस की अदायगी से छूट प्रदान कर दी गई है।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

15.00 बजे **डा० सुशील इन्दौरा :** अध्यक्ष महोदय, हमने कालिंग अटैंशन मोशन regarding shortage of power in Haryana either in agriculture, domestic, commercial or industrial sector दी थी उसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : वह डिसाअलाऊ कर दिया गया है।

डा० सीताराम : अध्यक्ष महोदय, हमने कालिंग अटैंशन मोशन regarding new policy of Government regarding purchase of mustard दी थी। इसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : वह डिसअलाऊ कर दिया गया है।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैंने कालिंग अटैंशन मोशन regarding deteriorating law and order situation in the State दी थी। उसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : आपने यह कालिंग अटैंशन मोशन आज 2 बजकर 5 मिनट पर दी है और कालिंग अटैंशन मोशन की रूलिंग में यह है "that it should be submitted one hour before the commencement of the sitting of the Session." गौतम जी अब आप इस बारे में कल ही पूछना।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

पूरे राज्य में पहले ओस द्वारा तथा अब बेमौसमी वर्षा के कारण रबी फसलों विशेषकर गेहूं तथा सरसों की क्षति सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a calling attention motion No. 3 from Shri Dharampal Singh Malik, M.L.A., regarding the damage of Rabi crops particularly wheat and mustard in the whole State earlier by dew and now due to untimely rain and similar calling attention motion No. 5 given notice of by Dr. Sushil Indora and six other members on the same subject, which has been bracketed with the calling attention motion No. 3 of Shri Dharam Pal Singh Malik, M.L.A. I admit the same. Shri Dharam Pal Singh Malik, M.L.A. may read his notice.

Ch. Dharam Pal Singh Malik : Speaker Sir, I want to draw the kind attention of this august House towards an urgent matter of public importance that the Rabi crops particularly wheat and mustard in the whole State had been completely destroyed earlier by dew and now due to untimely rain. The Government should immediately rush to give the relief to the farmers and the tenants, who are the worst sufferers in the State, where the crops have been completely damaged. So, Sir, I would request to the Government to make a statement in this regard on the floor of the House.

Sarvshri Sushil Indora, Balwant Singh, Ishwar Singh, Ramphal, Gian Chand, Sahida Khan and Smt. Rekha Rana, MLAs want to draw the attention of this august House towards the loss caused to the crops due to natural calamities being faced time and again by the farmers of the Haryana State. A few days back massive loss caused to the crops of the mustard, potatoes, vegetables, flowers and fruits due to the severe cold (Frost bite) in the State of Haryana. The farmers had not even over-come the said loss, heavy loss was again caused to the crops of wheat and mustard due to untimely rain. Not only this, Government has started recovery of abiana.

Therefore, they request the Government to provide relief to the farmers by conducting the special girdawari of the crops and by waiving of abiana. They request the Government to make a statement on the floor of the House in this regard.

डा0 सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हमने जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया था, उसको आपने धर्मपाल सिंह मलिक जी के कालिंग अटैंशन मोशन के साथ क्लब कर दिया है जबकि हमारे कालिंग अटैंशन मोशन का सब्जैक्ट अलग है।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आपने जो कालिंग अटैंशन मोशन नम्बर 5 दिया था उसका सब्जैक्ट और धर्मपाल सिंह मलिक जी की कालिंग अटैंशन मोशन नम्बर 3 का सब्जैक्ट एक जैसा है। इसलिए उसको कलब किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, माननीय इन्दौरा जी को आप स्पैशल पार्लियामैंट क्लासिज लगाएं। आपने इनके कालिंग अटैंशन मोशन को एडमिट कर लिया है और फिर भी ये शोर मचा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वाक-आउट

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, आपने हमारी कालिंग अटैंशन मोशन मलिक साहब की कालिंग अटैंशन मोशन के साथ कलब कर दी है। जोकि आपको नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उनकी कालिंग अटैंशन मोशन का सब्जैक्ट अलग है। आपने हमारी कालिंग अटैंशन मोशन को उनकी कालिंग अटैंशन मोशन के साथ कलब कर दिया है। इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए।)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : आपके पास बोलने को तो कुछ है नहीं इसलिए आप वाक-आउट का बहाना बनाकर भाग रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप बिना बरसात के छतरी उतारने लग रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनको आप तरीका भी सीखाएं कि अपनी बात कहां से खड़े हो कर बोलनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

वक्तव्य-

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी राजस्व मंत्री द्वारा

Mr. Speaker : Now, the Revenue Minister, please make your statement.

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, in response to the Calling Attention Motion No. 3 and 5 (Interruption) आपकी बात भी कह रहे हैं। आपकी जो कालिंग अटैंशन मोशन थी वह कलब कर दी गई है। आप अपनी सप्लीमैटरी पूछ लेना (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Dr. Indora, I will provide the opportunity to you. You can ask your supplementary. I am saying this thing repeatedly.

Now, the Revenue Minister, please make your statement.

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Speaker Sir, in response to Calling Attention Notice No. 3&5 (Calling Attention Notice No. 5), bracketed with Calling Attention Notice No. 3, regarding the damage caused to the crops of Mustard, Potato, Vegetables, Flowers and Fruits due to cold wave and frost during the Rabi season, it is stated that the scheme for Constitution and Administration of the Calamity Relief Fund as enumerated by the 12th Finance Commission, provides for immediate relief, only to the victims of cyclone, drought, earthquake, fire flood,

[Capt. Ajay Singh Yadav]
tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud burst and pest attack. Damage due to cold wave and frost is not covered under this Scheme. In fact, the request of Haryana Government for inclusion of the Natural Calamity of Cold Wave in the States specific items was turned down by the Govt. of India in January, 2002 उस समय इन लोगों की सरकार थी और सैंटर में NDA की सरकार थी लेकिन उस समय की सरकार ने यह बात टर्न डाउन कर दी थी, and hence financial assistance to the affected farmers, if any, is not covered under this Scheme. However, in view of the special circumstances of massive and unprecedented cold wave/frost all over the State which has adversely affected the sensitive crops like mustard, the Government of India has been approached again for widening the scope of Calamity Relief Fund norms so as to include compensation for cold wave/ frost affected crops.

In this context, frequent communications and personal meetings have been undertaken by Hon'ble Chief Minister and the Revenue Minister with a view to convincing the Union Agriculture Minister and Union Finance Minister as well as Union Home Minister, for inclusion of Cold Wave in the definition of Natural Calamity.

I would like to make a special mention that the Government of Haryana has brought the crops of Mustard and Gram under National Agricultural Insurance Scheme for the first time during the current Rabi season इससे पहले रबी सीजन को कभी भी इम्भुव नहीं किया गया था। यह तो हमारे को नेशनल इंश्योरैंस स्कीम के तहत लाया गया है whereas this Scheme was limited to only Kharif crops earlier. 73 blocks of 13 districts of the State, namely, Hisar, Fatehabad, Rohtak, Jhajjar, Sonepat, Gurgaon, Faridabad, Sirsa, Bhiwani, Jind, Mahendergarh, Rewari and Mewat are covered under NAIS for Mustard crops. The Scheme is compulsory for loanee farmers and optional for non-loanee farmers. A premium of 2% is payable by the loanee farmers. A subsidy of 10% on the amount of premium is provided by the State Government for small and marginal farmers. Indemnity level is fixed at 80% of the average productivity for the last 5 years in a particular Block. In case, the productivity of the insured crop in a Block falls below the guaranteed yield, all the farmers of the Block will be compensated on pro-rata basis depending upon the loss in productivity below the guaranteed yield. As on date, 48,833 farmers have got their Mustard crop insured NAIS. Hence, many farmers who have suffered losses even due to cold wave would be given financial assistance as per the National Agricultural Insurance Scheme which has been implemented for the first time during the current Rabi season.

As regards the rainfall during March, 2006, it has been reported that the overall impact thereof on Wheat crop has not been adverse. There had been a long dry spell since the beginning of the Rabi season. The sudden and abnormal rise in day temperatures during the second fortnight of February was not congenial for the Wheat crop. The rains in rather March helped in meeting the demand of water for irrigation at the critical stage of grain initiation and also in lowering of

temperatures. Thus, excepting the pockets where rains were accompanied with strong winds, the rainfall, though un-seasonal, has been beneficial for the Wheat crop. In any case, the regular Girdawari of the Rabi crop is going on and it would be completed by 31st March, 2006, and the damage, if any, would be known at that time to assess the extent of damage in order to take a decision to postpone the recovery of Abiana from the affected farmers. However, the State Government has already issued the directions to Cooperative Institutions and District Administration for not resorting to coercive means for recovery of dues.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने डिटेल में जवाब दिया है लेकिन मैं कुछ चीजों के बारे में उनसे पूछना भी चाहूंगा और उनके बारे में सुझाव भी देना चाहूंगा।

Mr. Speaker : Mr. Malik, ask your specific supplementary.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, किसानों को आज भी पसीना आ रहा है क्योंकि आज भी मौसम खराब है। जिन किसानों ने सरसों की अगेती फसल काट ली थी वर्षा में भीगने के कारण वह टोटली खराब हो गई है और जिन लोगों ने अपनी फसल को पानी दे रखा था वह तेज आन्धी और तेज हवाओं से खराब हो गई है जिन किसानों ने अपनी फसल में पानी नहीं दे रखा था उनको तो जरूर फायदा हुआ है ले. न जिन फसलों में पानी दे रखा था वे फसलें गिर गई हैं और उनमें 70-80 प्रतिशत नुकसान हुआ है। यह मैं मानता हूँ कि पाला पड़ने या इस किस्म की आंधी से फसलों का नुकसान कम ही होता है क्योंकि इस किस्म की आपदा कम ही आती है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की आपदा के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड से या प्राईम मिनिस्टर रिलीफ फण्ड से उन किसानों को मुआवजा दिया जा सकता है या नहीं और क्या सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है या नहीं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अपने जवाब में इस बारे में विस्तार से बताया है। हमने इस बारे में सैन्ट्रल गवर्नमेंट से अप्रोच किया है। पिछली सरकार ने भी अप्रोच किया था लेकिन अभी तक ग्राउंड फ्रोस्ट को सैंटर रिलीफ फण्ड के तहत कवर नहीं किया गया है जो मुआवजा दिया जाता है उसमें 75 प्रतिशत पैसा भारत सरकार का होता है और 25 प्रतिशत पैसा स्टेट का होता है। इस बारे में प्लानिंग कमिशन डिसाईड करता है। जहां तक कम्पनसेशन देने की बात है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में केवल 20 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था जबकि हमारी सरकार ने पिछले साल सत्ता में आने के बाद 86 करोड़ रुपया कम्पनसेशन के रूप में किसानों को दिया है। (शोर)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, ओले तो पिछली सरकार के शासन के समय में ही पड़े थे लेकिन उनके लिए किसानों को हुए नुकसान का कम्पनसेशन इस सरकार ने दिया है। हमने कम्पनसेशन को इन्हान्स किया है जितना कम्पनसेशन पिछली सरकार के समय में दिया गया था हमने उससे ज्यादा कम्पनसेशन दिया है।

डा० सीताराम : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बनते ही ओले पड़े थे।

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, please sit down.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के नार्म्ज हैं उनमें एक हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

है। जिन एरियाज में ऐश्योरड इरीगेशन हैं वहां पर 25 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। जो प्रेनियल फसलें हैं उनका 4 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। लेकिन हमारी सरकार ने अपने फण्ड से उस मुआवजे को एनहान्स किया है। जहां पर प्रेनियल फसल 26 से 50 प्रतिशत तक डेमेज हुई हैं उनके लिए जहां भारत सरकार एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देती है वहीं हमारी सरकार ने इन फसलों के लिए 3750 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया है। कहां एक हजार रुपये और कहां 3750 रुपये, इसमें काफी अन्तर है। इसके अलावा दूसरी क्राप्स के लिए जो 27 से 50 प्रतिशत तक खराब हो गई है। उनके लिए हमने 3150 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किया है। कहां एक हजार रुपये और कहां 3150 रुपये। इसके अलावा जो फसल 51 से 75 प्रतिशत तक खराब हो गई है उनके लिए हमने 5650 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा मुख्यमंत्री जो किसानों के बारे में सोचता है पहली बार हरियाणा की सत्ता में आया है। पिछली सरकार में तो किसानों की सिर्फ बातें की जाती थी हमने तो बाकायदा उनको पैसे दिए हैं। दूसरी फसलों के लिए 4600 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी प्रकार जो फसलें 76 से 100 प्रतिशत तक डेमेज होती हैं उनके लिए हमने 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किया है। पिछली सरकार ने ऐसा करने के लिए कभी नहीं सोचा था। अध्यक्ष महोदय, इस महीने में हम गिरदावरी करवा रहे हैं जहां पर जो फसलें जिस हिसाब से भी डेमेज हुई हैं जो रेट मैंने बताए हैं उसी रेट के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जायेगा।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर सर, मैंने जो सप्लीमेंटरी पूछी थी मंत्री जी ने उसका जवाब तो दिया ही नहीं। मंत्री जी ने सारा जवाब विपक्ष के सदस्यों को दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आपकी सैप्लीमेंटरी का जवाब दिया जा चुका है। सदन के नेता ने भी आपकी सैप्लीमेंट्री का जवाब दिया है।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि औलावृष्टि के लिए इतना इस सरकार ने मुआवजा दिया है और पहले के मुकाबले काफी बढ़ाकर दिया है। जो पिछली सरकार के समय ओले पड़े थे उसका भी मुआवजा इस सरकार ने बढ़ाकर दिया है।

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, ओले पिछली सरकार के शासन के समय में पड़े थे।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में 25-25 पैसे किसानों को मुआवजे के रूप में दिए जाते थे। उस समय जो किसान मुआवजा लेने जाता था उसको कहा जाता था कि एक रुपये ले जाओ और 75 पैसे हमें वापिस दे जाओ। अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन के 80 प्रतिशत और शायद इससे भी ज्यादा प्रतिशत सदस्य किसान परिवारों से संबंधित हैं और किसानों की समस्याओं को समझते भी हैं। आप सभी को मालूम है कि सूखा तो पूरे प्रदेश में लगभग एक साथ पड़ता है लेकिन बाढ़, ओले आदि की आपदाएं तो किल्ले टू किल्ले डिफर करती हैं।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, इसी बात को ध्यान में रखकर ही सरकार स्पेशल गिरदावरी

करवा रही है। Malik Sahib, please ask your specific supplementary. You have given calling attention notice. You can put two supplementaries, one you have already asked and what is your second supplementary ?

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं कि क्या सरकार क्राईटेरिया में चेंज करना चाहती है कि किल्ले टू किल्ले और विलेज टू विलेज के हिसाब से गिरदावरी कराई जायेगी और उसी हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि गिरदावरी बाकायदा 31 मार्च तक होनी है। उसमें सरकार ने प्रतिशतता निर्धारित की है कि 26 से 50 प्रतिशत तक जिन फसलों को नुक्सान होगा उनको अलग मुआवजा दिया जायेगा और जिनका ज्यादा नुक्सान होगा उनको अलग मुआवजा दिया जायेगा। भारत सरकार की इस बारे में जो पॉलिसी है उनके यहां ऐसा नहीं है लेकिन जहां ज्यादा नुक्सान हुआ है वहां ज्यादा मुआवजा दिया जायेगा और जहां कम नुक्सान हुआ है वहां कम मुआवजा दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार के नार्म्ज हैं उससे हम 7 प्रतिशत ज्यादा मुआवजा किसानों को देंगे। गिरदावरी में जो डिटेल होगी उसी हिसाब से हम मुआवजा देंगे। अध्यक्ष महोदय, हम विपक्ष के साथियों की तरह से आस्ट्रेलिया में पैसे जमा करवा नहीं जाते बल्कि वहां से पैसे लेकर आते हैं।

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार के नैचुरल कैलेमिटी के नियम अलग हैं। उन नियमों के हिसाब से किसानों को जो रिलीफ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। लेकिन किसानों की फसलों को औलों से, बरसात से नुक्सान हुआ है। कई जगहों पर बरसात से फायदा भी हुआ है इसके अतिरिक्त पाले से भी फसलों को नुक्सान हुआ है। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बजट में एक बात कही है कि (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इंदौरा साहब, बजट की बात बजट पर बोलना you will be given ample time. Please ask your specific supplementary pertaining to the calling attention motion. You are a seasoned parliamentarian. You know each and everything about the Parliament and Vidhan Sabha.

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी ने कहा है कि माप दण्डों में छूट देकर किसानों को मुआवजा दिया जायेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा कि विस मंत्री जी ने कहा है कि माप दण्डों में परिवर्तन करके, अथवा सुधार करके किसानों को किसी न किसी तरह का फायदा दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, किसानों को जो नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई स्टेट बजट में प्रोविजन करके या रूरल डिवैल्पमैंट फंड से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त मार्केटिंग फीस से भी इसकी भरपाई की जा सकती है, सबसिडाइज्ड रेट्स पर किसानों को दवाईयां, खाद आदि देकर भी उनके नुक्सान की भारपाई की जा सकती है अथवा उनको बिजली फ्री दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसानों को कुछ बोनस दे सकते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार किसानों के नुक्सान की भरपाई करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े विस्तार से बता दिया है कि अगर तूफान, फ्लड या बारिश से नुकसान होता है तो उसका मुआवजा देने के लिए गिरदावरी होती है। मैं श्रीमान जी को बताना चाहता हूं कि इनके डिस्ट्रिक्ट सिरसा में डस्ट स्टॉर्म आया । उस वक्त पहले जो नॉर्म्ज थे इन्डिविजुअल बैश में 50 हजार रुपये देते थे मुख्य मन्त्री जी ने उसको बढ़ा कर दो लाख रुपये कर दिया है इसके साथ ही साथ कैमल का चार हजार था वह बढ़ा कर 10 हजार कर दिया, बफैलो और बुल्ल का पांच हजार देते थे वह अब दस हजार कर दिया, बकरी का 300 रुपये देते थे वह बढ़ा कर 2000 कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने हर चीज में मुआवजे की राशि को बढ़ाया है। (विघ्न) श्रीमान जी, अगर कहीं पर नुक्सान होता है तो उसका मुआवजा दिया जाता है और उसके लिए बाकायदा गिरदावरी की जाती है। अगर तूफान से कोई नुकसान हुआ है तो उसके बारे में पूरी बात करेंगे और उसके बाद मुआवजा भी देंगे इनकी तरह से नहीं करेंगे (विघ्न)

Mr. Speaker : Sadhaura Ji, you ask only one supplementary.

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर सर, धन्यवाद। बीमे की योजना का लाभ ब्लॉक लैवल पर खण्ड लैवल पर देना है। अगर कहीं पर 20 या 25% तक नुकसान होता है तो जमींदार को मुआवजा नहीं मिलता है। जैसे कि मलिक साहब ने कहा है कि एक किल्ला छोड़ कर भी औले पड़ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे जमींदारों को मुआवजा देने में इस प्रकार की सुविधा देने की कृपा करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ब्लॉक लैवल पर पूरे पांच साल का ब्यौरा लेते हैं। अगर 20% से ज्यादा नुकसान हो जाता है तो उसमें पूरे ब्लॉक के किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। (विघ्न) जैसे कि आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने बात कही थी कि हम गाँव के लैवल पर इसको लेकर आएंगे लेकिन अभी तक तो इन्श्योरैंस स्कीम का जो क्राईटिरिया है वह ब्लॉक लैवल तक ही है। जिन भी फारमर्ज ने अपनी क्रॉप की इन्श्योरैंस करवा रखी है पूरे ब्लॉक के लोगों को मुआवजा इन्श्योरैंस कम्पनी द्वारा दिया जाएगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने जो कहा है वह सही है कि यह मुआवजा ब्लॉक लैवल का आंका जाता है। हमारा यह प्रयास है और हम इसे मानेंगे भी लेकिन फिलहाल यह बात इन्श्योरैंस कम्पनी के ऊपर है कि ब्लॉक लैवल पर नुक्सान आंका जाना चाहिए। हमारा यह प्रयास रहेगा कि ऐसा किया जाए।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आलू की फसल पर पाले के कारण नुकसान हुए बहुत दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक उस नुकसान की गिरदावरी नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह गिरदावरी क्यों नहीं हुई है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कोल्ड फरोस्ट की वजह से जो नुकसान हुआ है। चाहे वह आलू की फसल में हुआ है या मस्टर्ड में हुआ है उसकी गिरदावरी हम तभी करेंगे जब कोल्ड फरोस्ट नैचुरल कैलेमिटी के दायरे में आता हो। अगर बरसात की वजह से कहीं पर नुकसान हुआ है या आंधी की वजह से नुकसान हुआ है और यदि गेहूं कि फसल का नुकसान हुआ है तो वहां पर हम देखेंगे लेकिन कोल्ड फरोस्ट के मुआवजा

देने की फिलहाल कोई बात नहीं है। अगर सैंटर गवर्नमैंट इसको नैचुरल कैलेमिटी में ले लेती है तो हम इसकी गिरदावरी करवा देंगे अदरवाईज़ गिरदावरी करवाने का कोई फायदा नहीं है। गिरदावरी करवाने का तभी फायदा है जब हम नुकसान का कोई मुआवजा दे सकें।

Mr. Speaker : Ramphal Ji, you are also the signatory to the Calling Attention Motion. You can ask one supplementary.

श्री रामफल चिराना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि फसलों में नुकसान हो ही जाता है। मैं चाहता हूं कि किसान का जो भी नुकसान होता है चाहे वह पाले से होता है या किसी दूसरी तरह से होता है नुकसान तो नुकसान ही है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा प्रावधान करेगी कि किसान की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा उसको दिया जा सके ? अध्यक्ष महोदय, यह तो फसल के नुकसान की बात है साथ ही साथ मैं यह बात भी पूछना चाहूंगा कि क्या केवल कांग्रेस पार्टी के मैम्बर्ज के ही सड़कों के और दूसरे काम होंगे या हमारे काम भी होंगे ?

वर्ष 2006-2007 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members now general discussion on the Budget Estimaties for year 2006-2007 will take place.

श्री अध्यक्ष : मैं आनरेबल मैम्बर साहेबान्ज को यह बताना चाहूंगा कि बजट के ऊपर डिस्कशन आज और कल दो दिन होगी और परसों माननीय वित्तमंत्री जी जवाब देंगे। इस पर बहस करने के लिए सत्तापक्ष, विपक्ष और निर्दलीय सदस्यों के नाम आए हैं। सभी नामों को देखते हुए बजट पर बोलने के लिए समय का बंटवारा किया गया है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा के वे 5 या 7 मिनट में ही अपनी-अपनी बात खत्म करने की कोशिश करें। Now, Sh. Shadi Lal Batra will open the Budget speech.

श्री शादी लाल बत्तरा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, 17 मार्च, 2006 को वर्तमान सरकार का बजट पेश हुआ है। इस सरकार को पिछले दिनों में जो अनुभव हुए थे उनसे सीख लेकर सरकार अपना बजट पेश करती है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार 5 मार्च, 2005 को सत्ता में आई थी और इनसे पहले दूसरी सरकार सत्ता में थी। उस सरकार ने हमें क्या अर्थव्यवस्था दी थी, उस वक्त हरियाणा के क्या हालात थे, हरियाणा की जनता की क्या स्थिति थी, इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने यह बजट तैयार किया है। हरियाणा का विकास कैसे हो और हरियाणा के विकास की रेलगाड़ी किस तरह से पटरी पर तेजी से चले, इस बात को ध्यान में रखकर इस बजट को दूरदर्शिता से बनाया गया है। मैं इस सदन का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहूंगा कि जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो उस वक्त हरियाणा में क्या स्थिति थी। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2001 में हरियाणा पर 13 हजार, 928 करोड़ का कर्जा था और वह कर्जा वर्ष 2005 में बढ़कर 24 हजार 255 करोड़ रुपए हो गया था यानि कि 5 साल में 74 प्रतिशत की कर्जे में इन्क्रीज हो गई थी वर्ष 2001 से वर्ष 2005 तक टोटल क्लटीवेशन का एरिया 38.21 लाख हैक्टेयर था लेकिन बोआई सिर्फ 30 लाख 54 एकड़ पर हुई थी। बाकी का सारा एरिया अन इरिगेटिड रहा । वहां पर कोई फसल नहीं हुई और सिर पर कर्जा चढ़ गया। इस वजह से हालात यह हो गए थे कि हमारा जो भी बजट होता था, उसका 74 प्रतिशत हिस्सा पेमैन्ट आफ इन्ट्रस्ट, पेमैन्ट आफ लोन, पेमैन्ट आफ

[श्री शादी लाल बत्तरा]

सबसिडी और पेमैन्ट आफ पैंशन में चला जाता था। हरियाणा में विकास की गति नहीं थी। उसके बाद हमारी सरकार सत्ता में आई और हमारी मौजूदा सरकार ने आकर अपने निर्णय लिए । उन निर्णयों के मुताबिक आज हम देखते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है। आज हरियाणा का जन जन कह रहा है कि हरियाणा प्रदेश आज विकास की ओर चल रहा है। आज विकास की इतनी स्पीड है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई थी। 1966 में जब हरियाणा बना था उस वक्त हरियाणा के हिस्से में 161 करोड़ रुपए की लॉयबलिटीज आई थी लेकिन आज वह लायबलिटीज बढ़ गई हैं। इतनी ज्यादा लायबलिटीज होने के बावजूद भी यह सरकार विकास की ओर चल रही है और उसके लिए श्रेय इस सरकार की नीतियों को जाता है। मैं तो आज इस सरकार के नेतृत्व को बधाई देता हूं कि इस सरकार ने नीतियां जन जन के हित में बनाई हैं, हरियाणा के विकास के लिए बनाई हैं। यह इस सरकार की अच्छी सोच है और इनकी दूरदर्शिता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की जनता बहुत ही जागरूक और मेहनती है जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी होने के बावजूद भी पर-कैपिटा इन्कम बढ़ गई है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 में पर-कैपिटा इन्कम 16,872 रुपये थी और उससे पहले सिर्फ 15,752 रुपये पर कैपिटा इन्कम थी। हमारे समय में पर कैपिटा इन्कम इन्क्रीज हुई है। यह इस बात को दर्शाता है कि हमारे लोग कितने जागरूक और मेहनती हैं। इस सबके लिए भी मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में काफी इन्डस्ट्री डिवैल्प होने जा रही हैं। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि आज सारे देश में आमदनी के हिसाब से नम्बर एक पर गोवा राज्य है और नम्बर 2 पर हरियाणा प्रदेश है। हरियाणा में इसी तरह से विकास होता रहा तो आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश नम्बर एक पर होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि 12वां फाईनेंस कमीशन आया । इस कमीशन की जो रिकमैंडेशन थीं उनको अपनाते हुए फिसकल डैफिसिट और बजट मैनेजमैन्ट बिल, 2005 में पास हो गया था। जो फिसकल डैफिसिट था इसको घटाने का लक्ष्य रखा गया और यह माना गया कि यह लक्ष्य तीन प्रतिशत तक प्राप्त हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह बजट यह दर्शाता है कि वाकई में वर्ष 2008 तक फिसकल डैफिसिट तीन प्रतिशत तक आ जाएगा। इसी तरह से जो कर्जा था उस पर 13 पर सैंट तक ब्याज दिया जाता था लेकिन इस फाईनैंस कमीशन के आने के बाद अब यह दर कम आ गयी है इससे 200 करोड़ रुपये की बचत सालाना हरियाणा को होने लगेगी। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लीडरान और हमारे नेता की सूझबूझ थी कि उन्होंने ऐसा कर दिया। अब इसके बाद विकास की गति तेज हो गयी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास अगर आपने करना है तो इसके लिए यातायात बिना जाम अच्छा चलना चाहिए, रोडज और ब्रिजिज का अच्छा बनाना भी बहुत जरूरी होता है। अगर रोडज और ब्रिजिज ठीक हैं और यदि हमारी मूवमैन्ट ठीक है तो ऐसा कोई कारण नहीं कि हमारा विकास न हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने 50 प्रतिशत पैसा अपनी तरफ से देकर रेलवे लाईन को बनवाना मंजूर किया है। रिवाड़ी से रोहतक तक की लाईन इसी आधार पर बनने के लिए मंजूर हुई है। इसी तरह से 9 ओवर ब्रिजिज भी बनने हैं। इसी प्रकार 13 ओवर ब्रिजिज कैनाल के पूरे हो चुके हैं। इसके बाद अगर आप सड़कों की तरफ देखें तो नैशनल हाई वे नं0 10 दिल्ली से रोहतक तक चार लेन बनने वाला है। इसी प्रकार से पानीपत में प्रोविलेटिड फ्लाई ओवर बनना है। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि यातायात में रूकावट न हो, लोगों की मूवमैन्ट तेज हो और विकास की गति तेज हो। अगर ऐसा होगा तभी हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रीज लगेंगी और जो दूसरे देशों के

इन्वैस्टर्ज हैं वे यहां पर आकर अपनी इन्वैस्टमैंट कर सकेंगे। अगर ऐसा होगा तभी हरियाणा आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने हरियाणा के लिए 10 एस०ई०जैड मंजूर किए हैं। इनके बनने के बाद यहां पर इम्प्लॉयमैन्ट बहुत बढ़ जाएगी। यहां पर बहुत ज्यादा फॉरन इन्वैस्टमैंट हो जाएगी। इसके बाद हरियाणा की पोजीशन क्या होगी यह देखने वाली चीज है। यहां पर जितनी इन्वैस्टमैंट होगी उससे कहीं ज्यादा इम्प्लायमैंट आएगी क्योंकि हमारी लैंड होल्डिंग छोटी हो चुकी है इसलिए कृषि आज फ्रूटफुल और प्रोफिटेबल नहीं रह गयी है। जब एस०ई०जैड आएंगे तो इनसे हमारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी और उनके कमाई के साधन बढ़ेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारी पोजीशन कुछ और हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जो दस एस०ई०जैड आ रहे हैं यह बहुत बड़े-बड़े जैसे 2500 एकड़ या 1500 एकड़ के एरियाज में आ रहे हैं लेकिन अगर यह छोटे-छोटे एरिया में बनें तो इनसे आम आदमी को ज्यादा फायदा होगा। ऐसा होने से लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी और लोगों के लिए एक तरह से विकास के दरवाजे भी खुलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पावर की कमी की बात आती है। लेकिन पावर की कमी का कारण क्या है ? जब हरियाणा बना था तो उस समय हमारे पास 1600 मेगावाट पावर थी और तब से लेकर 2005 तक हम केवल चार हजार मेगावाट ही बिजली पैदा करते हैं जबकि जरूरत 9 हजार मेगावाट की है। आज हमारी सरकार ने जो इस बारे में एम०ओ०यू० साईन किए हैं वह आदर्श हैं। यमुनानगर, फरीदाबाद, हिसार और प ।।पत के लिए चार हजार मेगावाट पावर के लिए एम०ओ०यू० साईन किये गये हैं। जब यह ए.ई पावर प्लांट बनकर उत्पादन शुरू कर दें तो उस दिन हरियाणा में बिजली सरप्लस हो जाएगी तब हमारा विकास अधिक होगा। हम समझते हैं कि केवल वर्ष 2008 तक ही ऐसी यूनिटस चल जायेंगी जो अभी बिजली की कमी की वजह से नहीं चल पा रही है। उस समय तक बिजली की कमी नहीं रहेगी। बिजली के लिए सरकार ने जो प्रावधान किया है। उसके लिए वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। सरकारी बिजली के उत्पादन से और प्राईवेट बिजली के उत्पादन से हमारी जो बिजली की कमी है वह हम दूर कर पायेंगे। उस वक्त हम समझ पायेंगे कि हरियाणा के वर्तमान नेतृत्व ने ठीक ही ऐसा फैसला लिया है। लेकिन पिछली सरकार ने कुछ ऐसे काम किए कि किसानों और दूसरे गरीब आदमियों को बहका दिया था और कहा था कि पानी और बिजली के बिल न दो। इस वजह से उनके एरियर्स इतने इकट्ठे हो गये कि उससे सरकार की सारी मान्यताएं खत्म होती जा रही थीं। आगे जो विकास की लाईनें थी वह टूट चुकी थी । हमारे नेता ने किसानों के बिजली के बिल्ज के 1600 करोड़ रुपये माफ करने का जो काम किया है उससे यह फायदा हुआ है कि जो किसान प्रदेश के विकास की मुख्य धारा से दूर हट चुके थे वे अब मुख्य धारा में वापिस आ गए हैं। आज वह पोजीशन नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आज वे लोग भी बिजली के बिल दे रहे हैं जो पहले नहीं दिया करते थे। बिजली के बिलों की मुआफी का जो निर्णय लिया गया है यह सरकार के मैनिफेस्टो में नहीं था। इस बारे में जिस पिछली सरकार ने घोषणा की थी उस सरकार ने हरियाणा को पथभ्रष्ट करने के लिए, हरियाणा को दूसरे रास्ते पर लाने के लिए एक चाल चली थी परन्तु वे उस चाल में फेल हो गये। उसके बाद नई चुनी हुई सरकार आ गई और सरकार ने आते ही ऐसा फैसला कर लिया कि किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ कर दिये जायेंगे। इसके अलावा लोक कल्याण के लिए बहुत से फैसले किए गये। किसानों की एक्वायर होने वाली जमीन के जो फ्लौर रेट फिक्स किये गये वह भी एक आईडियल फैसला था। इससे पहले कभी किसानों को इतना ज्यादा अपनी जमीन का फ्लौर रेट नहीं मिला था अब जिस क्षेत्र की जमीन एक्वायर होती हैं। उस क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था क्या है वहां क्या पोजीशन

[श्री शादी लाल बत्तरा]

चल रही है उसी के मुताबिक सरकार की तरफ से किसानों को जमीन के रेट दिए जा रहे हैं। इसके बाद इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का फैसला लिया गया। जब से हरियाणा बना है तब से हरियाणा के कुछ एरियाज ऐसे थे जहां की जमीन प्यासी रही और पिछली किसी सरकार ने उस बात की परवाह नहीं की थी कि कास्त की जमीन को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कुछ एरियाज में पानी जा रहा था लेकिन कुछ एरियाज में बिल्कुल पानी नहीं जा रहा था। सभी ऐरियाज के बराबर पानी देने का फैसला यह सरकार आने के बाद किया गया। सरकार ने यह फैसला किया कि हरियाणा में जो पानी उपलब्ध है उसका समान बंटवारा हो। पानी के समान बंटवारे के कारण ही जिन टेलों पर कभी पानी नहीं पहुंचता था आज वहां पर भी पानी पहुंचने लगा है। वह धरती जो प्यासी थी उसको भी पानी मिलने लगा है। इससे हरियाणा के लोगों को यह महसूस हुआ कि वाकई हम आज स्वतंत्र हरियाणा में रह रहे हैं और हमें आज हरियाणा में आजादी का फल मिला है। आज हरियाणा के लोग कह सकते हैं कि हम हरियाणा के वासी हैं और सम्मानित नागरिक हैं । पानी के समान बंटवारे से किसानों को आत्म सम्मान और खुशहाली मिली है। इसके बाद किसानों की खेती अच्छी हुई है। जिसके कारण उनकी पैदावार भी अच्छी हुई है। इसी का परिणाम यह हुआ है। कि आज हरियाणा की पर कपिटा इन्कम भी बढ़ गई है। इसके अलावा सरकार ने न्यू इण्डस्ट्रियल पोलिसी की घोषणा भी की है। न्यू इण्डस्ट्रियल पोलिसी से यह हुआ है। कि जो हरियाणा में इन्वेस्ट करेगा वह यह सोच समझकर इन्वेस्ट करेगा कि through out the country. Haryana is the only proper place, where he can invest. इससे हमें दूरगामी फायदा मिलेगा। हरियाणा एक प्रगतिशील प्रदेश है यहां पर इन्वेस्टर्ज की इन्वैस्टमैंट हर प्रकार से सेफ रहेगी। इसके बाद बजट में सैक्स रेशों की बात कही गई है। हमारी बालिकाओं को जन्म से पहले ही खत्म किया जाता रहा है। सैक्स रेसों को बराबर लाने के लिए हरियाणा सरकार ने जो स्टैप्स लिए हैं वे काफी सराहनीय हैं। इन सराहना इसलिए भी की जानी चाहिए कि जो पंचायतें 6 से 14 साल की लड़कियों को स्कूल भेजेंगी उनको सरकार की तरफ से इन्सैन्टिव दिया जायेगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से लड़कियों को बस पास के लिए 50 प्रतिशत का ऐडीशनल कन्सैशन भी दिया गया है और टैक्नीकल ऐजूकेशन के लिए 25 प्रतिशत सीटें भी लड़कियों के लिए रिजर्व की गई हैं इसी प्रकार से हाउसिंग बोर्ड द्वारा अलॉट किए जाने वाले फलैट्स में और हुडा द्वारा अलॉट की जाने वाली सोसायटी में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। मैं तो यह कहता हूं कि ऐसी सोसायटीज होनी चाहिए जो सिर्फ महिलाओं की ही हों। सरकार को इस बारे में महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और ऐसा कोई प्रावधान करना चाहिए कि इन सोसायटीज के लिए केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकें। इस प्रकार के काम करने से महिलाओं में उत्साह बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, एस0सी0 के लिए यह कहा गया कि जो उनकी बेटी होगी उनकी शादी के वक्त कन्यादान के रूप में 15,000/- रुपये सरकार की तरफ से दिये जायेंगे और जो दूसरे गरीब हैं उनकी बेटी की शादी के समय 5100/- रुपये कन्यादान के रूप में दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, गरीबी सबके लिए बराबर है। गरीबी की कोई जात नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती। गरीब चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे हरिजन का बेटा हो, सब बराबर हैं। वे अपने साधन नहीं जुटा सकते इसलिए मेरा सरकार से सुझाव है कि किसी भी गरीब की लड़की की शादी हो सभी को बराबर कन्यादान के पैसे दिए जायें। यह नहीं होना चाहिए कि एक लाडली जो किसी गरीब पण्डित के घर पैदा हो गई उसको कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बेटी किसी अमीर हरिजन के घर पैदा हो गई

उसको 15,000/- रुपये दिए जायें। मेरा सुझाव है कि आर्थिक आधार पर यह राशि कन्यादान के रूप में दी जानी चाहिए और जो भी गरीब हैं उन सबकी लाडली की शादी के समय 15,000/- रुपये कन्यादान के रूप में दिए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पावर सैक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा पावर सैक्टर में बहुत एम०ओ०यू० साईन हुए हैं। यह ठीक बात है कि एम०ओ०यू० होने भी चाहिए। लेकिन एम०ओ०यू० केवल बड़ी कंपनियां जो एम०एन०सी० हैं या ऐसी कंपनियां जो अपने यहां बड़ी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस या दूसरी बड़ी कम्पनियां हैं उनके साथ ही साईन होने चाहिए। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो ये नये बड़े-बड़े बिजली के यूनिट लग रहे हैं इनके साथ-साथ 2-4 या 6 मेगावाट के छोटे-छोटे यूनिट्स भी लगाये जायेंगे तो अच्छा होगा और इन्हें आम आदमी भी लगा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि हरियाणा सरकार ठीक समझे कि आने वाले समय में हरियाणा में बिजली का उत्पादन बढ़े इसका हक उन आम आदमियों को दिया जाना चाहिए जो 2-4 या 6 मेगावाट के यूनिट्स लगाने के लिए तैयार हैं ऐसा करने से यह फायदा होगा कि आम जनता को काम मिलेगा और प्रदेश को ज्यादा बिजली मिलेगी। इसके द्वारा सोशलिज्म की पॉलिसी का हम अनुसरण करेंगे। हमें सोशलिज्म से हटकर कम्पलीट कैपीटलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए ताकि कहीं ऐसा न हो कि जो आदमी अमीर हैं वे और अमीर हो जायें और जो गरीब हैं वे और गरीब हो जायें। हमें सबकी समानता को देखना है और सबको समान अधिकार देने हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिजली उत्पादन के जो बड़े यूनिट्स 1000, 800 और 400 मेगावाट के लगने हैं उनका एम०ओ०यू० बड़ी कंपनियों के साथ साईन करें और साथ में छोटे यूनिट लगाने की परमिशन भी आम आदमियों को दी जाये क्योंकि बिजली उत्पादन के छोटे यूनिट लगने से सरकार को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। (इस समय सभापतियों की सूची में से माननीय सदस्य श्री आनंद सिंह डांगी पदासीन हुए) सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा। किसी भी देश की, प्रदेश की प्रगति तभी हो सकती है। जब वहां का नागरिक एजूकेटिड हो। वहां के नागरिक की सोच हो कि विकास कैसे होना चाहिए। आज हम मेन शिक्षा नीति से थोड़ा दूर चले गये हैं। अगर मैं पिछली सरकार के समय का जिक्र करूं तो जो ऐडिड स्कूल और कालेजिज हैं उनमें क्या हो रहा था कि अगर एक सबजैक्ट में एक टीचर लगा हुआ है और वह टीचर रिटायर हो गया या किसी की डैथ हो गई तो उसके बाद वह पोस्ट भरी नहीं जाती थी। उस पोस्ट के बारे में पिछली सरकार कहती थी कि आप अपने खर्च पर भरें और जो टीचर लग जाते थे उनको कंट्रैक्ट बेसिज पर तनख्वाह दी जाती थी जो कि टीचर्स की एक्सप्लोयटेशन थी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्कूल-कालेज थे जो अपने खर्चे पर टीचर नहीं लगा सकते थे और जिस सबजैक्ट का टीचर वहां से रिटायर हो जाता तो उसकी डैथ हो जाती थी वहां पर उस सबजैक्ट की पढ़ाई नहीं होती थी। जिसका सीधा नुक्सान बच्चों को होता था। हमारी सरकार आने के बाद जो इस तरह की पोस्टें खाली पड़ी थी उनमें से 50 प्रतिशत पोस्टें भरने की आज्ञा सरकार ने दे दी है। इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि 50 प्रतिशत भरने से काम नहीं चलेगा। अगर किसी एक स्कूल या कालेज में अलग-अलग सबजैक्ट की 9 पोस्टें खाली पड़ी हैं तो 9 में से 5 या 4 पोस्टें भर दें तो उससे बात नहीं बनेगी। इस बारे में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा के मामले में सरकार उदारता दिखाये। सभापति महोदय, सरकार ने उदारता दिखाई है। पहले ही हमारी सरकार ने 13.84 प्रतिशत बजट शिक्षा के लिए दिया है लेकिन इसमें थोड़ी उदारता और करने की आवश्यकता है। जो ऐडिड स्कूल और कॉलेज हैं, जो सरकार के

[श्री शादी लाल बत्तरा]

स्टैंडर्ड के अनुसार कार्य कर रहे हैं और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं उनको पूरी पोस्टें देनी चाहिएं तथा सरकार उन पर अपना कंट्रोल और मजबूत कर दे ताकि जो टीचर लगें उनको पूरी तनख्वाह मिले और उनका परोपर यूज हो, मिस यूज न हो।

सभापति महोदय, एक बात और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है। प्राईवेट कॉलेजिज बहुत आ रहे हैं और आम गरीब आदमी की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैडिकल ऐजुकेशन, इन्जीनियरिंग ऐजुकेशन अपने बच्चों को दिला सके। अगर वह टेक्नीकल ऐजुकेशन या मैडिकल ऐजुकेशन अपने बच्चों को दिलवाना चाहता हूं तो उस पर लाखों रुपये लगते हैं। आज हरियाणा के किसान या गरीब व्यक्ति की इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी फाईनैंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वह शिक्षा पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर सके। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का इकलौता मैडिकल कॉलेज रोहतक में है और इस इकलौते मैडिकल कॉलेज, रोहतक में केवल 100 सीटें हैं । इन सीटों से हरियाणा का काम कब तक चलता रहेगा। क्या इन सीटों की संख्या बढ़ाने की बात हम कर सकते हैं ? क्या इन 100 सीटों से हरियाणा प्रान्त की डॉक्टरों की आवश्यकता पूरी होती है? सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा बहुत जरूरी है। आज के टाईम में जिसको उच्च शिक्षा नहीं मिलेगी वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। यह मैडिकल ऐजुकेशन की कमी आगे प्रदेश में बड़ा नुकसान करेगी। हम हैल्थ सर्विसिज के लिए डॉक्टरज कहां से लाएंगे। इसका एक समाधान है कि या तो मैडिकल कॉलेज, रोहतक में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए या प्राईवेट कॉलेज खोले जाएं। जो प्राईवेट कॉलेजिज एम0बी0बी0एस0 या डैंटल कॉलेजिज खोले गए हैं या इन्जीनियरिंग कॉलेजिज खोले गए हैं उन पर पूरा अंकुश लगाएं ताकि आम गरीब आदमी के बच्चे उसमें एडमिशन ले सकें। ऐडमिशन लेने के बाद पढ़ाई करके डिग्री लेने के बाद वे बच्चे देश और प्रदेश की सेवा कर सकें। आज हम कह सकते हैं कि जो प्राईवेट कॉलेजिज हैं गवर्नमैंट उनको ऐड नहीं देती । गवर्नमैंट उनको ऐड न भी दे लेकिन यह भी जरूर देखे कि वे लोग कितना पैसा बना रहे हैं। क्या यह शिक्षा का क्षेत्र सिर्फ पैसा कमाने का क्षेत्र है। सभापति महोदय, शिक्षा का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है, अगर डैडिकेशन या डिवोशन खत्म हो जाती है। तो पैसा चाहे कितना भी कमा लें बात नहीं बनती है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगना भी बहुत जरूरी है।जब तक हम इस पर अंकुश नहीं लगाते तब तक हमारे शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आने वाले टाईम में शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा में जहां प्राईवेट कॉलेजों पर अंकुश लगाना आवश्यक है वहीं सरकार अपनी तरफ से इन कॉलेजों में भी बढ़ौतरी करे। सभापति महोदय, आज एक बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है। किसी भी सरकारी स्कूल में जाएं तो वहां पर जो टीचर्ज होते हैं उससे बहुत कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। हमें इसके बारे में गम्भीरता से सोचना होगा कि आज हमारे प्रदेश की जनता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजती है, सरकारी स्कूलों में बच्चों को न भेजने की क्या सोच है। इसका कारण यह है कि वे सोचते हैं कि अगर बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो वहां पर अच्छी पढ़ाई नहीं होती। यहां तक कि उन स्कूलों में जो टीचर्ज लगे हुए हैं वे भी अपने बच्चों को वहां पर नहीं पढ़ाते हैं। एक स्कूल में मैं खुद चला गया और वहां पर लगी हुई टीचर से मैंने पूछा कि बहिन जी, आपका बेटा कहां पर पढ़ता है तो उसने जवाब दिया कि मेरा बेटा फलां स्कूल में जाता है। मैंने पूछा कि आप अपने बेटे को यहां पर क्यों नहीं पढ़ाते तो उसने जवाब दिया कि यहां पर पढ़ाई ठीक नहीं होती है। सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि आज हमें स्कूलों में ऐसा वातावरण भी देना होगा कि ताकि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में भेजें।

स्कूलों के वे बच्चे जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने आते हैं उनकी संख्या में दिन-ब-दिन कमी होती जा रही है जो कि चिन्ता का विषय है। हम ऐसी नीति बनाएं कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में वापिस आएं। उन स्कूलों को हम ऐसे चलाएं कि वाकेय ही वे आईडियल स्कूल हों आदर्श स्कूल हों। स्कूलों में सरकार को आदर्शवाद शुरू करना होगा और उसके लिए भी हमें सोचना होगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जो इरिगेशन के लिए हमने स्कीमें बनाई हैं वे स्कीमें ठीक हैं। इरिगेशन के पानी का समान बंटवारा हो गया है यह बहुत ही अच्छी बात है। प्रदेश का हर नागरिक इसको ऐप्रिशियेट कर रहा है, इसकी सराहना कर रहा है। लेकिन इसके आगे कुछ और भी है। सभापति महोदय, जैसे सरकार की सोच है कि यमुना का जो पानी सरप्लस बह जाता है अगर उस पर हम अपना कण्ट्रोल कर लें, तो उससे हमारी सिंचाई में फायदा हो सकता है। हालांकि यह मामला अभी विचाराधीन है। मेरा अनुरोध है कि यह मामला जो विचाराधीन है इसको शीघ्र पूरा किया जाए और जो डैम बनने हैं जल्दी से जल्दी बनाए जाएं। एक एम०टी०एल० बुटाना नहर है जो शुरू हो चुकी है और यह नहर 259 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी। जब वह नहर पूरी हो जाएगी तो उससे समान बंटवारे के लिए हम पानी ले सकेंगे। उस क्षेत्र की धरती बिल्कुल प्यासी है और उसको उसके क्षेत्र के हक का पानी नहीं मिल रहा। उसके बारे में भी सरकार सोचे कि यह भी हरियाणा का ही एक अंग है और यहां पर भी विकास होना चाहिए। अब वहां पर विकास हो भी रहा है। विकास तब होता है। जब धरती को पानी मिले और काम करने वाले को कुछ सुविधा मिले। सभापति महोदय, उसके बाद अगर हम देखें कि हमारी रोड़ इतनी बन रही हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट में आज प्रतिदिन 11 लाख लोग सफर करते हैं। (विघ्न) सभापति महोदय, आज हरियाणा में 11 लाख व्यक्ति प्रतिदिन हरियाणा की बसों में यात्रा करते हैं इसके लिए यह जरूरी है कि राज्य में बसों की सुविधा हो। डीलक्स बसें हों ए०सी० बसें हो या सी०एन०जी० बसिज हों जिससे प्रदूषण न फैले और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले यह सरकार की सोच है। सरकार ने ट्रांसपोर्ट के लिए 78 करोड़ रुपये का बजट ऐलोकेट किया है। इसके लिए मैं अपने नेता को और हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने यह सोचा है कि हरियाणावासियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें। इसके साथ ही जो सड़कें हैं उनको भी मजबूत किया जा रहा है। जिससे यातायात अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो रहा है। मैं इसके लिए भी सरकार को बधाई देता हूं। आज हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां हम यह सोच रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कौन हो। इस बारे में आम आदमी क्या कहता है। मैं अपने नेता के लिए उनकी सोच क्या है उनकी क्या बातें हैं और वे कितनी दूरदर्शिता के हैं इस बारे में चन्द लाईनों में कह रहा हूं कि--

हमने जो भी चाहा वह पाया है, जो भी सोचा करके दिखाया है,
अब चलें अपने रास्तों की ओर, बढ़े चलो विकास की ओर,
देखी सारी दुनिया ने अपनी अदा, जीते हैं जीतेंगे हर मंजिल सदा,
हमें कोई रोके नहीं, किसी में न है दम, बढ़ते रहेंगे हमारे कदम,
आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे, चाहे हो आंधी या तूफान ।
इस पावन धरती पर छोड़ेंगे पांव के निशान, मेहनत से यह रास्ता बनाया है,
हमने सदा ही जो सोचा है वह पाया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं हरियाणा के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को मुबाकरबाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में यह सरकार प्रगति की ओर चल रही है, उसको आज हरियाणा के जन-जन

[श्री शादी लाल बत्तरा]
से सरहाना मिल रही है। आज हरियाणा की जनता मानती है कि उन्होंने अब की बार अच्छी सरकार चुनी है। और जो आशाएं इस सरकार से उन्होंने लगाई थीं, वे पूरी हुई हैं। इस सरकार ने जो घोषणाएं की थीं वे सब पूरी करी हैं। सभापति महोदय, सरकार ने जो घोषणाएं की थीं उनको पूरा करके हम उससे काफी आगे चले गए हैं। जैसी सरकार हरियाणा की जनता चाहती थी वैसी ही सरकार आज हरियाणा में है। यह सरकार जो मिसाल हरियाणा में छोड़ रही है वह मिसाल सारे देश में जाएगी और सारा देश भी यही कहेगा कि हमारा नेता और हमारी सरकार हरियाणा की आज की सरकार की तरह हो और हमारा नेता आज के नेता जैसा हो। इन शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : सभापति महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। उसका क्या हुआ है ?

श्री सभापति : मक्कड़ साहब, वह समय चला गया है। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। अब धर्मपाल मलिक जी बोलेंगे।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : माननीय सभापति महोदय, वित्तमंत्री जी द्वारा साल 2006-07 का जो बजट सदन में पेश किया गया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब बजट सैशन शुरू होना होता है तो प्रदेश वासियों के मन में एक आशा जागती है। (विघ्न)

श्री सभापति : सुशील इन्दौरा जी, स्ट्रैंथ के हिसाब से आपका जब नम्बर आएगा तो आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। अभी आप बैठ जाएं। मेरे पास आप सबके नाम आए हुए हैं। जब जब जिसका नम्बर आएगा उसको बोलने का मौका दिया जाएगा। अब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न) इन्दौरा जी, आपकी तो आदत हो गई है, कोई भी सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो आपने बीच में जरूर बोलना है। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न)

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : सभापति महोदय, मैं इन्दौरा जी को कहना चाहूंगा कि हर बात कहने का मौका होता है। ये अपनी बात जीरो ऑवर में कहें। जब कोई दूसरा सदस्य बोल रहा हो तो ये बीच में खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। सभापति जी, इनका तो यह बिल्कुल आऊट आफ आर्डर सिस्टम है। (विघ्न) इन्दौरा जी, जब सदन में आऊट आफ आर्डर कोई बात चल रही हो और हाऊस को इन आर्डर लाना हो तब प्वायंट आफ आर्डर होता है। सभापति महोदय, मैं यह बात कह रहा था कि जब भी कोई बजट पेश होने की बात होती है तो प्रदेशवासियों को काफी घबराहट होती है। कि पता नहीं कैसा बजट होगा, किस किस्म के उसमें कितने टैक्स लगेंगे। लेकिन मैं कहता हूं और मेरे ख्याल में यह पहला बजट है जिसमें कोई विशेष टैक्स नहीं लगाया गया है। मामूली सा पांच पैसे पर किलोमीटर रोडवेज का भाड़ा बढ़ाने की बात इसमें जरूर आई है। बाकी बिल्कुल टैक्स फ्री बजट है। एक सीधे साधे आदमी का जैसा बजट होता है बिल्कुल वैसा ही स्टेट का बजट पेश किया गया है। इसके अलावा मैं सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को और वित्तमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बजट में प्रदेश का और प्रदेश की जनता का पूरा ध्यान रखा है। बजट प्रस्ताव सरकार की मंशा का आईना होता है कि यह सरकार क्या करना चाहती है। सरकार के बजट में इस बात का संकेत दिया गया है कि हरियाणा की जनता की

आशाओं के मुताबिक, उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक यह सरकार चलेगी। बहुत लम्बे अर्से के बाद हरियाणा की जनता ने सुख की सांस ली है। आज लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई है। मैं केवल इतनी बात इस सम्बन्ध में कहूंगा कि इस बजट में कुल 11.56 करोड़ रुपए का घाटा है जो कि बहुत ही मामूली सा है। इस सारे बजट को इस ढंग से मैनेज किया गया है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिलें और लोगों पर किसी प्रकार का अतिरिक्त भार न पड़े। मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार बजट में घाटे पूरा करने के लिए जो कानूनी लूपहोल्ज़ हैं उन को पाट करके उस घाटे को पूरा करेगी या जो टैक्स में चोरी होती है उस को बंद करके इस घाटे को पूरा करेगी। तो सरकार इसके लिए बहुत ही बधाई की पात्र है क्योंकि यह जरूरी नहीं कि हर नये साल में हम टैक्स लगाकर घाटा पूरा कर दें। आलरैडी जो टैक्स लगाये हुए हैं उनकी रिकवरी ठीक करना और बीच में जो कानूनी लूपहोल्ज हैं उनको भरना हम सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। मैं मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी को मुबारिकबाद देता हूं कि इस बजट के अंदर विकास कार्यों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। बजट का करीब आधा हिस्सा केवल सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करने की बात इसमें कही गयी है। यह एक बहुत ही अनप्रैसीडैंटेड बात बजट में है कि सामाजिक सुरक्षा पर इतना जबरदस्त ध्यान दिया गया है क्योंकि 1568.92 करोड़ रुपया सामाजिक सुरक्षा के लिए दिया गया है। इसमें 7.54 परसैंट पैसा प्लान के लिए और बाकी पैसा नोन प्लान के लिए है। तकरीबन आधा पैसा प्लान के लिए है। इसी तरह से बजट में इंफ्रास्टक्चर जैसे बिजली, सिंचाई, सड़क और ट्रांसपोर्ट के लिए 12.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से प्लान के लिए 33.88 परसैंट का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से कैपीटल असैट्स को मजबूत करने के लिए पहले साल के मुकाबले 94.58 करोड़ रुपया ज्यादा उपलब्ध करवाया गया है। कैपीटल असैट्स हमारा जरूरी है इसलिए इसको मजबूत किया ही जाना चाहिए क्योंकि वही हमारी धरोहर है और उसी से हमारा सारा सिस्टम चलना है एवं प्रदेश की आर्थिक दशा सुधारनी है। इसी प्रकार से लोकल एरिया डिवल्पमैंट टैक्स में पंचायती राज इंस्टीच्यूशंज को 257.24 करोड़ रुपये, अर्बन म्यूनिसिपल कमेटी को 157.84 करोड़ रुपये बजट में दिये गये हैं। इसके साथ ही साथ मैं सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं। कि हमारी इस सरकार को केन्द्र सरकार से 57.77 करोड़ रुपयों की सहायता जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत मिली है। यह पैसा फरीदाबाद की डिवैल्पमैंट के लिए है। सरकार यह भी प्रयास कर रही है। कि इसी प्रकार से जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत ही हमारा जो एन०सी०आर० का एरिया है इसमें जितने भी हमारे शहर पड़ते हैं प्लस पंचकूला का जो एरिया है इनके डिवैल्पमैंट के लिए भी केन्द्र सरकार से सहायता मिले। इस बारे में सरकार ने, वित्त मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि इसके लिए पूरे ढंग से वे प्रयत्नशील हैं। उन्होंने इसका रीजन भी दिया है। कि जिस तरह की स्थिति फरीदाबाद की है वैसी ही स्थिति जो हमारे एन०सी०आर० के शहर या पंचकूला हैं, उनकी भी है और हम उम्मीद करते हैं कि केन्द्र सरकार इस बारे में हमें बड़ा भारी योगदान देगी और वहां से हमें पूरी सहायता मिलेगी। इससे एन०सी०आर० से एरियाज में पंचकूला के एरिया में बड़ी भारी डिवैल्पमैंट होगी। सभापति महोदय, मैं डिपार्टमैंटवाइज कुछ बातें कहना चाहता हूं क्योंकि हमारा देश भी कृषि प्रधान है और प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी है। अगर जमीन अच्छी है लेकिन पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राजस्थान के पास बहुत जमीन है लेकिन पानी नहीं। जमीन तो चाहे थोड़ी हो लेकिन अगर पानी मिले और पानी अगर बढ़िया हो तो बड़ा भारी फायदा रहता है। इस बारे में चूंकि

[चौ० धर्मपाल सिंह मलिक]

सदन के सभी साथियों ने कहा है लेकिन मैं फिर यह बात कहना चाहता हूं कि हम न्याय की बात करते हैं। हम कहते रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि हमें पंजाब से पानी नहीं मिल रहा है। क्योंकि एस०वाई०एल० कैनाल की कंस्ट्रक्शन बंद है। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे यहां ही अन्याय हो और जब हम खुद अपने लोगों को पानी नहीं दे सकें तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं? जब हमारे प्रदेश का राजा हमारे प्रदेश के लोगों को न्याय न दे सके तो हम दूसरे प्रदेशों से कैसे न्याय मांग सकते हैं। सभापति महोदय, पचास साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि समानता के 16.00 बजे आधार पर पानी के बंटवारे की बात कही गई है। मेरे ख्याल से कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि इसमें कोई नाजायज बात कही गई है। इसका नतीजा आप देख सकते हैं और आप खुद अन्दाजा लगाईए। डा० साहब बहुत गहराई से सोचने की बात है अगर आप इसके डेटाज देखें तो आप पायेंगे कि 70 प्रतिशत हरियाणा को तो 30 प्रतिशत पानी मिले और 30 प्रतिशत हरियाणा को 70 प्रतिशत पानी मिले। यह क्या अन्याय की बात नहीं है ? श्री सम्पत सिंह जी ने कल अपने इन्टरव्यू में इस बारे में कहा और एक डेढ़ महीने पहले अजय सिंह चौटाला ने भी गोहाना में जाकर हमारी छाती पर बैठकर इस बारे में कह दिया कि अगर न्यायोचित पानी के बंटवारे की बात कही गई और अगर पानी का समान बंटवारा हो गया तो हरियाणा में गृह युद्ध हो जायेगा। अगर न्याय लेने के लिए गृह युद्ध होगा तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम तो लाठियों और तलवारों से गृह युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हम तो न्याय लेकर रहेंगे इसको किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। 50 साल तक हम बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। इस मामले में मैं कहना चाहता हूं कि आप डिटेल देख लीजिए। पानी के बंटवारे के लिए तीन सिस्टम हरियाणा में हैं एक तो भाखड़ा वाटर सप्लाई, दूसरा यमुना वाटर यूनिट और तीसरा लिफ्ट कैनाल सिस्टम । भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और गुड़गांव को एक हजार एकड़ पर 4.29 क्यूसिक से लेकर 9.0 क्यूसिक्स तक पानी मिलता है और जो हमारे पूर्वी इलाके हैं उनको यमुना सर्विसिज से केवल 2.4 से 3.1 प्रतिशत पानी मिलता है। जिसके कारण उनकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हमारे इलाके में 42 दिन के बाद 8 दिन ही नहरों में पानी आता था लेकिन सिरसा के इलाके में 40 दिन में से 16 से 24 दिन तक नहरों में पानी आता था। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से यह एक न्यायोचित कदम उठाया गया है। इस बात के लिए तो विपक्ष के सदस्यों को भी सरकार को बधाई देनी चाहिए क्योंकि राजा तो सारी स्टेट का होता है एक गांव या एक जिले का नहीं होता उसको तो सारी स्टेट का सिस्टम देखना होता है। इसके साथ पता नहीं पंजाब से क्या बात हुई। पंजाब ने यह कहा कि हम एक बूंद पानी हरियाणा में नहीं जाने देंगे, भई, मेरे घर का पानी मेरे हक का पानी है इसमें पंजाब का क्या लेना देना है ? पंजाब के साथ जो झगड़ा है वह पानी के लिए थोड़े ही है पानी में उनका हक नहीं है बल्कि उनके साथ तो नहर की कंस्ट्रक्शन का झगड़ा है और इसके लिए ही हम उनसे बात करते हैं। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि जो एस०वाई०एल० कैनाल की खुदाई का राजनीतिक डिसीजन हुआ है। डेढ़ महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई बी०एम०एल०, हांसी और बुटाना मल्टीपरपज नहर बनाने के लिए आधारशिला रखी है जिसके लिए 259 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। यह नहर लिंक नहर का काम करेगी और इससे 2000 क्यूसिक पानी और आयेगा। इसके बाद सारे हरियाणा को बराबर का नहर का पानी मिलेगा और सभी लोगों को इसके लिए सुविधा हो जायेगी। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारे तीन डैम किसाऊ, रेणुका और लखवार ब्यास डैम बनाने के बारे में वित्त मंत्री

जी ने बजट में जिक्र किया है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीनों डैम्ज को हमें प्राथमिकता ले लेना चाहिए क्योंकि इन तीन डैम्ज के बनने के बाद यमुना का जो पानी बरसात के दिनों में वेस्ट चला जाता है या फल्ड में चला जाता है जिसके कारण उस पानी का भी इस्तेमाल हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते, हम उस पानी का ठीक से प्रयोग कर पायेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि इसके लिए कोई रिजर्वायर बनाया जाए ताकि हम उस पानी का प्रोपर इस्तेमाल कर सकें। पौंग डैम का प्रोजैक्ट बहुत पुराना पड़ा है मेरे ख्याल से 30-35 साल पुराना पौंग डैम का प्रोजैक्ट है। इस के बारे में इरीगेशन मंत्री जी आगे आयें। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पानी के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाये ताकि इस पानी का बराबर इस्तेमाल हो सके। पौंग डैम प्रोजैक्ट 30-35 साल पुराना पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप वाईड अप करें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं। आपने 3:50 पर बोलना शुरू किया था रिकार्ड की बात है।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जिले और हल्के की कुछ बातें और कहनी हैं उसके लिए मुझे थोड़ा समय और दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2006 बालिका वर्ष के रूप में मनाया जायेगा इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं । आज के दिन लिंग अनुपात की समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने इस वर्ष को बालिका वर्ष घोषित करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, इससे लिंग अनुपात में समानता आयेगी और इस समस्या का समाधान भी होगा। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। हमारी सरकार ने किसानों के ऋण पर ब्याज दर में जो कमी की है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और किसानों का हौसला भी बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं एक-दो सुझाव भी देना चाहता हूं कि जैसा पूरे सदन ने एक जुबान से, एक मत होकर चण्डीगढ़ में अपना अलग हाई कोर्ट होने का बिल पास किया है उसी की तर्ज पर पानी को नैशनल असैट् घोषित करने का बिल पास करें ताकि हमारे पानी के सारे झगड़े ही खत्म हो जायें। आप सभी को मालूम है कि एस०वाई०एल० के पानी का झगड़ा लम्बे समय से चला आ रहा है और अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। कोई न कोई रोड़ा अटकाना बहुत आसान है लेकिन उसका हल निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम सभी को एक मत होकर पानी को नैशनल असैट् घोषित करवाना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अनएथोराइज्ड कालोनियों की बात करना चाहूंगा। अनएथोराइज्ड कालोनियां दिन ब दिन हरियाणा प्रदेश में बहुत डिवैल्प हो रही हैं। अनएथोराइज्ड कालोनियां बनने के 20 साल बाद कह दिया जाता है कि उनको तोड़ दिया जाये। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी जिस समय अनएथोराइज्ड कालोनियां बन रही होती हैं उस समय सोये रहते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो जो हालात आज दिल्ली में हो रहे हैं वैसे ही हालात हमारे यहां हो जायेंगे। आज के दिन हरियाणा प्रदेश के शहरों में बिहार, यू०पी० आदि प्रदेशों से बहुत से लोग आकर बस रहे हैं। हमारे यहां के गांवों के युवक भी शहरों में आकर रहना पसंद करते हैं जिसके कारण शहरों की आबादी दिन ब दिन बहुत बढ़ रही है। जिस किसी को नौकरी मिल जाती है वह शहरों में रहना ही पसंद

[चौ० धर्मपाल सिंह मलिक]

करता है। इसका एक कारण तो यह है कि शहरों में गांवों के मुकाबले सुविधाएं बहुत अधिक हैं। हमारे जो टीचर लगते हैं या दूसरे सरकारी कर्मचारी जिनकी पोस्टिंग गांवों में होती है, वे भी वहां रहना पसंद नहीं करते । इसका एक कारण यह है कि गांवों में नौकरी करने वाले कर्मचारी को हाऊस रेंट शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों के मुकाबले कम मिलता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि गांव में जो टीचर पोस्टिड हो उनको और दूसरे कर्मचारियों को शहर के मुकाबले हाऊस रेंट अलाउंस या दूसरे अलाउंस ज्यादा दिये जायें ताकि वे लोग वहां पर रहें । शहरों में हाऊस रैंट अधिक देने की पॉलिसी बहुत पुरानी बनी हुई है। यह पॉलीसी जिस किसी ने भी बनाई होगी उसका रूझान शहरों की तरफ रहा होगा। इसलिए इस पॉलिसी को अब चेंज किया जाये। ऐसा होने पर जो शहरों में दिनों-दिन आबादी बढ़ रही है। उसमें भी कमी आयेगी। इसके अतिरिक्त मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम लोग सारा साल सिवाय ट्रांसफर करवाने के और कोई काम नहीं करते। सारा साल ट्रांसफर करवाने की लाईनें लगी रहती हैं और चुनाव के समय जब हम जनता से वोट मांगने जाते हैं तो लोग यह नहीं पूछते कि हमने किस-किस का ट्रांसफर करवाया। उस समय लोग विकास के बारे में पूछते हैं कि हमने कितना विकास करवाया। इसलिए मैं चाहता हूं कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाये। एजूकेशन विभाग के ट्रांसफर सबसे ज्यादा होते हैं इसलिए एजूकेशन विभाग की ट्रांसफर पॉलीसी तो अवश्य बनाई जाये। अध्यक्ष महोदय, अभी बत्तरा साहब, जिक्र कर रहे थे कि देहातों के स्कूलों में टीचर नहीं मिलते। मैं अपने हल्के के गांव शामड़ी के स्कूल में गया था। मैंने वहां उस स्कूल का रिजल्ट पूछा तो मुझे बताया गया कि स्कूल का रिजल्ट जीरो प्रतिशत था। मेरे पूछने पर बताया गया कि यह रिजल्ट जीरो प्रतिशत इसलिए रहा क्योंकि स्कूल में एक ही मास्टर है। अध्यक्ष महोदय, जब तक हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर और टीचर पूरे नहीं होंगे। तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। जो हमारे मौजूदा स्कूल हैं उनमें जब तक हम इन्फ्रास्टक्चर और टीचर पूरे नहीं कर देते तब तक हमें और स्कूल अपग्रेड नहीं करने चाहिएं। शायद कुछ देर बाद में ही कह दूं कि मेरे हल्के में फलाना स्कूल अपग्रेड किया जाये। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं गया था और बाईचांस मैंने वहां पर कुछ इण्डियन स्टूडैंटस से पूछ लिया कि आप बताइये कि आपकी एजुकेशन का क्या हाल है तो उन्होंने बताया कि प्राईमरी ऐजुकेशन तो हम सब को देना चाहते हैं लेकिन हायर एजुकेशन केवल उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जो उसके काबिल हों क्योंकि हायर ऐजुकेशन पर खर्च बहुत आता है। वहां पर आसानी से स्कूल अपग्रेड नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहता हूं इससे कुछ नाराजगी भी लोगों में होगी लेकिन लोगों को ठीक रास्ता दिखाना और न्याय दिलाना हमारी ड्यूटी है। मेरा यह सुझाव है और सरकार इस बात पर गौर करे।

Mr. Speaker: Malik Sahib, please conclude because other Hon'ble members also have to speak.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करके जल्दी ही कन्क्लूड कर दूंगा। मैं एक बात और कहता हूं कि जो देहात के मकान हैं उनका कोई नक्शा नहीं है और न ही उनके मालिक का कोई सबूत है। मैं वकील भी हूं और इस प्रकार के कई मामले मेरे नोटिस में आए हैं और सबूत न होने के कारण लिटिगेशन होती है। मकान में रहने वालों के पास किसी प्रकार का

कोई सबूत नहीं होता और वे कहते हैं कि जबरदस्ती निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर टाईम बाउंड प्रोग्राम दे कर एक महीने के अन्दर तमाम हरियाणा के गांवों के नक्शे तैयार होने चाहिएं। कौन किस मकान में बैठा है कौन किस मकान का मालिक है यह तय कर देना चाहिए। ऐसा कर देने से लिटिगेशन भी कम होगी और लोगों के अन्दर भाईचारा भी बढ़ेगा तथा वहां पर रहने वाले लोगों में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि कहीं न कहीं हमारा मकान भी है। वे लोग किसी की जमानत तक नहीं दे सकते हैं। शहर में किसी का अगर दस गज का प्लॉट भी है तो वह जमानत दे सकता है लेकिन देहात में जिसके एक हजार गज जमीन है वह किसी की जमानत नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास मालिक होने का कोई सबूत नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि उनको बाकायदा मालिक बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं मुरथल इन्जीनियरिंग कॉलेज की बात कहना चाहता हूं क्योंकि इसके लिए बहुत से लोग मेरे पास आए थे। इन्जीनियरिंग कॉलेज के स्टुडैंटस आए थे, टीचर्ज तथा नॉन टैक्नीकल स्टाफ के लोग भी आए थे। हरियाणा में एक इन्जीनियरिंग कॉलेज है और वह सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। इस कॉलेज को किसी प्राईवेट संस्था को देने की चर्चा सुनने में आ रही है मेरी गुजारिश यह है कि यदि ऐसा किया जाता है तो भविष्य का ख्याल रखते हुए उसके ऊपर डिसीजन लिया जाए और स्टुडैंटस टीचर्ज तथा स्टाफ का भी इसमें पूरा ख्याल रखा जाए।

Mr. Speaker : Malik Sahib, now you please conclude. 3 बज कर 50 मिनट पर आपने बोलना शुरू किया था और आपको बोलते हुए 22-23 मिनट हो गए हैं दूसरे ऑनरेबल मैम्बर्ज ने भी बजट पर बोलना है इसलिए अब आप कन्कलूड करें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कांस्टीच्यूएंसी की दो तीन बातें कहना चाहता हूं। माननीय बहिन जी बैठी हुई हैं मैं इनके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। सांप काटने, कुत्ते और बन्दर के काटने पर दिए जाने वाले टीकों की बहुत कमी है। ये टीके प्राईवेट दुकानों पर तो मिल जाते हैं लेकिन होस्पीटल वाले कह देते हैं कि फैक्टरी अभी ये टीके प्रोडयूस नहीं कर रही है। क्योंकि स्ट्राईक है। वे टीके बाहर दुकानों पर आम मिल जाते हैं, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे हल्के की पांच सड़कें निहायत जरूरी हैं। इसमें एक विधल से जौली, निहात से गामड़ी, लाठ से गुमाना थाया भैंसवाल कलां, भैंसवाल से तेहाड़, कलाना खास से खानपुर कलां इसी तरह से लाठ गांव की इरिगेशन के लिए मालोट सब-ब्रान्च लाठ आर०डी० 53 पर एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकालने की बहुत जरूरत है और यह बहुत पुरानी मांग है। 20-30 साल से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। फरमाना माईनर की रि-मॉडलिंग किये जाने की बात मैं कहना चाहता हूं और इसकी दो बुर्जियां आगे बढ़ाया जाए तो काफी बड़े ऐरिया को उसका लाभ हो सकता है। माननीय मुख्यमन्त्री जी ने रामगढ़ माईनर मन्जूर की थी और उसके बारे में एनाउंसमैंट की थी। उसका ऐक्वीजीशन का सिलसिला भी काफी ऐडवान्स स्टेज पर है। उसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उसको जल्दी कम्पीलट करवा दिया जाए तो इससे लोगों का बड़ा भारी भला होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आयुर्वैदिक डिस्पैंसरी के लिए बहन जी से कहना चाहता हूं इन्होंने कहा भी था कि एक आयुर्वैदिक डिस्पैंसरी बीघल में बनाएंगे। एक माहरा गांव में ऑप्रेशन थियेटर बनाने के लिए कहा था। बहुत सारे लोगों का अन्धविश्वास है कि वहां पर आंखों पर आपरेशन ज्यादा कामयाब है। माहरा गांव के बारे में लोग कहते हैं कि वहां पर 15 साल से एक आदमी अन्धा था

[चौ० धर्मपाल सिंह मलिक]
और उसकी आंखें वहां से बन गई थीं अब लोगों में यह अन्धविश्वास हो गया है कि और कहीं से आंखें नहीं बन सकती-हैं। वह रूरल ऐरिया है और कोई भी आई आपरेशन गवर्नमैंट होस्पीटल के आपरेशन थियेटर से बाहर नहीं होना चाहिए। वहां के लोगों में आंखों के आपरेशन के बारे में अंधविश्वास को देखते हुए यह जरूरी है। माहरा गांव आपरेशन थियेटर बनाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माहरा गोहाना प्रोपर के लिए स्टोर्म वाटर के लिए तीन करोड़ रुपये की योजना है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मलिक साहब, अब आप बाकी के बारे में लिख कर भेज दीजिए। अभी और दूसरे काफी मैम्बर साहेबान ने बोलना है। Malik Sahib, Hon'ble Finance Minister is sitting here. Whatever you are saying he will incorporate your suggestions. Please give him in writing.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : ठीक है अध्यक्ष महोदय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री ज्ञान चन्द ओध (रतिया- एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहूंगा कि मैं बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मैं एक विनती करूंगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के पीले कार्डज का जो सर्वे हुआ है। यह ठीक तरह से नहीं हुआ है। इसको आप दोबारा से करवाने का कष्ट करें क्योंकि गरीब आदमी को इस कार्ड पर कुछ नहीं मिलता है। वे लोग बहुत ही दु:खी हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग के लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर होते हैं उनका आपको ध्यान रखते हुए यह सर्वे दोबारा से करवाना चाहिए। इसके साथ मैं सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे यहां पर बानवास से लटूवास, सतनगढ़ से पिलछियां और रतियां से बबनपुर की सारी सड़कें बुरी तरह से टूट चुकी हैं इनको भी आप ठीक करवाने का काम करवाएं। ज्यादा कुछ न कहते हुये मैं अपना स्थान लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री शाहिदा खान (तावडू) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। मेरे अपने गांव के साथ तो भेद भाव किया जा रहा है। वहां पर जो सड़क मेरे गांव में जाती है। उसका तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। हम अपने घर तक गाड़ी में बैठकर नहीं जा सकते हैं। तावडू तहसील से एक पी०डब्ल्यू०डी० का रोड जाता है और एक मार्किटिंग बोर्ड की सड़क जाती है। उस सड़क की हालत देखकर अध्यक्ष महोदय, आप खुद यह कहेंगे कि वाकई में वहां के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। (विघ्न) इस बारे में मैंने पिछले सैशन में भी कहा था कि हमारे मेवात के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है, वहां पर लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। (विघ्न) वहां पर पशुओं के लिए तो क्या आदमियों के लिए भी पीने का पानी नहीं मिलता है। पिछली बार जब मैं सैशन में आया था तो एक्सियन साहब से बात करके आया था। मैंने एक्सियन साहब से कहा था कि एक्सियन साहब यह जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है इसमें पहले जैसे हालात थे वैसे ही आज भी हालात हैं। अध्यक्ष महोदय, जब भाईयों में बंटवारा होता है और अगर किसी एक के हिस्से में पतीली नहीं आती है। तो दूसरी पतीली खरीदी जाती है। अध्यक्ष महोदय, हमारा मेवात डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले जैसा था वैसा ही

डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद भी है। यह एक तहसील जैसा ही है। मंत्री जी, आप तो हमारे पड़ौसी हैं हम तो आपसे काफी उम्मीद लगाए हुए थे।(विघ्न) पिछली दफा तो खूब पानी मिलता था और बहुत ही बढ़िया सड़कें थी लेकिन अब तो नहरों में जो कांई जमीन हुई थी वह भी सूख गई है और सड़कें टूटने के कारण ट्रैक्टर नहरों में से होकर गुजरते हैं। इस बारे में, मंत्री जी, आप इन्कवायरी करवा सकते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह तो इस साल की बात है पिछले साल तो वहां पर बहुत पानी आता था। वहां पूरी तरह से सैलाब आया करता था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारे नूह हास्पिटल में डाक्टरों में रिश्वत का बहुत चलन है। वहां पर पैसे लेकर झूठे केस दर्ज होते हैं। कोई उंगली तोड़कर ले जाता है और कोई कुछ और तोड़ कर ले जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। कि इस बारे में इन्कवायरी करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रेखा राणा (घरौंडा) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए बजट पेश किया है उस बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे यहां पर जो हरियाणा और यू०पी० की भूमि पर विवाद चल रहे हैं उस तरफ यह सरकार अपना ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय,आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामफल चिराना (बड़ौदा, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से वित्तमंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं। कि वित्तमंत्री जी आपने बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है जिससे यह लगे कि यह बजट बहुत अच्छा है। स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी ने बसों का किराया बढ़ाकर आम आदमी पर खासकर गरीब आदमियों की कमर तोड़ दी है और उनका घरेलू बजट तथा मासिक बजट हिलाकर रख दिया है। बजट में अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिए कुछ विशेष नहीं है। स्पीकर साहब, मैं वित्त मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के बच्चों को वजीफे दें लेकिन मेरी इच्छा यह भी है कि जो भी अच्छे विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी सहायता दी जानी चाहिए। हालांकि इन वर्गों का भला केवल वजीफे देने से नहीं होगा। इन लोगों को नौकरियों में उचित आरक्षण भी दिया जाना चाहिए और बैकलॉग भी पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा 85वें संविधान संशोधन को भी लागू किया जाना चाहिए। अगर ये कदम उठाए जाएंगे तो इनसे इन वर्गों का भला हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से प्रदेश के इन लोगों को अनेक सामाजिक संगठनों के दबाव के बावजूद भी गैस्ट टीचर की भर्ती में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया है। वह ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, गैस्ट टीचर की भर्ती में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। अगर इस तरह से ही भर्तीयां होती रहीं तो इन वर्गों का कोई सुधार नहीं हो सकता। इस तरह से तो यह लोग और भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। अध्यक्ष जी, हमारे संविधान में इन वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है इस तरह से इसका महत्व ही कम होता जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात कहते हुए शर्म आती है कि जिन दलित और कमजोर वर्गों के सहारे यह कांग्रेस की सरकार बनी थी आज उसी सरकार के शासनकाल में हजारों की संख्या में इनके बच्चे, बूढ़े, नौजवान और औरतों को पलायन करके भागना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी की जरूरत होती है। उसके जीवन की सुरक्षा । इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि उन्हें उचित नौकरियां मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इससे उनका भला हो सकता है। आज पूरे प्रदेश में बिजली पानी नहीं है, सारे प्रदेश में ब्लैक आउट है। इसी तरह से कानून और व्यवस्था को आप देखिए। हर रोज अखबारों में इस बारे में आप और सारा

[श्री रामफल चिराना]

सदन भी बढ़ता होगा। हालांकि पहले कुछ दिनों के लिए इसमें सुधार हुआ था लेकिन उसके बाद फिर वहीं होना शुरू हो गया। हर रोज डकैती, बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं। रोज अखबारों में इस तरह की खबरें भरी रहती हैं। चूंकि यह घटनाएं डिस्ट्रिक्वाइज होती हैं इसलिए सबका पता नहीं लग पाता क्योंकि वहां के अखबार वहीं रह जाते हैं। अगर ये घटनाएं एक ही अखबार में हों तो इन सबका पता चल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक किसान हूं और किसान का किसी भी तरह का नुक्सान यदि होता है। तो सरकार को उसको देखना चाहिए। मंत्री जी कहते हैं कि पाले से किसान की फसल को हुए नुक्सान की भरपायी नहीं की जा सकती। लेकिन मेरा कहना यह है कि सरकार चाहे तो वह बीज पर सबसिडी दे सकती है या फिर किसी और तरह से उसको बोनस दे सकती है। इस तरह से अगर सरकार की इच्छा हो तो वह किसी भी तरह से किसान का भला कर सकती है। इलैक्शन के दौरान कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि हम बेरोजगारों को नौकरियां देंगे लेकिन नौकरियां देने के बजाए कितने ही लोगों को बेरोजगार बना दिया गया और सड़कों पर ला दिया गया। इनमें से कईयों ने तो आत्म हत्या तक कर ली। मैं आपके माध्यम से सरकार के कहना चाहता हूं कि लोगों को नौकरी से न हटाया जाए बल्कि उनको रोजगार दिया जाए। सरकार का काम लोगों को नौकरियों से हटाना नहीं होता है बल्कि उनको नौकरियां देना होता है। अध्यक्ष जी, मेरे बड़े भाई धर्मपाल मलिक जी अभी फरमा रहे थे। उनका बहुत तजुर्बा है। वे कह रहे थे कि पिछली सरकार बहुत अन्यायी थी उसके मुख्यमंत्री अन्यायी थे। अध्यक्ष जी, अभी मेरे बड़े भाई मलिक साहब सदन में बैठे नहीं है वे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं उस समय वे कहां थे ? उस समय भी तो पानी का बंटवारा हो सकता था और उस समय वे मुख्यमंत्री जी के सबसे नजदीकी माने जाते थे। उस समय उनकी मेरे ख्याल से चलती भी खूब थी इसलिए उस समय ही उनको पानी का बंटवारा कराना चाहिए था। उस समय ये सरकार के सामने सिर क्यों झुका रहे थे ? ये उस समय भी पानी का बंटवारा करवा सकते थे।

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आर्डर सर /-सर, जो पानी के बंटवारे वाली बात है, मेरे ख्याल से सारे हरियाणा में पानी का बराबर बंटवारा आज तक कोई नहीं कर पाया खाली पानी पर राजनीति की गई। हमेशा समझौते होते रहे। जो राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ था अगर वह समझौता उस वक्त मान लिया जाता तो आज एस०वाई०एल० नहर का झगड़ा भी नहीं होता। आज इस नहर का काम वहीं पर रूका पड़ा है। मैं मानता हूं कि इस पाप के सांझी हम भी हैं, वह पाप किया गया था। यह सारा हरियाणा जानता है कि हरियाणा के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। सिर्फ एक सत्ता हासिल करने के लिए पानी के लिए लोगों के सिर फुड़वाये, हाथ तुड़वाये और ट्रैक्टर तुड़वाये और इसमें लोगों की जानें तक गई। लेकिन जो वायदा चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जनता के सामने किया था वह आज पूरा करके दिखाया है। इसलिए आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी।

श्री रामफल चिराना : अध्यक्ष महोदय, बिजली मंत्री और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिजली की तारें पहले खींची गई हैं और गरीब आदमियों को प्लाट बाद में दिए गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि गरीब आदमियों के लिए जो पहले प्लाट कटे हैं और अभी भी कट रहे हैं वहां पर बिजली की तार पहले से ही मौजूद होती हैं। यदि उन तारों को हटाने की बात की जाती है। तो बिजली महकमा एक बहुत बड़ा एस्टिमेट लाकर उन गरीब

आदमियों के सामने रख देता है। वह एस्टिमेट इतना ज्यादा होता है कि उतनी तो उस प्लाट की कीमत भी नहीं होती। 5-7 हजार रुपये में गरीब आदमी अपनी झौपड़ी डाल लेता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन बिजली के तारों को सरकारी खर्चे पर हटाने का सरकार काम करे। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री ईश्वर सिंह पलाका (दादौर, एस०सी०) : स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। स्पीकर साहब, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है यह कोई खास अच्छा बजट नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में होते थे तो एक बात कहा करते थे कि हमारे पास एक जादू की पुड़िया है जब भी हम सत्ता में आयेंगे तो बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर देंगे। स्पीकर सर, बेरोजगारी खत्म तो क्या करेंगे जो बेचारे नौजवान युवक नौकरी में थे उनको भी नौकरी से हटा दिया गया है।

Mr. Speaker : Don't repeat the same thing. यह तो चिराणा जी ने बता दिया आप अपने सुझाव दीजिए, रिपीट मत कीजिए।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : बेरोजगारी भत्ते की बात बजट में कही गई है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी भत्ता देने का ऐसा प्रावधान कर दिया कि आम बेरोजगार युवक को बेरोजगारी भत्ता बड़ी मुश्किल से मिल पायेगा। स्पीकर सर, जब पिछली सरकार सत्ता में थी और आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने जो वैट लागू किया था तो उस समय आज के सत्ता पक्ष के हमारे साथियों ने बड़ा शोर मचाया था और व्यापारियों को बहकाया था कि वैट एक मिथ्या प्रचार है इससे यह हो जायेगा वह हो जायेगा। स्पीकर सर, आज उसी वैट का कमाल है जो हरियाणा में अर्थव्यवस्था कुछ ठीक हुई है। स्पीकर सर, बजट सरकार का सारे साल का लेखा-जोखा होता है कि कहां से पैसा आयेगा और किस-किस मद पर कितना-कितना पैसा खर्च किया जायेगा। स्पीकर सर, जैसा कि सभी को मालूम है कुछ खर्चे योजनागत होते हैं और कुछ गैर योजनागत खर्चे होते हैं। अच्छा बजट उसी को माना जाता है जिसमें योजनागत खर्चे अधिक होता है। पिछली बार बजट में 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी और अबकी बार 7.8 प्रतिशत है जो कि बहुत कम है । अध्यक्ष महोदय, हमारे समय में बजट घाटा 48 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष इस सरकार के समय में बजट घाटा 54 करोड़ रुपये था और आने वाले साल में यह घाटा 65 करोड़ रुपये हो जायेगा। इसका मतलब यह है कि सरकार की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है। स्पीकर सर, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी की अच्छी सोच की वजह से हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि यह सुधार हमारी सरकार के समय में वैट प्रणाली लागू करने के कारण हुआ है।

श्री अध्यक्ष: ईश्वर सिंह जी, आप यह बतायें कि वैट क्या है ?

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर, वैट का मतलब वैल्यू एडिड टैक्स होता है। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इस बजट का विरोध करता हूं और आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (नौल्था) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया

[श्रीमती प्रसन्नी देवी]

इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं । साथ ही साथ इतना अच्छा बजट पेश करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का और पूरी सरकार का भी धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बहुत ही शानदार और अच्छा बजट प्रदेश की जनता को दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग को फायदा पहुंचेगा। बजट बनाते समय वित्त मंत्री जी ने हर बात को ध्यान में रखा है कि किस प्रकार से हर वर्ग इस बजट का फायदा उठा पायेगा। स्पीकर सर, हमारी सरकार को बने हुए एक साल हुआ है और इस एक साल में हमारी सरकार ने बहुत अधिक जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। हमारी सरकार आने से पहले चारों तरफ भय का वातावरण बना हुआ था। हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता को भय मुक्त वातावरण दिया है। पहले आदमी जब सुबह घर से बाहर निकलता था तो पता नहीं होता था कि शाम को वापस घर आयेगा भी की नहीं। कौन रास्ते में ही मारकर दौड़ जाये किसी को पता नहीं होता था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद 99 प्रतिशत बदमाशों का सफाया हो गया है और कोई भी आदमी कहीं आये-जाये किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगी कि पिछली सरकार के लोग वोट लेने के लिए लोगों को कहते रहे कि वे बिजली के बिल न भरें उनकी सरकार बनने पर वे बिजली के बिल माफ कर देंगे। लोग उनके झूठे वायदों में आ गये और उनको वोट दिए। उनकी सरकार भी बनी लेकिन उन्होंने किसानों के बिजली के बिल माफ नहीं किए। किसान इतने बोझ तले दब गये थे कि बिजली के बकाया बिलों से छुटकारा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था लेकिन हमारी सरकार आने के बाद किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए गए इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं। उन्होंने किसानों को बहुत सारी सहूलियतें दी हैं। स्पीकर साहब, कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहती हूं। बिजली की समस्या है लेकिन इसकी तरफ सरकार गम्भीरता से विचार करने के लिए लगी हुई है। कितनी ही योजनाएं सरकार ने शुरू की हुई हैं और कुछ टाईम के बाद इसमें बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि बिजली का 10% खर्चा तो बढ़ता ही है। जितनी बिजली की खपत बढ़ती है उसके साथ ही साथ उसके उत्पादन में बढ़ोतरी भी होती रहनी चाहिए। इसी तरह से किसान के लिए पानी की कितनी दिक्कत थी। हमारे अपने इलाके में 42 दिन के बाद पानी आता था अब कम से कम हम यह तो कह सकते हैं कि पानी जितना है वह बंटवारे के मुताबिक जिस एरिया में जितना पानी मिलना है वह उसके मुताबिक मिलता है। पानी के लिए कोई शिकायत नहीं करता है। थोड़ी-बहुत शिकायत अगर कहीं पर होगी तो वह यह है कि कहीं पर पानी चढ़ता नहीं या नाले में कमी हो इस तरह की बात तो कहते हैं लेकिन यह कोई नहीं कहता कि सिरसा में इतना पानी आ गया है या रोहतक में इतना पानी आ गया। यहां पर सब जगह बराबर का हिसाब किताब से पानी देकर इस सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। स्पीकर साहब, बालिका वर्ष की शक्ल में इस साल को मना कर मैं कहती हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने लड़कियों की तरफ बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। पढ़ाई के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियों में 33% हक देने के लिए आवास में 33% मकानों और उसके साथ ही साथ और कितनी छोटी-मोटी सुविधाएं लड़कियों के लिए दी हैं। अकेली लड़की होने पर सरकार ने सुविधा दी हैं ये सारी चीजें इस बजट के अन्दर हैं। इस एक साल के अरसे के अन्दर इस सरकार ने इतनी सुविधाएं दी है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्री जी से कुछ प्रार्थना करना चाहती हूं। जहां लड़कियों को इतनी

सहूलियत दी है वहीं पर मैं कहना चाहती हूं कि हालात को देखते हुए लड़कियों के लिए प्राईमरी से लेकर मिडल, हाई, हायर सैकेंडरी तक जितने ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जा सकें वे खोलने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के लिए जीन्द में एक कॉलेज बनाया गया है यह बहुत अच्छा कदम कहा जाएगा। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक और प्रार्थना भी करती हूं और यह कहना चाहती हूं कि हर जिले में लड़कियों के लिए कम से कम एक सरकारी स्कूल तथा सरकारी कॉलेज जरूर खोलना चाहिए। मैं समझती हूं कि सरकार के इस कदम की सारी महिलाएं सराहना करेंगी और सारा महिला समाज मुख्य मन्त्री जी को हमेशा-हमेशा के लिए याद रखेगा। इसके साथ ही माननीय मुख्य मन्त्री जी ने लड़कियों के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी की घोषणा की है यह बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है जिसको यह महिला वर्ग कभी भी भुला नहीं सकेगा। स्पीकर साहब, इसी के साथ ही साथ हमारा एक तबका ऐसा है जिसे और सरकारी सहूलियतें देने की जरूरत है। जो कमजोर वर्ग का तबका है उसकी कुछ समस्याएं रहती हैं। जैसे कि कार्डज की समस्या है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के साथ पिछली सरकार ने बड़ी बेइन्साफी की थी। जिनको कार्डज मिलने चाहिएं थे उनको कार्ड नहीं मिले थे लेकिन जो लोग उन कार्डों के अधिकारी नहीं थे उनको कार्ड मिले हुए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करती हूं कि सरकार इसके बारे में पूरे कदम उठाएगी। इसके साथ ही मैं सरकार से एक और प्रार्थना करना चाहती हूं कि अब सारी सहूलियतें देने के बाद गरीब आदमी की जो सबसे बड़ी जरूरत है, वह है मकान। उसको रहने के लिए जगह की इतनी दिक्कत है कि आप अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। बहुत पहले इन्दिरा गान्धी जी के टाईम में 100-100 गज के प्लॉट्स गरीब लोगों को मिले थे। उसके बाद अब कई कई पीढियां आ गई। हमारे मुख्यमन्त्री जी बड़े दयालु हैं। मैं समझती हूं कि जहां 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए हैं अगर 800 करोड़ रुपये गरीबों के प्लाटों पर खर्चे जाएं तो सदा-सदा के लिए वे लोग आपके उपकार को भुला नहीं सकेंगे। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं हैं और वे लोग बहुत ही मुश्किल में हैं। पिछले बजट में जो घोषणा की गई थी अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। कॉमन लैट्रिन्ज़ गरीब वर्ग के लिए बननी चाहिएं क्योंकि गांवों में औरतों को इस बात की बड़ी दिक्कत रहती है। स्पीकर साहब, मैं सरकार से एक और प्रार्थना करना चाहती हूं। हमारी जो विधवा बहनें हैं विशेषतौर से वे महिलाएं जो दलित वर्ग से ताल्लुक रखती हैं उनकी आमदनी का कोई साधन नहीं है, उनको मकान देने की स्कीम का कुछ प्रबन्ध करना चाहिए। 25 हजार रुपये परपोज हुए हैं लेकिन वह थोड़े-थोड़े से सभी गांवों में पहुंचाए जाते हैं। यह स्कीम तो वित्त मन्त्री जी देखेंगे कि बजट में क्या करेंगे लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूं कि जो इसके लायक हैं उनको ये मकान मिलने चाहिएं। जिसके पास रोटी खाने का साधन नहीं हैं उनको रहने के लिए मकान जरूर मिलने चाहिएं। यह बहुत जरूरी है। स्पीकर साहब, राजीव गांधी जी का पंचायती राज का स्वपन था मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने हरेक तरीके से गांवों में और शहरों में उस बारे में अमल किया है। उसके साथ-साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि मात्र एक साल के राज में इस सरकार ने यह सब किया है। पिछली सरकार तो यह कहती थी कि बजट में पैसा ही नहीं है। आज हरियाणा में कहीं पर नालियां बनती नजर आ रही हैं, कहीं पर गांवों में गलियां बनती दिख रही हैं और कहीं कालेजिज की बिल्डिंगज के लिए पैसा मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाएं हैं। कहीं इन्होंने गांवों की स्कीमों के लिए कदम उठाए हैं और कहीं पर गांवों के जोहड़ों की चारदीवारी वगैरह बन रही हैं। इस सरकार के अच्छे काम

[श्रीमती प्रसन्नी देवी]

होते दिखाई दे रहे हैं। इससे यह दिखता है कि इस सरकार में किस तरह से हर वर्ग के काम हो रहे हैं। स्पीकर सर, इसी तरह से पीने के पानी की एक बहुत भारी समस्या है। जब पहले हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय पानी के लिए एक स्कीम चालू की गई थी। अगर पिछली सरकार थोड़ा सा भी काम अपनी बुद्धि से लेती और उन चालू हुई स्कीमों पर काम करती तथा उन पर पैसा खर्च करके उनकी सम्भाल करती रहती तो आज यह स्कीमें खण्डहर नहीं बनती। हरियाणा प्रदेश के गांवों में उस वक्त कांग्रेस सरकार के राज में पानी पहुंचा दिया गया था लेकिन उन स्कीमों के बन्द होने के कारण वह पानी भी बंद हो गया है। आज हरियाणा में पानी की बहुत समस्या है। पाईप्स न मिलने की वजह से वहां पर यह समस्या खड़ी हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से सरकार से प्रार्थना करूंगी कि गर्मियां आने से पहले विशेषकर हरिजन तबकों के लिए जिनके पास पानी पीने का और कोई साधन नहीं है और उनके एरियों में कई जगहों पर हैंडपम्पस भी काम नहीं करते हैं वहां पर कोई भी इन्तजाम करके उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें। स्पीकर सर, मेरे हल्के में जनवरी में मुख्यमंत्री जी गए थे। वहां पर क्या-क्या वायदे किए थे। उस बारे में कहने में काफी लम्बा समय लगेगा। उन वायदों में से काफी काम शुरू हो गए हैं, कुछ अभी होने बाकी हैं। मैं उनके लिए मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि उन कामों को जल्दी से जल्दी करवाया जाए। स्पीकर सर, यह बात ठीक है कि इस बार सड़कों के लिए बजट में बहुत पैसा रखा गया है लेकिन इसमें एक फर्क यह रह गया है कि उसमें यह मार्क नहीं किया गया है कि कितनी सड़कें मार्किटिंग बोर्ड द्वारा और कितनी सड़कें पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा बनाई और रिपेयर की जाएंगी। इस बारे में सरकार को जल्दी से हिसाब किताब कर देना चाहिए ताकि उनका काम भी जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। इसके अलावा जो स्टेट हाई-वे की सड़कें हैं उनको भी रिपेयर करने के लिए सरकार की तरफ से पैसा जल्दी से जल्दी मुहैया करवा देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैडम जी, बाकी की मांगे आप लिखकर दे देना।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : ठीक है सर। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के इस बजट की सराहना और समर्थन करती हूं कि इस सरकार ने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर (नारनौल) : अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने इस सरकार का दूसरा बजट पेश किया है। मैं इस बजट का अनुमोदन करने के लिए सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने इस बजट की आलोचना भी सुनी है लेकिन उसका एक ही निचोड़ है कि वह आलोचना निराशा और कुंठित भावना का परिणाम है और कोई सार, कोई तथ्य उसमें नहीं है। हमारी सरकार का यह दूसरा बजट कुल 3300/- करोड़ रुपए का है। इसमें 1568 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा के लिए रखे गए हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मनुष्य आवश्यकता से और स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और जिस समाज के अन्दर मनुष्य रहता है अगर उस समाज के अन्दर मनुष्य में असुरक्षा की भावना और हीनभावना आ जाएगी तो वह समाज प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इस बजट में सामाजिक सुरक्षा का जो मानदण्ड रखा गया है उसके लिए मैं इस सरकार को बधाई देता हूं। हमारे देहात के अन्दर बजट के माध्यम से समय पर लोगों को पैंशन मिल जाती है। अनुसूचित जातियों के लिए आवास बनाने के लिए 50 हजार रुपयों

का प्रावधान बजट में किया गया है इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पैसा है वह उस गरीब आदमी को ही दिया जाना चाहिए। सरकारी अधिकारियों के माध्यम से सामान नहीं खरीदा जाना चाहिए क्योंकि वह सामान बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है और गरीब आदमी को मजबूर होकर वह सामान लेना पड़ता है। इसके साथ ही हमारे जो गरीब विद्यार्थी हैं, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको तीन हजार रुपये का वजीफा देने की बात कही गयी है यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन राज्य की जनसंख्या को देखते हुए, विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए इसको और बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अध्यक्ष महोदय, दूसरे वर्गों के जो गरीब विद्यार्थी हैं अगर उनको भी सरकार इस तरह का लाभ दे तो यह अच्छी बात होगी। यह बात सही है कि हमारी जो लड़कियां है वह दो कुलों को पवित्र करती हैं। यह वर्ष बालिका वर्ष के रूप में हमारी सरकार मना रही है। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं इसके अलावा भी और जो-जो बातें बजट में हैं वह हम सबने देखी हैं लेकिन मैं सामान्य तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि विकल्प योजनाओं के माध्यम से या दूसरी योजनाओं के माध्यम से आज हम आगे बढ़ रहे हैं जोकि एक अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक नहरों का सवाल है, हमने सबसे पहले यह कल्पना की थी और यह बात आयी थी कि हमें जो पानी मिलता है वह यमुना की बाढ़ से मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 18 फरवरी को इसी को ध्यान में रखते हुए एक योजना की आधारशिला भी रखी जोकि एक सराहनीय कार्य है। मैं कहना चाहता हूं कि राजा प्रजा की अच्छाई के लिए सब कुछ करना चाहता है वह जन-जन का विकास करना चाहता है और इसी कसौटी पर हमारे मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। जो वायदे किए है वह निभाए जा रहे हैं और जो वायदे नहीं भी किए हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक इतिहास की बात बताना चाहता हूं एक पिता का कहना मानना या पिता की इच्छा की पूर्ति करना एक बेटे का सबसे बड़ा काम होता है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और चौधरी रणबीर सिंह ने भाखड़ा बांध बनाकर हमारे प्रान्त को दिया था। भाखड़ा मेन नहर से ही बुटाना हांसी नहर निकाली जा रही है। उस समय भी चौधरी साहब की इच्छा थी कि इसका पानी रोहतक और नारनौल या नांगल चौधरी के इलाकों तक पहुंचे लेकिन परिस्थियां ऐसी रहीं कि वह पानी वहां तक नहीं पहुंच सका लेकिन आज उस काम को पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी एक सुपात्र बेटे की तरह लगे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नांगल चौधरी के इलाके तक उस पानी को पहुंचाया जाए ताकि हमारे चौधरी साहब की इच्छा पूरी हो सके। यह बहुत आवश्यक काम है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अंदर नांगल दुर्गा, जाखड़ी और माखरी नहर पर आधारित योजनाएं बनीं लेकिन वह अभी तक जोड़ी नहीं गयी हैं इसलिए इनमें अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने वैसे तो इनके लिए 271 लाख रुपया दिया है जिसके लिए मैं और मेरे क्षेत्र के लोग उनका अहसान मानते हैं लेकिन हम उनसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि जब तक इन योजनाओं को नहर के माध्यम से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। गर्मी का मौसम आने वाला है अगर ऐसा नहीं होगा तो यह गर्मी का मौसम मुश्किल से निकल पाएगा इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी युद्ध स्तर पर काम करवाकर इन तीनों योजनाओं को जोड़ा जाए। अध्यक्ष महोदय, बिजली की भी कमी है। हम सब यह बात मानते भी हैं लेकिन जो नीयत है वह अच्छी है। पहले की सरकारों ने बिजली बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया लेकिन वर्तमान सरकार ने चार बिजली उत्पादन के कारखाने शुरू करवाने की बात कही है। इसलिए आशा है और आशा के ऊपर यह संसार टिका हुआ है। आशा के ऊपर ही हम सब

[श्री राधे श्याम शर्मा अमर]

जीविल हैं। बिजली मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बिजली के पोल्ज के नाम से या ट्रांसफार्मज के नाम पर काम नहीं हो रहा है। मैं तो यह भी कहूंगा कि हर साल बजट में कहा जाता है कि 30 जून तक जन-स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी कर दी जायेंगी। 30 जून तक तो इतनी गर्मी हो जायेगी कि लोग मारे जायेंगे। इसलिए 30 जून के स्थान पर अगर इन सुविधाओं को 15 अप्रैल तक ही पूरा कर दें तो देहात को अच्छी तरह से बिजली और पानी मिल जायेगी। हमारे इलाके में अगर बिजली चली जाये तो पीने का पानी नहीं आ पाता। आपके यहां तो जोहड़, नहर, कुएं और तालाब भी हैं लेकिन हमारे इलाके में गर्मियों में पीने का पानी की बहुत समस्या हो जाती है। दूसरी बात बजट में लड़कियों की शिक्षा के बारे में भी कही गयी है। बहुत अच्छी बात है कि खानपुर में जहां पर पहले एक पुराना गुरूकुल था, वहां पर एक महिला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। महेन्द्रगढ़ में काफी लड़कियां पढ़ने वाली है वहां पर हमारे यादव तथा चौधरी भाईयों की 100 प्रतिशत और गुर्जर बिरादरी की 50 प्रतिशत लड़कियां पढ़ती हैं इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उस महिला विश्वविद्यालय का एक रीजनल सैन्टर नारनौल में भी खोला जाए। यह मेरा सरकार से अनुरोध है । स्पीकर साहब, मैं एक निवेदन यहां पर सरकार से करना चाहूंगा क्योंकि यह गरीबों से संबंधित है। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हजारों क्विंटल ए०पी०एल० और बी०पी०एल० लोगों के लिए गेहूं की नारनौल में स्मगलिंग हुई है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार ने इस मामले में 2-3 अधिकारियों को सस्पैंड भी कर दिया है लेकिन जो बड़े मगरमच्छ थे उनका भी ध्यान करने की जरूरत है क्योंकि उनकी रहनुमाई में ही यह सारे काण्ड हुए हैं मेरे इलाके का गरीब आदमी रोता रहा और इतनी बुरी हालत हो गई कि गांव के लोगों को गेहूं 1150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भी नहीं मिला। इसलिए ऐसा अन्याय करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने से पब्लिक में सरकार की इमेज बढ़ेगी। जो ये अधिकारी बेईमानी करते हैं वे सरकार की इमेज नहीं बढ़ायेंगे क्योंकि ये सारी बातें सरकार को नहीं बतातें। आपका विधायक आपको सारी बातें बतायेगा। इससे आम जनता में सरकार की इमेज भी बढ़ेगी और इससे आम जनता को लाभ भी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : सर मैं एक बात और दो मिनट में बोलकर अपना भाषण खत्म करता हूं। आपका आदेश मुझे मिल गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी कल परसों ओम प्रकाश चौटाला जी का एक उदाहरण देते हुए कह रहे थे कि यदि वे हाउस में आते तो हम भी उनके अनुभव का लाभ उठाते । मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि जिन अनुभवों की वे बात कर रहे थे उन अनुभवों से दूर ही रहना अच्छा है क्योंकि उनका अनुभव हरियाणा पहले ही काफी भुगत चुका है। यह मुख्यमंत्री जी की दरियादिली है क्योंकि सभ्य समाज में रहकर एक सभ्य आदमी ही ऐसी बात कह सकता है। ये भाई इस तरह की बात नहीं कहते । मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चेहरा बदलने से व्यवस्था बदलती है। यह जो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी है इस कुर्सी पर 5 मार्च, 2005 से पहले क्या चेहरा था, उस समय राज्य में क्या आतंक था लेकिन चेहरा जब बदला तो उसी राज के अन्दर व्यवस्था भी बदली और खुशहाली आई और राज्य में अमन चैन आया । जिन जिलों में अभी भी खूंटा ठोक चेहरे बैठे हैं उनको बदलने से जनता में सरकार की इमेज बढ़ेगी। एक बात और मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने

मेरे हल्के में एक हमीदपुर बांध जोड़ने के लिए एक नहर मन्जूर की है। मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि दोहन और कृष्णावली नदियों के अन्दर जल्दी से जल्दी पानी डाला जाये। एक बात मैं कैप्टन साहब से कहना चाहता हूं कि उन्होंने 31 मार्च तक सरसों की फसल की गिरदावरी करवाने के लिए कहा है। लेकिन वर्षा के होते ही हमारे किसानों ने तो सरसों को काट लिया है। इसलिए अब 31 मार्च तक तो सरसों का एक पौधा भी खेत में नहीं मिलेगा। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Sharma, please address the Chair. आपको चेयर को एड्रैस करके बोलना चाहिए, कौन क्या कर रहा है इसको देखना आपका काम नहीं है। The Finance Minister is nothing the points.

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : स्पीकर साहब, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा आप इसके लिए बुरा न माने। जो आपने हाउस के बाहर लॉबी में सदस्यों के सिटिंग प्लान का बहुत सुन्दर चार्ट बनाया हुआ है। उसमें ट्रेजरी बैन्चिज और विपक्ष में बैठने वाले सदस्यों के फोटोज टेढ़े लगे हुए दिखाया है जो कि सही नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस चार्ट को ठीक तरह से लगवाने का काम करें। यह चार्ट पिछले सैशन में भी लगा हुआ था। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : परम आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट चर्चा पर बोलने के लिए समय दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश है और इस देश में बजट एक आर्थिक उत्सव है जिसमें साल का आय और व्यय का गणित, लेखा व जोखा प्रस्तुत किया जाता है। उसके शब्दों और आंकड़ों के अनुसार आने वाले साल के लिए प्रदेश की तस्वीर बनाई जाती है। यह कोई औपचारिकता नहीं है, यह एक संवैधानिक जरूरत है। 26 नवम्बर, 1947 से बजट की शुरूआत हुई थी। उस समय पहले वित्तमंत्री मिस्टर चेट्टी थे और आज तक वह परम्परा चली आ रही है। पहले शायद आम आदमी बजट के पहलू को नहीं समझता था लेकिन आज की तारीख में सूचना, संचार और समाचार पत्रों के माध्यम से आम आदमी इसके महत्व को समझता है इसके आने वाले प्रभाव को जानता है। इसलिए मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को और वित्तमंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही बैलैंस्ड बजट प्रदेश की जनता को दिया है जो कि कर रहित भी है। इसके लिए जितनी इनकी प्रशंसा की जावे वह कम है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं हमारी यू०पी०ए० की अध्यक्षता त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्ति आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि वे जो लक्ष्य लेकर भारत निर्माण में लगी हुई हैं उसी तर्ज में ऊपर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हरियाणा के निर्माण में लगे हुए हैं और यह हमारी अध्यक्षा की पारखी और पारदर्शी नजरें हैं जिन्होंने एक ईमानदार स्वच्छ छवि के व्यक्ति के हाथों हरियाणा की बागडोर सौंपी है। आज चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है और मैं कहूं कि हमारे मुख्यमंत्री गंगा पुत्र हैं तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। कुछ भाई आज कह रहे थे कि प्रदेश में विकास नजर नहीं आता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे ऐसी कोई जगह बतायें जहां उनको विकास नजर नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क की बात करूं या परिवहन की, स्वास्थ्य की या रोजगार की यानि किसी भी पहलू की बात करूं हर तरफ विकास हो रहे हैं। मेरे साथी कोई पहलू बतायें, जरिया बतायें या कोई क्षेत्र बतायें जहां पर विकास का कार्य न चल रहा हो। लेकिन

[राव दान सिंह]

विपक्ष के साथियों के मन ही मन में एक कचोट है क्योंकि ये प्रदेश में विकास होते नहीं देख सकते इसलिए इनके मुखौटे आज बंद हैं। आज ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अध्यक्ष महोदय, किसी शायर ने कहा है कि --

हवाओं के चलने से पत्ते सर-सराते हैं,
खामोश सन्नाटे बहुत कुछ कह जाते हैं,
हमारे एक साल के कामों को देखकर,
विरोधी भी घबराते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष के साथियों में हिम्मत नहीं है कि ये सरकार के कामों को देख सकें। हमारी सरकार ने जो इस साल का बजट पेश किया है यह बहुत ही निपुणता और कौशल के साथ तैयार करके पेश किया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का चहुमुखी विकास हो और हरियाणा प्रदेश एक नम्बर पर हो यह हर व्यक्ति की लालसा है लेकिन उसको पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे वित्तमंत्री जी ने 3300 करोड़ रूपये का परिव्यय का लक्ष्य लेकर के बजट को पेश किया जो पिछले साल से 300 करोड़ रुपये अधिक है। मेरे विपक्ष के भाई कह रहे थे कि बजट में कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इनके समय का बजट उठाकर देखिये 2200 करोड़ रुपये का बजट पेश किया और 2000 करोड़ रूपये भी खर्च नहीं कर पाये । यदि हम भी इन्हीं की तर्ज पर चलते तो यह जो 10वी0 पंचवर्षीय योजना जिसका 2006-07 अंतिम वर्ष है और जो 12000 करोड़ रुपये को अनुमोदित करता है उस लक्ष्य को हम कभी हांसिल नहीं कर पाते। 11.56 करोड़ रूपये के घाटे के साथ बजट पेश किया और मात्र 5 पैसे बस किराये के अंदर बढ़ाये हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निपुणता की और कोई बात नहीं हो सकती। मैं बजट के ज्यादा आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता और सबके सामने जो बातें पेश की गई हैं उनको भी दोहराना नहीं चाहता। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अवश्य कहना चाहता हूं। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले कानून व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत थी।अध्यक्ष महोदय, हम अपने प्रदेश को चाहे कितना भी सोने का बना दें, कितने ही साधन और संसाधन जुटा दें लेकिन जब तक प्रदेश में अमन-चैन और शांति नहीं होगी तब तक हमारे सारे प्रयास विफल हो जायेंगे। इसलिए प्रदेश के विकास के लिए सबसे पहला कार्य हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने जो किया वह कानून-व्यवस्था को प्रदेश में बरकरार करने का किया है। मैं एक साल पहले का समय स्मरण कराना चाहूंगा के हत्या, डैकेती और लूटपाट उस समय सरेआम होती थी। सरकार के लोग अपराधियों को संरक्षण देते थे। यहीं बैठकर वे अपराधी लोग आपस में इज्जत की बात समझते थे तथा गर्व महसूस करते थे कि मेरी बगल में कोई अपराधी बैठा है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। आज हमारी पुलिस का मनोबल ऊंचा है, एक समय था जब हमारी पुलिस का मनोबल बहुत नीचे चला गया था और वे अपनी हिम्मत और हौंसले से अपराधियों से टकराते हुए घबराते थे लेकिन अब पुलिस ने 18 घोषित अपराधियों को इनकाउंटर में मारा है। बचे हुए अपराधी प्रदेश छोड़ कर चले गए हैं, इक्का दुक्का बचे हैं उन्हें भी शीघ्र ही सींखचों के पीछे डाल दिया जाएगा। हमारी सरकार का युद्ध अपराधियों के प्रति जारी है। मैं मानता हूं कि अपराधियों का समापन सम्भव नहीं है। अपराधी की प्रवृत्ति अपराध करना होती है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम अपराध का समापन करके रहेंगे इसलिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अन्दर चैन और अमन है जिसका प्रताप देखने को मिलता है। वे उद्योग जो यहां से पलायन करके

चले गए थे, जो उद्योगपति यह कहते थे कि हरियाणा में मत जाओ वहां पर लुट जाओगे, डकैती, मारी जाएगी और आपकी हर रात चिन्ता में गुजरेगी। वहीं पर अब उद्योगपति कहते हैं कि देश में सबसे बढ़िया निवेश करने के लिए अगर कोई जगह है तो वह हरियाणा प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश के पास आज उद्योग लगाने के लिए उन लोगों के देने के लिए जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली आज एक ऐसी जरूरत हो चुकी है जिस पर हम निर्भर करते हैं अगर एक घंटा बिजली न हो तो ऐसा लगता है कि जैसे यह जीवन ठहर गया हो। आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय ने सबसे पहले इस प्रदेश के 75% जनता के मन की जो बात थी उसको भांपते हुए बिजली के बकाया बिलों के 1600 करोड़ रुपये मुआफ किए और साथ ही उनको पेश आने वाली समस्याओं से जूझने का भी प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, बिजली की खपत ज्यादा है जबकि बिजली का उत्पादन काफी कम है यानि बिजली की पैदावर की तथा खपत के साथ सामंजस्य नहीं बैठ सकता है इसलिए उन्होंने इस बात को लेकर केन्द्रबिन्दु किया और उस पर काम करना शुरू किया। इस वक्त हमारे प्रदेश में नौ हजार मेगावाट बिजली की आवश्यकता है जब कि हरियाणा प्रदेश में चार हजार मेगावाट बिजली की पैदावार होती है और पांच हजार मेगावाट बिजली हम खरीद कर लेते हैं यह बिजली हम अपने संसाधनों से क्यों नहीं बनाते ? इस बात को लक्षित करते हुए उन्होंने अपनी शुरूआत की है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले तीन साल के अन्दर हरियाणा प्रदेश नौ हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा और 18 से 20 घण्टे तक हरियाणा प्रदेश के लोगों को बिजली दी जाएगी तब जाकर हरियाणा को चैन और अमन का रास्ता मिल पाएगा। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात आती है पानी की। पानी के बिना जीवन दूभर है। कहते हैं कि जल ही जीवन है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो उस क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं कि जहां सूखी धरती है और वहां का किसान परिश्रमी है धरती का सीना चीर कर वह अनाज पैदा करना जानता है, लेकिन जब उसको पानी की बून्द नहीं मिलती तो वह अपने आंसू बहाता है और व्यथित होता है मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने शपथ लेते ही सबसे पहले यह फैसला किया कि प्यासी धरती की प्यास बुझानी है। अगर हरियाणा में एक बून्द भी पानी होगा तो वह समान बंटवारा होकर हरियाणा की जनता के पास जाएगा तथा दक्षिणी हरियाणा के एक-एक खेत को एक-एक इंच भूमि को पानी मिलेगा। इससे पहले हमारे साथ क्या होता था कि जब भी राजनेताओं से पानी की बात की जाती थी तो हमें एस०वाई०एल० का नाम देकर टाल दिया जाता था और हम कहते थे कि पानी तो आएगा लेकिन हमारी आंखों में आएगा। अध्यक्ष महोदय, आज पानी के समान बंटवारे का फैसला हो चुका है और उसका शिलान्यास भी हो चुका है और उसके लिए बजट में 260 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसका कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है तो आसा की एक किरण नजर आने लगी है। दो साल बाद इस पानी से वहां लहलहाती फसल नजर आएगी। उस दिन इस हरियाणा का भाग बदलेगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही गम्भीर बात पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है और वह गिरते हुए लिंगानुपात की चिन्ता है। क्योंकि देखिए इस मनुष्य की संरचना महिला के माध्यम से हुई है।यह वह महान धरती है और हमारे समाज बताते हैं हमारे शास्त्र बताते हैं हम गऊ को माता मानते हैं पत्थर को पूजते हैं लेकिन लड़की पैदा करने पर उसकी भ्रूण हत्या करने को आमादा हो जाते हैं यह बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। इसको चिन्हित करते हुए हमारी सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं और प्रोत्साहन के अनेकों काम चलाए हैं । मुख्य मन्त्री जी उस होने वाली बच्ची के दुख और वेदना को समझते हैं। वह बच्ची

[राव दान सिंह]

चीख-चीख कर कह रही है कि हमें प्यार चाहिए हमें दुलार चाहिए। उन बच्चियों के प्रति माननीय मुख्य मन्त्री जी चिन्तित हैं और उनके अधिकारों के प्रति भी उनके मन में बहुत कुछ है। इसी बात को लेकर मुख्य मन्त्री जी चिन्तित हैं। उन्होंने कहीं पर भी सम्पत्ति के अन्दर 2% बजट के अन्दर महिलाओं के नाम सम्पत्ति की रजिस्ट्रेशन में टैक्स को माफ किया है। उनको नौकरियों में 33% का आरक्षण दिया है कॉलेजिज तथा इन्जीनियरिंग कॉलेजिज में अगर वे प्रवेश करने के लिए जाएंगी तो उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है। अगर हाउसिंग बोर्ड या कहीं दूसरी जगहों पर प्लॉट के लिए ऐप्लाई करती हैं तो उसके अन्दर भी उनको आरक्षण की सुविधा दी गई है। यह सुविधा एक बहुत बड़ी सुविधा है जिसका लाभ उनको मिलने वाला है। सुविधा शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर भी है। अगर हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो दो परिवार पढ़ते हैं और अगर लड़का पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई एक ही परिवार तक सीमित रहती है। इस बात को केन्द्रित करते हुए उन्होंने एक महिला महाविद्यालय और एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। जहां पर हमारी बच्चियां जाकर बड़े शौक से पढ़ सकती हैं। आने वाले समय के अन्दर तकनीकी युग में प्रवेश करके महिलाएं हमारे भाईयों के साथ कंधे से कंधा मिला कर इस देश और प्रदेश के निर्माण में काम करेंगी। अध्यक्ष महोदय, जहां पर रोडज़ तथा पुलों की बात आती है तो किसी भी प्रदेश और देश की तरक्की उसकी आधारभूत संचरना से मापी जाती है। जहां पर 6 लेन, 8 लेन तथा 12 लेन रोडज़ होंगी जहां पर बड़े पुल और आर०ओ०बी० भी होंगे वहां पर आम आदमी आ कर यह कहेगा कि यह देश और प्रदेश बड़ी तरक्की पर है। आज तक इस प्रदेश की तरक्की की तरफ किसी व्यक्ति ने इतना ध्यान नहीं दिया। मुख्य मन्त्री आए और अपनी राजनैतिक रोटियां सेंक कर और व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करके चले गए लेकिन किसी व्यक्ति ने इस देश की इस हरियाणा प्रदेश की व्यथा को जानने का प्रयास नहीं किया। यह प्रदेश दिल्ली के इतना नजदीक है जिसके कारण हम हरियाणा को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पहले मुख्य मन्त्री हैं जिन्होंने इस बात को पहचाना और मन के अन्दर एक लक्ष्य लिया है कि हमने हरियाणा प्रदेश को नम्बर एक प्रदेश बनाना है। आज हरियाणा प्रदेश देश में दो नम्बर पर है। परसैंटेज आय में हमें दो नम्बर से दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हरियाणा प्रदेश को नम्बर एक पर लाना है इसमें कदापि कहीं पर दो राय नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं परिवहन व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। परिवहन के बारे में हरियाणा रोड़वेज की यह स्थिति है कि अगर हरियाणा रोड़वेज की बस कहीं से जाती है तो दूसरे प्रदेश की बसों में बैठी हुई सवारियां उनसे उतरकर हरियाणा रोडवेज की बसों की तरफ भागती हैं। जब उनसे ऐसा करने के बारे में पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि हरियाणा रोडवेज की बस तेजी से जाएगी, इसमें अच्छी सीटें होती हैं और इसमें बढ़िया सुविधा और बढ़िया सुरक्षा मिलती है। आज हरियाणा रोडवेज की एक्सीडैंट की रेशों 8 प्रतिशत है जो कि सारे देश के अन्दर सबसे कम आंकी गई है। इस साल हरियाणा रोडवेज में 500 नई बसें बदली गई हैं और 300 अगले साल बदलेंगे। हरियाणा रोडवेज 3500 गाड़ियों के बेड़े के साथ हर रोज़ 11 लाख लोगों को सवारी करवाती हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में इस तरह का बढ़िया परिवहन कोई और नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ जहां तक रोजगार और बेरोजगारी की बात आती है, इस बारे में हमारी सरकार ने सोचा और विचार किया कि हम एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं। हमारी सरकार ने इस बारे में यह सोचा कि जब तक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तब तक यह सरकार उसको रोजगार भत्ता देगी मजाक के तौर पर उसको 100-150 रुपए नहीं

देंगे बल्कि हमने उस बेरोजगारी भत्ते को 300 रुपए और 500 रुपए रखा है। आने वाले समय में 2 लाख करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश में निवेश होने का अन्दाजा है और यह असाउन्ट एस०ई०जैड के अन्दर लगाया जाएगा। इसके तहत 10 लाख लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी। इसकी वजह से हरियाणा की बेरोजगारी की समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब इसके अलावा मैं ग्रामीण विकास की बात करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर राजकीय विद्युतिकरण और दूसरी कई योजनाएं आई हैं। जिसके माध्यम से इस हरियाणा प्रदेश का विकास किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जब तक मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हैं तब तक इस प्रदेश के अन्दर किसी व्यक्ति को इस बात की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है कि उनको आगे जाकर क्या काम करना है। यहां पर हर हाथ को काम, हर मुंह को निवाला, हर साथी को मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा उस शख्सीयत का नाम है जो हंसते भी हैं हंसाते भी हैं, नजरों से नजरे मिलाते भी हैं, ये उनसे भी नजरे मिलाते हैं,जो इनसे नजरे चुराते हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) एक वक्त था जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते थे कि हमारे पास विपक्ष नहीं है। इसलिए हमें ही विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है। लेकिन हमारी सरकार को एक साल हो चुका है और हम आज यह देखना चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका कैसी होती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला जी जल्द से जल्द सदन में आएं और अपनी भूमिका यहां पर निभाएं । इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय-हिन्द।

श्री सुखबीर सिंह जोनपुरिया (सोहना): परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे सदन में बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामय सदन में 17 तारीख को 2006-07 का बहुत ही बढ़िया बजट रखा गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बजट में आम और गरीब आदमियों की जरूरत की सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत न हो। सबसे खुशी की बात तो यह है कि मैंने आज सुबह 5.00 बजे टी०वी० खोला तो उसमें यह देखा कि गुड़गांव और झज्जर का एस०ई०जैड में नम्बर आया है। मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश की तरक्की के लिए बड़े ही दृढ़ विश्वास से मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में जो एस०ई०जैड के थ्रू दो लाख करोड़ रुपए आ रहा है और उसको हरियाणा के 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे हरियाणा में बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। इसकी वजह से क्षेत्रीय रोजगार में बहुत वृद्धि हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे गुड़गांव में डी०सी० ने सभी इन्डस्ट्रीज वालों को बुलाकर एक कैम्प लगाया था और जहां पर बेरोजगारों को भी बुलाया था। वहां पर सभी का इन्टरव्यू लिया गया था। आज हर महीने ऐसी कार्यवाही होती है और उसमें ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को इन्डस्ट्रीज में रोजगार दिया जा रहा है। यह एक बहुत ही बढ़िया शुरूआत है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर 15 हजार एकड़ जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है। वह दिल्ली से जीरो किलोमीटर पर है अगर उस जमीन को भी एस०ई०जैड में ले लिया जाए तो उस जमीन का यूज भी हो जाएगा और हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, बजट में एक नई नीति के अनुसार 41 नई योजनाएं लाई गई हैं। जो कि पहले 35 थीं। उसमें ग्रामीण विकास योजना भी रखी गई है। इस योजना के तहत गांवों में बहुत अच्छा विकास हो सकेगा। जो चीजें पिछली बार बजट में नहीं रखी गई थीं वे सब इस बार ग्रामीण विकास योजना के अन्दर रखी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मद में जो बजट रखा गया है।

[श्री सुखबीर सिंह जोनपुरिया]

उस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा में जो रैशनेलाईजेशन हुआ था उसमें 2 स्ट्रीम थी, एक कामर्स और दूसरी साईंस । इसमें पहले यह था कि अगर किसी स्कूल में पांच बच्चे साईंस या कामर्स स्ट्रीम के लिए एडमिशन में विषय चुनते थे तो उस स्कूल में वह स्ट्रीम दे दी जाती थी। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक ग्रामीण विकास की बात है, सरकार ने अब 20 बच्चों के दाखिले पर साईंस और कामर्स सब्जैक्ट देना कम्पलसरी कर दिया है। अगर बीस बच्चे एक स्कूल में दाखिल नहीं हो पाते तो वह स्ट्रीम वहां से हटती जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि 20 बच्चों के बजाए यदि दस या पन्द्रह बच्चों के दाखिले का यह क्राईटेरिया कर दिया जाए तो यह अच्छा होगा क्योंकि इससे जो रूरल बच्चे हैं उनको भी इन स्ट्रीम्ज की ऐजुकेशन मिल सकेगी। अध्यक्ष महोदय, उनके पास सब्जैक्ट बचते हैं केवल आर्टस के और आर्टस के सब्जैक्टस को पढ़कर वे कहां जाएंगे ? इसलिए इसमें फेरबदल की जरूरत है।अध्यक्ष महोदय, जो बेरोजगारी है अभी तक उसके बारे में अहम फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि जो भी इंडस्ट्रीज के हरियाणा में लाईसेंस दिए जाएं उनमें पांच परसैंट, दस परसैंट या दो परसैंट या कुछ न कुछ ऐसा नियम बनाया जाए कि इतने परसैंट नौकरियां हरियाणा के बच्चों को ही देनी पड़ेंगी। अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में कम से कम पचास हजार लड़के दिल्ली से काल सैंटर्ज में काम करने के लिए आते हैं लेकिन उनमें हरियाणा का कोई भी बच्चा नहीं होता। जो क्वालिस या सूमो गाडियां चल रही हैं उनमें भी हरियाणा का कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। इसलिए इस बारे में ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आज हरियाणा में इतने उद्योग आ रहे हैं इनमें हरियाणा प्रदेश के बच्चों को रोजगार मिलना ही चाहिए। इसके अलावा मैं एक और सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि पिछली बार राजस्व में शराब के ठेकों से 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अब की बार मुख्यमंत्री जी ने और बढ़िया स्कीम इस बारे में निकाली है। इस बार जो शराब के ठेकों का ड्रा निकाला गया है उसमें जितने बेरोजगार थे उन सबको इसकी दुकानें मिल गयी है जो शराब माफिया पिछली सरकार के वक्त में था उसको इस बार यह ठेके नहीं दिए गए हैं। पिछली सरकार में टेलीफोन आ जाता था कि फलाने को ठेका दे दो। इस बार जो ड्रा निकाला गया है उसमें आम बच्चे को ड्रा में शामिल किया गया है। अब आम बच्चा भी अपना रोजगार चलाएगा। पहले तो इकट्ठे ही ठेके दे दिए जाया करते थे और वे अपनी मर्जी से इनको चलाते थे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं महिलाओं के बारे में कहना चाहूंगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि दो परसैंट की छूट स्टाम्प ड्यूटी में उनको दी गयी हो। महिलाओं के लिए 33 परसैंट रिजर्वेशन सैंट्रल गवर्नमैंट में भी पास नहीं हो पाया लेकिन हमारी इस सरकार ने महिलाओं को 33 परसैंट आरक्षण दिया है यह बहुत खुशी की बात है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा वीरों की धरती है। मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज में भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से आरक्षण दिया है। हमारे जो सैनिक हैं वह देश के बोर्डर पर देश की सेवा करते हैं। हमारी सरकार ने उन सबका उचित मान सम्मान किया है। अब वे भी यह सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने उनका ध्यान रखा है। अध्यक्ष महोदय, आज उन लोगों को मान सम्मान मिला है। यह सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पैंशन 1400 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दी है और 21 हजार रुपये स्वतंत्रता सेनानियों की लड़कियों की शादी में कन्यादान के लिए दिए गए हैं हालांकि यह बात बजट में नहीं लिखी गयी है लेकिन फिर भी यह एक सराहनीय कार्य है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद बिजली की बात है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले हरियाणा में 2000 मेगावाट बिजली ही बनती थी और दो हजार मेगावाट

बिजली हम बाहर से खरीदते थे लेकिन आज चार हजार मेगावाट बिजली बनाने के प्रोजैक्टस शुरू किए गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसको अभी और बढ़ाने की जरूरत है ताकि बिजली की पूर्ति हो सके। इसी तरह से बिजली की तारें पुरानी हो गई हैं और टूट टूट कर गिर रही हैं जिसकी वजह से बहुत ऐक्सीडैंटस होते हैं। मैं बिजली मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इनके लिए बजट में प्रावधान किया जाए और ये तारें बदली जाएं ताकि ये ऐक्सीडैंटस न हों। सिंचाई और जल निकासी की जहां तक बात है, इस मामले में मेवात क्षेत्र को हम अलग से पैकेज दे रहे हैं लेकिन जो गुड़गांव का ड्रेनेज और सीवरेज का आउटर पानी है अगर उसके लिए एक नहर बनाकर मेवात की तरफ ले जायी जाए तो सबसे अच्छी बात होगी क्योंकि इससे वहां पर आज जो पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। वह भी बढ़ जाएगा और जो वहां पर आज जमीन ड्राई हो गयी है, फालर हो गयी है उसमें भी काफी कमी आएगी। अभी जिस तरह से वहां पर नहर आई है उस की वजह से वहां की जमीन ठीक हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि मेवात को भी गुडगांव की तर्ज पर एक स्पैशल पैकेज दिया जाना चाहिए। गुड़गांव को 796 करोड़ रुपये का स्पैशल पैकेज दिया गया है यह मुख्यमंत्री जी ने बहुत सराहनीय काम किया है। स्पीकर सर, आज भी गुडगांव में ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है हालांकि फलाई ओवरों के माध्यम से सड़कों को कई जगह जोड़ा गया है। राजीव चौक का फलाई ओवर एक दो महीने में चालू होने वाला है। हीरो हौण्डा चौक, सदर थाने वाला रोड़, कादीपुर रोड़ आदि पर आठ-आठ सड़कों की लाईनें हैं इस प्रकार ये सारी 24 सड़कों की लाईनें इक्ट्ठी हो जाती हैं जिसके कारण वहां पर डेढ़-डेढ़ घण्टे तक जाम लगा रहता है। सरकार एम०एन०सीज० को बुलावा दे रही है अगर वे लोग वहां पर इतनी देर तक ट्रैफिक में उलझे हुए रहेंगे तो सरकार के लिए यह शर्मनाक बात होगी। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि इन रोडज के लिए सरकार को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इसके अलावा गुड़गांव से अलवर का जो रोड़ है वह बादशाहपुर तक तो आठ लाईन कर दिया गया है लेकिन उसको आगे आठ लाईन का नहीं किया गया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि उसको आगे भी बनाया जाए। इसके अलावा रेवाड़ी से पलवल तक जो नया हाई-वे बन रहा है। वह भी काफी सराहनीय कार्य है। स्पीकर सर, इसके अलावा जो सबसे अहम काम सरकार करने जा रही है वह है अम्बाला-जीरकपुर-कालका रोड़ को चार लाईन करने का बजट में प्रावधान करना। इस रोड़ पर चण्डीगढ़ आने में काफी समय लग जाता है। उसके लिए अलग से बजट दिया है यह बहुत सराहनीय कार्य किया है। स्पीकर सर, हमारे सोहना और नूह के लिए भी सीवर सिस्टम की व्यवस्था की गई है यह व्यवस्था पहले कभी नहीं की गई थी। यह बहुत सराहनीय कार्य किया है। इसके अलावा बजट में बस अड्डों पर रैन बसेरे बनाने की बात भी कही गई है यह भी सरकार की एक अच्छी उपलब्धि है क्योंकि ड्राईवर और कण्डक्टर इतने लम्बे-लम्बे रूटस से आते हैं जिसके कारण वे थक जाते हैं इसलिए उनको नहाने धोने और सोने की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। स्पीकर सर, बस अड्डों पर टॉयलेट और बॉथरूम तो होने ही चाहिएं। स्पीकर सर, गांवों में ट्यूबवैल्ज भी हैं और पेय जल के लिए सरकार ने पूरा पैसा भी दिया है। लेकिन मेवात एरिया में पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। जहां तक कानून-व्यवस्था की बात है, हमारे डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में पहले चोरियां काफी होती थीं अगर कोई बैंक में गया है और मोटरसाईकिल बाहर खड़ी की है तो बैंक से बाहर आने से पहले उसकी मोटरसाईकिल चोरी हो जाती थी। लेकिन पिछले 6 महीने से इन चोरियों में गिरावट आई है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Please do not make running commentary.

श्री सुखबीर सिंह जोनपुरिया : इसके अलावा सरकार ने जो पंचायतों को पूरे अधिकार दिए हैं वह भी एक सराहनीय कार्य है। पिछली सरकार ने ग्रामीण विकास सचिव के नाम से अपने प्रतिनिधियों को गांवों में बैठा दिया था लेकिन उनकी तनख्वाह उनको नहीं दी गई है। उनकी तनख्वाह अब दी जा रही है। इसके अलावा मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के में चौटाला साहब से समय नरसिंहपुर गांव में जमीन एक्वायर करने के लिए सैक्शन 4 का नोटिस जारी किया गया था उस समय लोगों ने चौटाला साहब को बुलाया और माला डाली लेकिन चौटाला साहब ने कहा कि माला इधर लाओ और सैक्शन 4 को भूल जाओ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उन लोगों की बात सुनी और उनको आश्वासन दिया कि इसके बारे में न्यायोचित जांच होगी और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जायेगा। इसके बाद इन लोगों को बहुत राहत मिली है। पहले जमीन का मुआवजा 4-5 लाख रुपये प्रति एकड़ मिलता था। लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 20-25 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दिया है। स्पीकर सर, फुटबाल एकेडमी का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक फुटबाल एकेडमी हमारे इलाके में भी बननी है ऐसा न हो कि वह इधर उधर कर दी जाए। अब गरीब आदमियों को अपने मकान बनाने के लिए 50 हजार रुपये देने का काम सरकार ने किया है। पहले यह 10 से 25 हजार रुपये तक जाते थे । मैं समझता हूं कि 50 हजार रुपये में एक कमरा और बरामदा तो बन ही सकता है। इसलिए यह बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार द्वारा किया गया है। स्पीकर सर, गरीब आदमियों को मकान या प्लाट सिर्फ कांग्रेस के राज में ही मिलते हैं।

Mr. Speaker : Please conclude. Other Hon'ble Members will also speak.

श्री सुखबीर सिंह जोनपुरिया : स्पीकर सर, गरीब आदमी का मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा है। स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डा० सुशील इंदौरा (ऐलनाबाद, एस०सी०) : स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर चर्चा करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर चर्चा करूं उससे पहले आपकी अनुमति से आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। पार्लियामैंट और विधान सभाओं में परम्परा रही है कि जब माननीय राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय की स्पीच होती है उस पर चर्चा की शुरूआत सरकार के किसी सदस्य की तरफ से की जाती है। यानि सरकार के किसी सदस्य द्वारा राज्यपाल महोदय की स्पीच पर चर्चा को परपोज किया जाता है। जब बजट पर चर्चा की शुरूआत होती है तो चाहे सिंगल लार्जैस्ट पार्टी का एक विपक्ष का हो एक ही सदस्य हो उसकी तरफ से चर्चा की शुरूआत की जाती है। उस समय अध्यक्ष महोदय, आप चेयर पर नहीं थे, मैंने चेयरपर्सन महोदय को यह बात कही थी।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई रूल नहीं है।

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वे सदन की परम्पराओं का ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : इंदौरा साहब, मैंने आपकी तरफ देखा था। उस समय आपने ऐसी कोई इंटैंशन शो नहीं की कि आप बोलना चाहते हैं और सदन की ऐसी कोई गलत परम्परा नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनको हरियाणा की जनता ने इस कदर नकारा है कि इनके नेता विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाये।

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा फर्ज सदन को अवगत करवाना था वह मैंने करवा दिया है।

Mr. Speaker : I will give you every priority without fair and impartial manner.

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इंदौरा साहब को बताना चाहूंगा कि जब इनकी पार्टी की सरकार थी तो उस समय मैं कई साल तक विपक्ष का नेता रहा हूं लेकिन मुझे एक बार भी बजट पर शुरूआत करने का अवसर नहीं दिया गया।

श्री आनंद सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के 6 सदस्यों को लगातार बोलने का अवसर दिया गया है, यह भी अपने आप में एक रिकार्ड है।

Mr. Speaker : Mr. Indora, please carry on your speech.

डा0 सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, 17 तारीख को माननीय वित्तमंत्री जी ने बजट सदन में रखा। माननीय वित्तमंत्री जी बड़े ही सुलझे हुए आदमी हैं। ये हर बात को बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, हर बात की इनको जानकारी है। ये एक खास तरीके से अपनी बात को रखते हैं । इनको पता है कि वित्तीय प्रबन्धन किस तरह रखे जाते हैं। चाहे वह वित्तीय प्रबन्धन पिछली सरकारों के रहे हों, चाहे इस सरकार के रहे हों, उनका श्रेय अपनी सरकार को किस प्रकार से दिया जाये इन बातों का वित्त मंत्री जी को पूरा अनुभव है और उसी तरीके से यह बजट इन्होंने पेश किया है। हमारे वित मंत्री जी लोक सभा में भी रहे हैं और विधान सभा में भी कई साल तक रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि पिछले विधान सभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की जनता ने प्रचण्ड बहुमत से जीत दिलवाई है। लोगों ने खुले दिल से कांग्रेस पार्टी को वोट दिए हैं। मैं समझता हूं कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी को इतना अधिक बहुमत हरियाणा में कभी नहीं मिला होगा। लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इस विश्वास के साथ वोट दिए थे कि नई सरकार बनेगी तो शायद अच्छे काम करेगी। लोगों को इस सरकार के बनने के बाद आशा थी कि अब प्रदेश में विकास के काम होंगे, बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी और विकास की नई-नई प्रपोजल बनेंगी तथा पिछली सरकार जो अधूरे काम छोड़कर गई थी उनको पूरा करेगी। लेकिन सरकार के इस बजट को देखते हुए हमें नहीं लगता कि यह सरकार लोगों की आशाओं पर पूरा उतर पायेगी। वित्त मंत्री जी ने अपना दूसरा बजट पेश किया है जिस समय पहला बजट पेश किया था उस समय हमने कुछ नहीं कहा। मैं बजट का विरोध इसलिए नहीं करूंगा कि मैं विपक्ष का सदस्य हूं। विरोधी पक्ष का सदस्य होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि सरकार को अच्छी बातें बताऊं और जो सही बातें हैं वही कहूं। उन पर सरकार सोचे और यदि सरकार हमारे से सलाह मश्विरा लेना चाहेगी तो हम देंगे। हम सरकार को यह भी बतायेंगे कि आप ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी जो पिछला बजट जल्द बाजी में लेकर आये थे उसी समय प्रदेश की जनता का चुनावी रंग छूटता नजर आ रहा था। लोग उस बजट को समझ नहीं पाये थे। लेकिन एक साल का अरसा बहुत होता है। शुरू में वित्त मन्त्री जी ने कहा कि एक साल का समय कम होता है फिर भी इसके बावजूद उन्होंने कहा कि एक साल से अरसे में हमने अच्छा वित्तीय प्रबन्धन किया। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रबन्ध करने का मतलब यह है कि आपने

[डा० सुशील इंदौरा]

जो योजनाएं बनाई हैं वह ज्यादा से ज्यादा 90-100% पूरी हो गई हों या गैर योजना का खर्च जो बीच बीच में आया है उसको घटाया जाए। राजस्व प्राप्तियां सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से मजबूत हों। राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले में खर्चों पर कण्ट्रोल किया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जिस तरह से कहा है कि इस देश के प्रधान मन्त्री डा० मनमोहन सिंह जी उस वक्त वित्त मन्त्री थे। डा० मनमोहन सिंह जी आर्थिक सुधार के लिए काम करने वाले एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और वे बहुत ही अच्छी नेचर के इन्सान हैं। हमारे दिल में उनके प्रति बहुत सम्मान है। वे आज सारे देश के प्रधान मन्त्री हैं। मैं माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी जिक्र करूंगा कि उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हालात ऐसे हो गए थे कि कांग्रेस पार्टी बिखराव पर थी। अध्यक्ष महोदय, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि इस बात का श्रेय स्वयं वित्त मन्त्री जी ने खुद को दिया। आज जो हरियाणा की स्थिति है उसका उचित वित्तीय प्रबन्धन की सलाह डा० मनमोहन सिंह जी ने दी थी। माननीय वित्त मन्त्री जी बड़े ही सुलझे हुए ढंग से बात करते हैं और अपनी बात को बड़ी चतुराई से मोड़ लेते हैं। उनमें यह खासियत है कि अगर इन्दौरा ने भी कुछ अच्छा काम किया हो तो उसका श्रेय भी वे स्वयं ले लें। मैं इसी लिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। इन्होंने जो श्रेय दिया वह डा० मनमोहन सिंह को दिया और श्रीमती सोनियां गांधी को दिया लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि नवम्बर, 1999 में जो वित्तीय प्रबन्धन की शुरूआत हुई थी वह कांग्रेस पार्टी के राज में नहीं हुई थी, हालांकि डा० मनमोहन सिंह जी ने अच्छे प्रयास किए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी कहता हूं कि उस वक्त सारे हिन्दुस्तान में ज्यादातर प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं। उस वक्त इस वित्तीय प्रबन्धन में जो सुधार उन्होंने पेश किए थे कांग्रेस पार्टी शासित प्रदेशों की सरकारों ने उन्हें मानने से इन्कार कर दिया था। जब नवम्बर, 1999 में एन०डी०ए० की सरकार थी और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधान मन्त्री थे तब उन्होंने प्रदेश के मुख्यमन्त्रियों की एक बैठक बुलाई थी ताकि सारे हिन्दुस्तान में सामाजिक समता और समानरूपता के साथ जो टैक्स प्रणाली है जो वित्तीय प्रबन्धन है जो तरीके हैं उनको सुचारू रूप से लागू किया जाए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमन्त्रियों की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में आर्थिक सुधारों की चर्चा हुई। आर्थिक सुधारों की चर्चा में तीन मुद्दे खुलकर सामने आये थे। तब उन्होंने कहा था कि यूनिफोर्म फ्लोर रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए,दूसरे जो इण्डस्ट्रियल इनसैन्टिव रिगार्डिंग सेल्ज टैक्स और तीसरा था वैट यानि वैल्यू ऐडिड टैक्स। इसी तरह से उन्होंने स्टेट के फाईनैंस मिनिस्टर्ज की ऐम्पावरड कमेटी भी बनाई थी ताकि उस पर चर्चा हो। इस पर काफी चर्चा हुई और लम्बी बहस के बाद यूनिफोर्म फ्लोर रेट ऑफ टैक्सिस के बारे में इण्डस्ट्रियल इन्सैंटिव रिगार्डिंग सेल्ज टैक्स के बारे में भी विचार किया गया और वैट के मामले में भी बहस हुई और इस बहस में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने वैट का विरोध किया था। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जिसने उस वक्त के हालात में सबसे पहले वैट को लागू किया था। आज बड़े हर्ष की बात है और उसको माननीय वित्त मन्त्री जी ने भी माना है कि वैट से फायदा हुआ है। आज लगभग पूरे हिन्दुस्तान में लोगों ने वैट प्रणाली को लागू किया है। वित्तमन्त्री जी बैठे हुए हैं वे बड़े ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हैं और विदेशों में भी जाते रहे हैं और इनको याद भी होगा। इन्होंने यह महसूस भी किया होगा कि जर्मनी और यूरोपियन कण्ट्रीज में दीवार खिंची हुई थी। फ्रांस से इनकी बड़ी लड़ाई थी और उन्होंने एक होकर यूरो को लागू किया और अमेरिकन डॉलर को पीट दिया। हमारे यहां पर उस वक्त हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश

चौटाला जी के नेतृत्व वाली सरकार थी और उन्होंने बड़े साहस का कदम उठाया। एक साहसिक कदम उठाते हुए उन्होंने सोचा कि जब ये कण्ट्रीज इकट्ठे हो सकते हैं तो हमारे देश के जो 31 प्रदेश हैं अगर वे वैट प्रणाली को लागू करें तो उनको नेतृत्व कौन देगा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के लोगों में देने की हिम्मत नहीं थी। वे पीछे-पीछे तो जा सकते हैं लेकिन आगे बढ़कर नेतृत्व देने की बात कभी नहीं कर सकते है। नेतृत्व देने वाले लोग तो बहुत साहसी होते हैं और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नेतृत्व देने के लिए आगे आए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में वैट लागू किया था। आज अगर आप उस समय के लोक सभा और विधान सभा के चुनावों के समय के अखबार देखें तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हर वर्ग के लोगों को भड़काया था और व्यापारियों को भड़काया था। अगर उस वक्त थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ती थी तो कहते थे कि वैट का असर पड़ गया है। अगर कनक नहीं बिकी तो कहने लग जाते थे कि वैट के कारण ऐसा हुआ है। कांग्रेस के प्रचारकों ने हर जगह जा-जा कर यह कहा कि वैट खा गया। इनका तो चुनावी मुद्दा था कि हम सत्ता में आएंगे तो वैट को खत्म कर देंगे। फार्म 38 खत्म कर देंगे। (शोर एवं व्यवधान) अगर यह कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं था तो इस बारे में प्रचार क्यों किया था (शोर एवं व्यवधान)

वित्तमंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य ने वैट के बारे में यह कहा कि कांग्रेसियों ने या कांग्रेस पार्टी ने वैट का विरोध हरियाणा में किया था। इनकी यह बात बिल्कुल ही निराधार है। स्पीकर सर, उस वक्त आप भी हाऊस में होते थे और आज के मुख्यमंत्री जी भी हमारे लीडर आफ दि अपोजीशन हुआ करते थे। हमने जनता में भी और सदन में भी बार-बार यह कहा था वैट को अगर कोई इन आईसोलेशन इन्ट्रोडयूस करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। इन्दौरा जी, आप एक बात समझिए कि अगर वाजपेयी जी ने इतना बड़ा कदम उठाया था तो उनकी भी लोक सभा में सरकार थी हरियाणा में भी उनकी स्पोर्ट से ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। उसको लागू करने में ओम प्रकाश चौटाला जी का अकेले का ही थोड़े ठेका था। अगर ऐसा था तो बी०जे०पी० की सरकारों से वैट लागू करवाते। आज भी राजस्थान में बी०जे०पी० की सरकार है और वे भी फर्स्ट अप्रैल से वैट लागू कर रहे हैं । आज भी उत्तर प्रदेश में वैट लागू नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमने उस वक्त यह कहा था कि जब भी यूनिफार्मली देश में वैट लागू होगा तो हम उसके पक्षधर होंगे। हमने कभी वैट का विरोध नहीं किया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने इस बात को बड़ी भूमिका बनाकर सदन में कहा है कि ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत बड़ा काम किया है। हमने कभी भी वैट का विरोध नहीं किया है।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि इस देश में किसी न किसी को लीडरशीप देनी ही थी। यह बड़े ही गर्व की बात है और आप लोगों को भी इस बात के लिए गर्व करना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश ने हिन्दुस्तान में वैट लागू करने में देश को लीडरशीप दी है। इस बात को तो आप मानेंगे। उस वक्त आपने जन सभाओं में कहा था कि हम फार्म 38 को खत्म कर देंगे।

श्री एस0एस0 सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। श्री इन्दौरा जी, एक्चुअली आपने लीडरशीप नहीं ली थी, आपने व्यापारियों की रड़क काडन खातर वैट लगाया था, असल बात तो यही थी। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो कहा है यही कांग्रेस ने कहा था कि इसको

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

हम रैशनेलाईज करेंगे तो ही लागू करेंगे और दूसरे अगर हिन्दुस्तान में सब जगहों पर इक्ट्ठा वैट लागू होगा तब हम लागू करेंगे। लेकिन आपने तो व्यापारियों को सजा देने के लिए वैट लागू करा था, इसके अलावा आपको पार्लियामैंट में पर्ची नहीं मिली थी इसलिए भी लागू किया था।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी जो चर्चा कर रहे हैं उस वक्त मैं विपक्ष का नेता था। उस समय मैंने सदन में कहा था कि हम वैट के विरोधी नहीं है लेकिन वैट को जो इस आइसोलेशन लागू किया है उस की वजह से किसान जो धान पैदा करता है। उसका कई सौ करोड़ रुपयो का नुक्सान हुआ है। हमारे यहां पर जितने भी शैलर्ज थे उन्होंने पलायन किया था और प्रदेश का उसकी वजह से बहुत नुक्सान हुआ था।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आज भी वही बात है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जनता को उस वक्त भड़काने को जो काम किया गया था उसकी वजह से हमारी पार्टी को बहुत राजनीतिक नुक्सान हुआ है। हमें इतना राजनीतिक नुक्सान हुआ कि आज हमें अपोजीशन में बैठना पड़ा। (शोर एवं व्यवधान)

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हरियाणा में जो लूट खसौट, भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी की थी उसकी वजह से हरियाणा के लोगों ने यहां पर इनको बिठाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) इन्दौरा जी, आपके नेता हैं और वे बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज् आप अपनी सीटों पर बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं खुलकर कह रहा हूं कि हमें इससे राजनैतिक तौर पर बहुत नुक्सान हुआ है और उस नुक्सान को हमने सारे हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए सहा है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि हमारी सरकार के समय वित्तीय प्रबन्धन बहुत बढ़िया था लेकिन आज यह बखान किया जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश पर कैपिटा इन्कम में नम्बर वन है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यह किसकी देन है ? इसकी शुरूआत तो हमने की थी।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, हमने एक परिवार की इन्कम जरूर कम की है जबकि पूरे हरियाणा के लोगों की पर कैपिटा इन्कम को हमने बढ़ाया है और हम इसको और बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं।

डा0 सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, उस समय जन सभाओं में कांग्रेस के नेताओं ने एक ही बात कही थी। इन्होंने कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जो उस समय टैक्सों का बोझ करोड़ों का लाद दिया गया था वह हम हटाएंगे। इन्होंने उस समय यह भी कहा था कि हम वैट को खत्म करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमने तो हलवाईयों का टैक्स भी हटाया और किसानों के बिजली के बिलों के बकाया 1600 करोड़ रुपये भी मुआफ किए हैं।

डा0 सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, क्या वित्त मंत्री जी अपने जवाब में यह भी बताएंगे कि वेट को छोड़कर कितने रुपयों का टैक्स इन्होंने घटाया है ? (विघ्न)

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, मैंने अपनी बजट स्पीच में भी यह कहा था और जैसा कि सुरजेवाला जी ने भी कहा कि हमने यह कहा था कि जब सारे देश में वैट इंट्रोडयूज होगा तो हम भी इसको इंट्रोडयूज करेंगे और जो अब्रैशन ओम प्रकाश चौटाला के समय में इसमें रह गयी थीं उनको हम ठीक करेंगे। स्पीकर सर, जो इस बारे में हाई पावर कमेटी बनी थी उसने भी अपनी रिकमंडेशन दी है। विनोद शर्मा जी उस समय एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर थे। डा0 साहब, 193 करोड़ रुपया तो हमने अब भी इसमें घटाया है।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के वक्त में यानी 2003-04 में वित्तीय प्रबन्धन अच्छा था और पर कैपिटा इन्कम भी अच्छी थी। अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति तब तक मजबूत नहीं होती जब तक उसके योजनागत खर्चे सही न हों। गैर योजनागत खर्चे घटाने और योजनागत खर्चों को बढ़ाने से प्रदेश को आर्थिक मजबूती मिलती है। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे 2004-05 के पिछले रिकार्ड को देखें।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, आपको बोलते हुए बीस मिनट हो गये हैं।

डा० सुशील इन्दौरा : सर, मेरा आधा टाईम तो इन्होंने ही ले लिया है। मैं तो पांच मिनट भी नहीं बोल पाया हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इनको बोलने के लिए और समय दे दिया जाए।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री की प्रार्थना पर बोलने के लिए वक्त नहीं लेना चाहता। अगर आप कहें तो मैं अभी बैठ जाता हूं लेकिन जो हमारा हक है वह हमें मिलना ही चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जितना समय ये बोलने के लिए लेना चाहें उतना समय आप इनको दे दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर में इनकी बात अपने आप ही खत्म हो जाया करती हैं।

डा० सुशील इन्दौरा : अगर योजनागत तरीके से खर्चा किया जाए और उन पर कंट्रोल किया जाए तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर योजनागत खर्चे बढ़ते जायेंगे तो फिर आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो सकती है ?

Mr. Speaker : Indora Ji, repeatedly you are saying the same thing. आप पांच मिनट से वित्तीय प्रबन्धन के बारे में ही बात कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, जिस तरीके से वर्ष 2004-05 में योजनागत बढ़ौत्तरी हुई है वह है 11.5 प्रतिशत। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वर्ष 2005-06 में वे इस बढ़ौत्तरी को 42 प्रतिशत पर ले आये हैं। उसका कारण भी मैं बता देता हूं कि सरकार को केन्द्र सरकार से एकमुश्त खासा पैसा मिल गया होगा। उससे हमने समझा कि जिस रफ्तार से वे शुरू में चले थे अगर उसी रफ्तार से ही चलते तो शायद मेरे प्रदेश के लोगों को बहुत खुशी होती क्योंकि अगर ऐसा होता तो हरियाणा प्रदेश बहुत प्रगति करता। जो बढ़ौत्तरी ये वर्ष

[डा० सुशील इन्दौरा]

2005-2006 में 42 प्रतिशत पर लाये थे वह बढौत्तरी अब वर्ष 2006-2007 के बजट में 7.86 प्रतिशत दिखाई गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी विभाग के मद में पैसा कम दिया गया होगा। आज बढ़ती महंगाई में हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं चाहे वह सीमैंट हो, लोहा हो। आज मैं यह बात कह सकता हूं कि किसी सड़क पर काम नहीं चल रहा है, किसी नहर पर काम नहीं चल रहा है और न ही कोई नया बिजली प्रोजैक्ट बना रहे हैं। हमारे मंत्री जी बैठे हैं उनको सिरसा शहर की अच्छी जानकारी है वे दिखा दें कि कहीं पर काम चल रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं कि जो खर्चे पिछले साल के बजट में डाले थे वही खर्चे इस साल के बजट में भी डाल रखे हैं हालांकि उनमें बढ़ौत्तरी होनी चाहिए। होना यह चाहिए था कि उन मदों में ज्यादा पैसा डाललें तो हमारा विकास होता लेकिन पिछले साल जो पैसा डाला था उतना ही पैसा अब डाला है। जैसे एच०ए०यू० में और दूसरे डिपार्टमैंटस में जैसे फोरेस्ट, फिशरीज, वाईल्ड लाईफ, काडा, सिविल एविएशन, रोड़ ट्रांसपोर्ट, नॉन कन्वैन्शनल एनर्जी, एनवायर्नमैंट, आयुर्वेदा, एन०सी०आर० अर्बन डिवैलपमैंट और बिजली आदि । यह आपके बजट एट ए ग्लांस के पेज नं0 20 पर लिखा है। रोड़ पर देखिये। रोड ट्रांसपोर्ट पर पीछे 2005-06 में revised outlay 7800 था और जो अब है वह भी 7800 है। इसी तरह से अगर आप देखें टूरिज्म पर 1000 लाख रुपये था यानि 10 करोड़ रुपये उसमें कम करके 800 लाख रुपये यानि 8 करोड़ रुपये कर दिया गया। टूरिज्म मिनिस्टर यहां बैठी हुई हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि टूरिज्म पर बजट कम करने से काम कैसे चलेगा इसी तरह से साईंस एंड टैक्नोलोजी में देखें 410 लाख रुपये यानि लगभग 4 करोड़ रुपये था जिसे अब 3 करोड़ रुपये कर दिया गया। ऐसे बहुत से विभाग हैं जिनका बजट कम किया गया है। यदि मैं सारे गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जायेगा। किसी में बराबर-बराबर भी रखा हुआ है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप प्लान एक्सपैंडीचर की बात कर रहे हैं या नॉन प्लान एक्सपैंडीचर की बात कर रहे हैं।

डा0 सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, मैं प्लान एक्सपैंडीचर की ही बात कर रहा हूं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोडज में 37.26 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी है। इसमें हमने 141 करोड़ रुपये से 194 करोड़ रुपये किया है। यानि 53 करोड़ रुपये की बढ़ौत्तरी है जो 37.26 प्रतिशत बनती है।

डा0 सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, बजट एट ए ग्लांस मेरे हाथ में है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, शायद आप नॉन प्लान की बात कर रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि आप नॉन प्लान एक्सपैंडीचर की बात कर रहे हैं या प्लान एक्सपैंडीचर की बात कर रहे हैं।

डा0 सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, मैं पढ़कर सुना देता हूं। यह देखिये 9th & 10th five year plan and annual plan 2006-07 इस पर लिखा है। आप देख लिजिए । मेरे हाथ में है। You can see yourself.

श्री अध्यक्ष : यह फाईव ईयर प्लान का नहीं है, इस साल का है। (विघ्न)

डा० सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, एनुअल प्लान भी इसी में लिखा हुआ है या तो यह गलत छप गई होगी। यदि गलत छप गई है तो इसे ठीक करवा लीजिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप वही बात क्यों कहते हो जो डाक्टर सीता राम कहते हैं। Indora Ji, you are repeating the same thing. You are an intelligent man. You are a seasoned parliamentarian. Please come to the point and speak on the Budget.

डा० सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, मैं बजट स्पीच पर ही आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जिन मदों में बजट घटाया गया है। जैसे एग्रीकल्चर सैक्टर है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है यहां की ज्यादातर जनता कृषि पर आधारित है। यदि ऐसे प्रदेश में एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए बजट कम किया जायेगा तो प्रदेश के हित में नहीं होगा। यह अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर सैक्टर के साथ-साथ हम टर्सरी सैकेण्डरी सैक्टर की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि बजट में लिखा हुआ है। यह अच्छी बात है कि हमने ट्रर्सरी और सैकेण्डरी सैक्टर में इम्प्रूव किया है। लेकिन कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण हमें एग्रीकल्चर सैक्टर की तरफ भी पूरा ध्यान देना होगा। जैसे वर्तमान केन्द्र की सरकार बाहर से 1100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं मंगवा रही है इसलिए ऐसा न हो जाये कि हम वहीं की वहीं पर रह जायें इसलिए हमें एग्रीकल्चर सैक्टर की तरफ भी पूरा ध्यान देना होगा। ऐसी बातों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त जैसे रूरल डिवैल्पमैंट है, कम्युनिटी डिवैल्पमैंट है, कोआपरेटिव है, विलेज एंड स्माल इण्डस्ट्रिज है, लार्ज एंड मीडियम इण्डस्ट्रिज है, इलैक्ट्रोनिक्स है, इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी है। इनकी तरह भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी का जमाना है लेकिन उसमें भी पैसा घटाया गया है। साईंस और टूरिज्म में भी पैसा घटाया गया है। अध्यक्ष महदोय, जहां तक शिक्षा का संबंध है, शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया था। यह बात सरकार भी कहती है कि ये भी बहुत कुछ कर रहे हैं और शिक्षा का हाल देखिये 2003-04 में जनरल एजुकेशन जैसे प्राईमरी है, मिडल है, सैकेण्डरी है उसके लिए 104.94 करोड़ का बजट था।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप यह भी बतायें कि उस समय टोटल प्लान कितनी थी ?

डा० सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, ये आंकड़े मैं निकाल देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने यह आंकडा तो निकाल लिया। आप एनुवल प्लान बतायें कि 2003-04 में एनुवल प्लान कितनी थी और please you carry on your speech on budget.

डा० सुशील इन्दौरा : वित्त मन्त्री जी, आप जरा सुनिये। वर्ष 2005-06 में ऐजुकेशन के लिए हमने 55% पैसा बढ़ाया था और आपने शिक्षा का बजट 37% रखा है। वर्ष 2006-07 में मैं यह 26% कैलकुलेट कर रहा था। हो सकता है कि मेरी कैल्कुलेशन में कोई गलती हो। आपने शिक्षा के बजट को 26-27 प्रतिशत कर दिया है यह बात इसलिए रख रहा हूं कि इसी से झलकता है कि कितना विकास हो रहा है सरकार की जो मन्शा है कि हम विकास करेंगे, नये-नये प्रोजैक्ट लगाएंगे, नये-नये काम करेंगे, जब बजट में पैसा ही नहीं होगा तो कैसे यह सब करेंगे यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि ये बताएं कि जब मदों में पैसा घटा रहे हैं बजट में आपने पैसे का प्रावधान नहीं किया है तो ये आप ऊंची-ऊंची जो बातें लोगों के बीच कह कर आते हैं उनको पूरा कैसे करेंगे। अभी हिसार में कांग्रेस

[डा० सुशील इन्दौरा]

पार्टी की रैली हुई थी वहां पर रैली में स्पीच के बीच कहा कि राजीव गांधी बीमा योजना लागू करेंगे लेकिन बजट में उसका कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है। वित्त मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं वे बताएं कि क्या इसके लिए कहीं पर बजट में कोई प्रावधान किया गया है ? इसका बजट में कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है। वित्त मन्त्री जी को इसके लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए। पिछली बार शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा था कि हम मॉडल स्कूल खोलेंगे। इस सरकार को बने हुए एक साल का समय हो गया है लेकिन आज तक सरकार एक भी मॉडल स्कूल पूरा नहीं कर पाई है। राजीव गांधी ऐजुकेशन सिटी के बारे में कहा गया है। राजीव गांधी जी बहुत अच्छे इन्सान थे। उनके नाम पर ये कहते हैं कि कुण्डली जिला सोनीपत में राजीव गांधी ऐजुकेशन सिटी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ऐजुकेशन सुविधा दी जाएगी। जब मैं वहां पर जाता हूं तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वहां पर कम से कम एक साल में कुछ तो करते। इसका नींव पत्थर ही कहीं रखते, कोई ईंट लगाते या कुछ और कार्य करते। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो अच्छे काम किये हैं मैंने उनके लिए सरकार की तारीफ भी की है। वित्त मन्त्री जी से मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि वे मेरी बात पर गौर करें और कुछ करके तो दिखाइये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं नॉन प्लान बजट की बात बताता हूं।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आपको बोलते हुए 32-33 मिनट हो गए हैं। जब बजट रखा गया था तो उसमें एक घण्टा लगा था लेकिन आपको बोलते हुए 33 मिनट हो चुके हैं।

डा० सुशील इन्दौरा : वित्तीय प्रबन्धन आर्थिक मजबूती का आधार है। गैर योजनागत खर्च हम घटाएं और इसे कम से कम लैवल पर लाएं ताकि हम वह पैसा विकास कार्य पर लगा सकें। मैं यह कहता हूं कि वर्ष 2003-04 में यह 10563 करोड़ रुपये था और बाद में यह घट कर 9806 करोड़ रुपये हो गया है। चालू वित्तवर्ष 2006-07 में यह आपने बताया कि 11213 करोड़ रुपये हो गया है। 2006-07 में अनुमानित जो आपने दिया वह 11903 करोड़ रुपये है यानि कि इसमें कोई खास डिफरैंस नहीं है। थोड़ा सा प्रयास किया है। अनुमानित में घटाने का तो इस तरह से जो खर्च हमने और हमारी सरकार ने घटाया था वह हमारे वित्तीय प्रबन्धन से घटा जोकि आहिस्ते-आहिस्ते बढ़ने लगा है। मुझे इस बात की शंका है कि आप वायदे करते हैं या जनता से बात करते हैं कि हम पूरी स्पीड से काम करेंगे लेकिन काम कैसे करेंगे। मैंने खुद कहा है कि 42% बजट बढ़ाने की आपने कोशिश की थी। लेकिन अगर खर्च ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे और भी बढ़ेगा। यह तो अनुमानित है और आगे हो सकता है कि यह योजनागत खर्चा इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हमारे कण्ट्रोल से बाहर हो जाए। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : इन्दौरा जी, आप कुछ हिसाब लगाएं कि आपकी सरकार में सारा बजट साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपए का था और अब 17 हजार करोड़ रुपए का है। उसी रेशों से तो घटता बढ़ता रहता है।

डा० सुशील इन्दौरा : वह तो मैंने मान लिया है। लेकिन उसी रेशों में परसैंटेज से भी देखिए और उसको परसैंटेज में घटाईए।

श्री बीरेन्द्र सिंह : यही तो समझने की बात है। आप घाटे को देखिए, हम घाटे को 980

करोड़ से 320 करोड़ तक लेकर आए हैं। आप यह देखें कि आपके वक्त में 980 करोड़ रुपए का डैफिशिट था।

डा० सुशील इन्दौरा : वह फिसकल डैफिशिट था।

श्री बीरेन्द्र सिंह : नहीं नहीं, जो प्रोजैक्शन था उसमें 600 करोड़ रुपए का डाउन आया है। और उस में नॉन प्लान का मेन कन्ट्रीब्यूशन है।

डा० सुशील इन्दौरा : सर, मैं भी तो यही कह रहा हूं। इसको और कम लाएं। हमने तो इसको और भी कम ला दिया था। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से 2005-06 में राजकोषीय घाटा 1873 करोड़ रुपए बढ़ गया था, उसको इन्होंने थोड़ा सा कम करके 1843 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नैगलीजिबल सी बात है। मैं इस बारे में कोई कमैन्ट नहीं करूंगा। लेकिन यह कहना चाहूंगा कि यह जो इन्होंने प्रयास किया है इससे सरकार को कुछ तो फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कर्जे की बात करता हूं। अगर हमारी सरकार पर और स्टेट पर कर्जा रहेगा तो वह प्रदेश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमने कर्जे को कम करते-करते 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत तक करने की बात थी। लेकिन आपकी जिस तरह से कर्जे लेने की स्पीड आज कल चल रही है तो कहीं ऐसा न हो कि यह 100 प्रतिशत हो जाए और हम कर्जे के बोझ के नीचे दब जाएं और हरियाणा प्रदेश प्रगति न कर सके। सर, इसके बाद तनख्वाह और पैंशन के खर्चे पर आता हूं। किसी भी सरकार की महत्ता इसी बात से आंकी जाती है कि वह अपने इम्पालाईज को अच्छी सुविधा दे लेकिन उन खर्चों को लिमिट में भी रखे। 1988 में हमारे समय में इम्पालाईज की तनख्वाह और पैंशन पर खर्चा 59 प्रतिशत था उसको हम घटाकर 2005 में 40.9 प्रतिशत पर ले आए थे। आपने इसको और घटाकर 39.55 प्रतिशत पर ला दिया है। आपका इस बारे में जो प्रोजैक्टिव खर्चा है वह 39.47 प्रतिशत है। यह तो लिमिट में है। अध्यक्ष महोदय, इससे मुझे हैरानी इस बात की होती है कि ये बजट में तनख्वाह को कम करने की बात करते हैं और मुख्यमंत्री जी दूसरी तरफ 4000 कांस्टेब्लज को भर्ती करने की बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कहीं पर टीचर्ज की भर्ती करेंगे या यह करेंगे या वह करेंगे। अब आप खुद ही देखें कि आप तनख्वाह पर खर्च को बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। हिसाब तो यह होना चाहिए कि 40 प्रतिशत तनख्वाह पर और 60 प्रतिशत विकास पर खर्च होना चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आप आज कर रहे हैं इसकी वजह से कहीं यह उल्टा ही न हो जाए कि 60 प्रतिशत तनख्वाह पर और 40 प्रतिशत विकास पर खर्च हो । (शोर एवं व्यवधान) This is not manageable. सर, इन्होंने 1-1-2006 में पैंशन देने के बारे में भी कहा है। इस पैंशन का शुरु में तो असर नहीं पड़ेगा लेकिन बाद में प्रदेश पर और इम्पलाईज पर इसका असर जरूर पढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष: आप कन्कल्यूड करें। आपको बोलते हुए 40 मिनट हो गए हैं। बाकी मैम्बर्ज ने भी बोलना है।

डा० सुशील इन्दौरा : सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 10-15 मिनट में कन्कल्यूड कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक अहम बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी किसी रैली में कहा है कि ये उन इम्पलाईज को दोबारा से भर्ती करेंगे जिनको नौकरियों से निकाला गया था। उनको भर्ती करने के लिए इन्होंने मिनिस्टर्ज की एक कमेटी भी बनाई है। इन इम्पलाईज को निकालने का

[डा० सुशील इन्दौरा]

लांछन ये हमारे उपर लगाते हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि उन इम्पलाईज को ये कहीं न कहीं अडजैस्ट करेंगे। इन्होंने यह भी कहा था कि उस कमेटी की रिपोर्ट 18-3-06 को आ जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि वे इम्पालईज कैसे आश्वास्त हों, क्योंकि उन इम्पलाईज का जिक्र तक इन्होंने इस बजट में नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, हर आदमी बजट की तरफ देखता है कि अगर कोई बात बजट में आएगी तो ही वह लागू होगी। (शोर एवं व्यवधान) आप उन इम्पलाईज के लिए बजट में प्रावधान रखते कि आप उन इम्पलाईज को लगाएंगे तो उनको इतनी तनख्वाह देनी पड़ेगी।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, बजट में उनका जिक्र होता है जो सरकारी मुलाजिम होते हैं। इनकी सरकार ने कोरपोरेशंज, बोर्ड और फैडरेशन के इम्पलाईज को नौकरियों से हटाया था लेकिन इनका जिक्र बजट स्पीच में नहीं किया जाता। हालांकि हमने इनके बारे में डिसीजन लेना था इसलिए मेहरबानी करके इनको इन बातों को समझना चाहिए कि मैंने क्यों इनका अपनी बजट स्पीच में जिक्र नहीं किया? अगर कोई पोलिसी डिसीजन होगा तो मुख्यमंत्री जी का इस बारे में बयान आएगा लेकिन बजट में इनका जिक्र नहीं होता।

राजस्व मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी को यह बताना चाहिए कि इनकी सरकार ने कितने आदमी हटाये थे ? इनको इस बात का जवाब देना चाहिए। इन्होंने बीस हजार आदमी हटा दिए थे। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, बोर्ड और कोरपोरेशंज तथा सरकारी मुलाजिम दो तरह के इम्पलाईज का मसला हमारे सामने हैं। एक मसला तो बोर्ड एवं फैडरेशन इम्पलाईज का है और दूसरा मसला सरकारी इम्पलाईज का है। ये अभी 18 तारीख की बात कर रहे थे मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस तारीख को बोर्ड और कोरपोरेशंज के निकाले गये इम्पलाईज के बारे में हमने रिपोर्ट देनी है लेकिन इन लोगों का बजट में जिक्र नहीं किया जाता।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, जिस तरह से इन्होंने दूसरे मामलों में हरियाणा प्रदेश के लोगों को आश्वासन दिया है वैसे ही इस बारे में भी ये उनको आश्वासन दे सकते थे। बजट में कहा गया है कि सरकार एस०वाई०एल० कैनाल बनवाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इन्होंने यह भी कहा है कि सरकार इस मामले को कोर्ट में अच्छी तरह से प्लीड करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह बात कहना चाहता हूं कि पंजाब विधान सभा ने जो टर्मीनेशन ऑफ वाटर ट्रीटी ऐक्ट पास किया था वह तो कोर्ट में पैंडिंग है लेकिन एस०वाई०एल० कैनाल के निर्माण से संबंधित कोई भी मामला देश की किसी कोर्ट में लम्बित नहीं है इसलिए सरकार प्रयास करे और इस कैनालको बनवाना शुरू करे। इसके बारे में तो कोई भी मामला पैंडिंग नहीं है सिर्फ टर्मीनेशन आफ वाटर ट्रीटी ऐक्ट कोर्ट में लम्बित पड़ा है।

श्री आनन्द सिंह डांगी : आप यह भी बता दें कि यह मुद्दा कब से पैंडिंग पड़ा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने अपने वकीलों से इस मामले में अरली हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाने के लिए कहा है लेकिन इनकी सरकार के समय में ऐसा कभी भी नहीं किया

गया। इन्होंने अपने समय में कभी भी सुप्रीम कोर्ट में ऐप्रोच नहीं किया कि जल्दी हीयरिंग की जाए क्योंकि इनकी नीयत में खोट था। जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे वे हमेशा ही हमारे हिस्से का पानी लेते रहे थे। अगर एस०वाई०एल० कैनाल बनती तो उनके सिरसा के इलाके को नुक्सान होने वाला था इसलिए इस मामले को जानबूझकर लटकाये रखा गया। वे हमेशा इस मामले को लेकर राजनीति करते रहे। लेकिन हमारी सरकार ने अपने वकीलों से कहा कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में जल्दी हीयरिंग करवायी जाए। जबकि ये कह रहे हैं कि यह मामला पैंडिंग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब इस बारे में सारे ऐग्रीमैन्ट खत्म हो गये तो ये इस तरह की बातें करके हाउस को मिसलीड क्यों कर रहे हैं।

डा० सुशील इन्दौरा : सर, अब मैं सबसिडी की बात पर आता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी मेरी बात को सुन रहे हैं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। रिकार्ड को ठीक करने के बारे में तो इनको ज्ञान होता नहीं है। किसी बात को जानकर भी ये डिसटोर्ट करते हैं। जब पंजाब असैम्बली ने टर्मीनेशन ऑफ वाटर ट्रीटी ऐक्ट पास कर दिया और हरियाणा के साथ हुए पहले ऐग्रीमैंट कैंसिल कर दिए तथा वे अमैंडमैंट वगैरा हाउस में लेकर आये थे तो उस समय ओम प्रकाश चौटाला का राज था। उसके कई महीने बाद भी वे मुख्यमंत्री रहे थे और सैंटर में भी इनकी सरकार थी लेकिन इन्होंने जानबूझकर इस बारे में कुछ नहीं किया। इसलिए अब हरियाणा की जनता इनसे जवाब मांगती है कि क्या ये बताएंगे कि हरियाणा का नुक्सान पंजाब सरकार ने जिसमें अकाली भी शामिल थे, किया या नहीं ? हरियाणा का बहुत बड़ा नुक्सान पंजाब वालों ने किया क्योंकि ये अकालियों और बादल के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते थे इसलिए इस मामले में कुछ नहीं किया। यह हरियाणा के हितों की रक्षा करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हैं। यह हमेशा अकालियों की स्पोर्ट पर जिंदा हैं। इनकी सरकार ने जानबूझकर बेईमानी की और न तो सुप्रीम कोर्ट में और न ही हाई कोर्ट में इस मामले में चैलेंज किया।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस बारे में अलग से डिबेट करा ली जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और वे लोक सभा में भी रहे हैं इसलिए उनको इस बारे में पता है। अब मैं सब्सिडी की बात पर आ रहा हूं। कोई भी सरकार अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए सब्सिडी देती है उसमें चाहे एग्रीकल्चर सैक्टर हो या कोई दूसरा सैक्टर हो इसके लिए प्रावधान अवश्य रखती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1600 करोड़ रुपये के किसानों के बिजली के बिल माफ किए जिसका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। जब अच्छी बात चली तो कोई किन्तु परन्तु नहीं था। हमने भी हाउस में इस बात के लिए प्रशंसा की कि मुख्यमंत्री जी लोगों को कुछ दे रहे हैं। लेकिन किन्तु परन्तु लगने के बाद में हमें पता लगा कि कितने लोगों को फायदा हुआ है। जो 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिल के माफ किए हैं वे तो आपने एच०दी०पी०एन० को देने होंगे। 22 प्रतिशत बढ़ौत्तरी वर्ष 2004 में सब्सिडी पर हुई है जो घटकर वर्ष 2006 में 20 प्रतिशत तक रह गई है। यह अनुमानित पैसा कहां से आयेगा ? आज अगर मुख्यमंत्री जी यह घोषणा कर दें कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का आबियाना माफ कर दिया जायेगा यह बहुत अच्छी बात होगी। हमारी सरकार ने भी यह बात कही थी। लेकिन वह इसको पूरा नहीं कर पाई थी। यह बात अच्छी होगी अगर मुख्यमंत्री जी कह दें कि आबियाना माफ कर दिया जायेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपका प्वायंट ऑफ आर्डर क्या है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं। स्पीकर सर, पिछली सरकार ने इलैक्शन से पहले आबियाना माफ करने की सिर्फ घोषणा की थी लेकिन उसके बाद इस बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई कि आबियाना माफ किया जाता है। पिछली सरकार की तरफ से इलैक्शन से पहले टोटली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बाकायदा सब-कमेटी बनाई गई थी। लेकिन कागजी कार्यवाही कोई नहीं हुई वह सिर्फ एक न्यूज आईटम था और कुछ नहीं किया गया।

डा0 सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, अब मैं सैण्ट्रली स्पौंस्र्ड स्कीम की तरफ आता हूं। केन्द्र सरकार से इन स्कीम्ज के तहत वर्ष 2004-05 में 600 करोड़ रुपया, वर्ष 2005-2006 में 425 करोड़ रुपया और वर्ष 2006-07 में 575 करोड़ रुपया मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध करुंगा क्योंकि ये केन्द्र सरकार के बड़े चहेते मुख्यमंत्री हैं, बड़े लाडले मुख्यमंत्री हैं, अगर ऐसा है तो 575 करोड़ रुपये की बजाए ये 1000-2000 करोड़ रुपये का कोई स्पैशल पैकेज केन्द्र सरकार से हरियाणा के लिए लेकर आएं। मैं नाम लिए बगैर कहता हू कि आपके रोहतक के सांसद ने कहा कि हम हरियाणा के लिए स्पैशल पैकेज लेकर आयेंगे। लेकिन स्पैशल पैकेज तो सिर्फ सात स्टेटस को ही मिला है। स्पैशल पैकेज के नाम से तो हरियाणा को कुछ भी नहीं मिला। अगर इनकी केन्द्र में इतनी बात है तो ये हरियाणा के लिए 2000-4000 करोड़ रुपये का स्पैशल पैकेज लाते ताकि हरियाणा की जनता आपको सराहती और हम भी सराहते । अब मैं इन्फ्रास्ट्रक्चर की तरफ आता हूं।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आप कन्कलूड कीजिए क्योंकि आपको बोलते हुए 50 मिनट्स हो गये हैं।

डा0 सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। जहां तक रोड्ज के बजट के बारे में लिखा है कि रोड्ज के लिए 54 करोड़ रुपये दिए हैं। आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है कि रोड्ज के लिए 54 करोड़ रुपये दिए गये हैं। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2005 में 51 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं और बजट स्पीच में कहा गया है कि हमने इतनी सड़कें बना दी यह कर दिया वह कर दिया। केवल 51 किलोमीटर सड़कें बनाई यह बड़े शर्म की बात है। इससे अच्छा न बनाते तो ठीक था। अब मैं पावर के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच के बारे में बता रहा हूं। वित्तमंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि हम 4000 मेगावाट बिजली अगली पंचवर्षीय योजना में पैदा करेंगे। अगली पंचवर्षीय योजना का मतलब है जो 2007 से शुरू होगी और 2012 में खत्म होगी और मुख्यमंत्री जी कहीं पर जाते हैं तो कहते हैं कि साढ़े तीन साल में 4000 मेगावाट बिजली पैदा कर देंगे। पिछले एक साल से मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक साल से कह रहे हैं और एक साल यह हो जायेगा। क्या आगे एक में साल 4000 मेगावाट बिजली पैदा हो जायेगी और हरियाणा की बिजली की समस्या खत्म हो जायेगी। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि पिछले साल जो हमारे बिजली के संयत्र हैं जिनसे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। वे इनएफीसिर्यैसी की वजह से पूरी बिजली पैदा नहीं कर पाये। सरकार अपने अधिकारियों पर लगाम कसती और यह आदेश देती कि अगर बिजली

का कोई संयंत्र खराब हो गया तो उस जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाये। गैर जिम्मेवारी की वजह से हमें 250 से 500 मेगावाट बिजली कम मिली है। सरकार को चाहिए कि जो हमारे बिजली संयंत्र खराब हो जायें उनको जल्दी से ठीक करवाया जाये और प्रदेश की जनता का नुक्सान होने से बचाया जाये। इसी तरह जहां तक रूरल इम्पलोयमैंट की बात है, मेरे हल्के के डींग गांव से शायद स्पीकर सर, आप उद्घाटन करके आये थे। केन्द्र सरकार ने जो जोब गारंटी की योजना भेजी है उसके तहत स्किल्ड लेबर को 365 दिन में 100 दिन रोजगार दिया जायेगा जो कि जोहड़ आदि की सफाई का और नहरों आदि की खुदाई का काम करेंगे। मैं वित्तमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसमें सरकार ने मिनिमम वेसिज 90 रुपये प्रति दिन के हिसाब से रखे हैं और आज हरियाणा के मिनिमम वेसिज 100 रुपये हैं। जब हरियाणा के मिनिमम वेजिज 100 रुपये हैं तो 90 रुपये में कौन काम करेगा। यह असंवैधानिक भी है। जहां कानून बना हुआ है कि हरियाणा प्रदेश के एक मजदूर को मिनिमम वेजिज एक दिन का 100 रुपये मिलेगा और रोजगार गारंटी के तहत आप यह कहते हैं कि 90 रुपये दिये जायेंगे। इससे संविधान की उल्लंघना हुई या नहीं हुई, एक कानून की उल्लंघना हुई या नहीं हुई ? ये बातें शायद सरकार की जानकारी में नहीं आई होंगी। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूंगा तो ये सारे खड़े हो जायेंगे और स्पीकर सर, आप मुझे कहेंगे कि बैठ जा। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहता अभी कल-परसों की बात है कि कैथल में लोगों ने किस तरह से रोष प्रकट किया था वहां। 100 से ज्यादा लोगों से फिरौतियां मांगी गईं और एक व्यापारी नरेन्द्र अरोड़ा की हत्या कर दी गई। यह एक जगह की बात है दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही हो रहा है। बहादुरगढ़ में देखें कि बंद कमरे में सो रहे एक आदमी को तेल डालकर जला दिया गया और सरकार कहती है कि हम प्रदेश की जनता को भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं डाक्टर साहब इनकी सरकार के समय की बात याद दिलाना चाहूंगी कि बहादुरगढ़ में उस समय बेबी किल्लर ने बहुत सी बच्चियों की हत्या की थी। उस बात को ये भूल गये हैं।

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा कि हमने 41 नई स्कीमें शुरू की हैं, 35 बंद कर दीं। बहन करतार देवी जी बैठी हुई हैं। चौधरी भजन लाल जी बैठे नहीं हैं। जिस समय वे मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी "अपनी बेटी अपना धन"। सरकार ने उस स्कीम पर कहा है कि दूसरी लड़की पैदा होने पर इनसैंटिव देंगे। जिस बेचारे के एक लड़की होगी वह तो मारा गया। आप क्या चाहते हैं,जनसंख्या कंट्रोल करना चाहते हैं या लिंग अनुपात को कम करना चाहते हैं। अगर आप लिंग अनुपात को कम करना चाहते हैं तो यह स्कीम पहली लड़की के पैदा होने से शुरू कीजिए। हो सकता है कोई कपल ऐसा हो जो एक ही बच्चा चाहता हो। पण्डित जवाहर लाल नेहरू के एक ही लड़की श्रीमती इंदिरा गांधी थी।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने अभी कैथल की घटना की बात की है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर जो दो-तीन गैंग हैं वे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के परवर्दा हैं, यह बात सबको मालूम है। कांग्रेस का राज आने के बाद अपराधियों को जेलों में जरूर डाला गया है। (विघ्न) जब तक ओम प्रकाश चौटाला के बदमाशों को जड़ से नहीं उखाड़ दिया जायेगा तब तक ये वारदातें बंद नहीं होंगी। (विघ्न)

डा0 सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, कोई बात अगर उल्टी पड़ती दिखे या सरकार पर उल्टी पड़ती दिखे तो कहते हैं कि चौटाला ने करवा दिया। (विघ्न) सर, हमारी सरकार की कुछ स्कीमें आपकी सरकार ने अपनाई हैं देवी रूपक योजना आज भी स्टैंड स्टिल है। ऐसी योजनाएं जो लाभकारी हैं उनको सरकार ने अपनाया है यह अच्छी बात है। कुछ स्कीमें आपकी सरकार ने बदल दी हैं जैसे इम्पलॉयमैंट की बात है, उसमें भी कई प्रकार की शर्तें लगी दी हैं दस जमा दो के बाद डिप्लोमा। मुख्यमन्त्री जी, इससे लाभार्थी कम होते हैं। अगर लाभार्थी कम होंगे तो नुक्सान किसका होगा, इसका नुक्सान हरियाणा प्रदेश के लोगों को जाएगा। बैठकर अच्छी स्कीमें बनाएंगे तो लोग सरकार की तारीफ करेंगे। हम तो हो सकता है दबे कुचले हैं और कुछ विरोध कर देंगे कि यह ठीक नहीं है लेकिन जो अच्छे काम हैं लोग उनकी तारीफ करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बहन करतारी देवी जी यहां पर बैठी हुई हैं उन्होंने 'अपनी बेटी अपना धन' योजना शुरू करवाई थी। यह बहुत ही अच्छी योजना थी लेकिन अब सरकार ने इस योजना को बन्द कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो अच्छी स्कीमें हैं वे चलती रहनी चाहिएं। प्रियदर्शनी शगुन योजना के तहत 5100/-रुपये का शगुन देकर हमारी सरकार ने यह योजना शुरू की थी। सरकार ने 5000 रुपये की राशि बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। मैं इसके लिए सरकार की तारीफ करता हूं। गरीब आदमी का 50,000 रुपये में मकान बन जाता है। अगर सरकार इस प्रकार के काम करेगी तो हर आदमी सरकार की तारीफ करेगा लेकिन यह नहीं है कि बहकावे में आकर नाजायज तरीके से या बदले की भावना से काम करें और जो शहीद हैं, स्वतन्त्रता सेनानी हैं उनका नाम हटा दें। अब चौधरी देवी लाल के नाम से थर्मल प्लांट चल रहा था। इससे प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा था और इसके नाम में कोई हर्ज नहीं था। फिर उनका नाम क्यों हटाया गया है, क्या इससे कहीं पर कोई फर्क पड़ गया है। क्या चौधरी देवी लाल स्वतन्त्रता सेनानी नहीं थे ? क्या आज थर्मल पावर प्लांट में कुछ बदल गया है? चौधरी देवी लाल का नारा था, भ्रष्टाचार बन्द बिजली का पानी का प्रबन्ध और उन्हीं के नाम से उस यूनिट का नाम रखा गया था। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में पावर प्लांट का नींव पत्थर रखा गया था। लेकिन आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। ये कहते हैं कि गैस बेस्ड प्लांट लगाएंगे। ये गैस बेस्ड प्लांट कैसे लगाएंगे, क्या वित्त मन्त्री जी इस बात का जवाब देंगे ? केन्द्र सरकार कहती है कि हम वर्ष 2009 तक गैस उपलब्ध नहीं करवा सकते, तो गैस बेस्ड थर्मल प्लांट का औचित्य हमें बताइये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे तो अच्छा है कि थर्मल पावर प्लांट लगाएं। ये कहते हैं कि कोयला उधर से लाना पड़ेगा। कोयला तो रेल ढो कर लाती है हमें कोयला सिर पर ढो कर तो नहीं लाना है। अगर हमें कोयला सिर पर ढो कर लाना हो तो अलग बात है। यह कोयला रेलगाड़ी ढो कर लाएगी। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि आप अच्छे प्रोजैक्टस लगाएंगे तो इससे मजा आएगा और प्रदेश की जरूरत पूरी होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश को बिजली की जरूरत है, बिजली दीजिए, प्रदेश को पानी की जरूरत है, पानी दीजिए, प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की जरूरत है प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर सुधारिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुद डर लगा रहता है कि सड़क पर निकाल जाऊं तो पता नहीं कौन मरवा दे (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सरकार ने टैक्स में रियायत लाने की कोशिश की और कहा है कि हमने टैक्स घटाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैडिसीन पर टैक्स घटा दिया है। यह टैक्स सरकार ने नहीं घटाया यह टैक्स वैट ने घटाया है। कई और प्रदेशों में जब वैट लागू नहीं था तो कहीं पर 10%, कहीं पर 12% और कहीं पर साढ़े बारह परसैंट टैक्स था। लेकिन पड़ौसी प्रदेशों में वैट लगाया गया तो आपको फायदा

हो गया। ऑटोमैटिकली आपको टैक्स बढ़ाना पड़ा। वैट को लागू करके शुरू में आपने टायर और ट्यूब पर साढ़े बारह परसैंट टैक्स लगा दिया। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि बेचारे रेहड़ा वाहने वालों पर भी आपने गलती से टैक्स लगा दिया था। जो रेहड़ा वाहते हैं और रेहड़े के लिए टायर ट्यूब खरीदते हैं शायद सरकार को इनका ध्यान नहीं रहा और बाद में आपने इसके बारे में विचार किया कि यह गलत हो गया इसलिए वह साढ़े बारह परसैंट से आपने जीरो परसैंट कर दिया है। इसी तरह से सरकार लीकर की एक नई पॉलिसी लाई। शराब की नीति के बारे में सरकार कहती है कि हमने रैवेन्यू बढ़ाया है। सरकार ने पिछली बार कहा था कि हमें रैवेन्यू बढ़ाना है और सरकार ने कहा कि रैवेन्यू हमने बढ़ा दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह रैवेन्यू तब बढ़ा था जब सरकार ने यह कहा कि शराब का इतना कोटा बेचना है। जितना कोटा फिक्स था आपने उससे कई गुणा कोटा बढ़ा दिया और उसमें सरकार ने रैवेन्यू कलैक्शन कर ली। यह बात लोगों को गुमराह करने वाली है। हम इस बात को मानते हैं और खुले दिल से मानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को गुमराह करके ये लोग यहां पर सत्ता में बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये लोग अब तो प्रदेश की जनता को गुमराह न करें कम से कम अब तो अपनी जिम्मेदारी समझकर उस जिम्मेदारी के साथ लोगों के काम करें। अच्छे कामों में हम इनके साथ रहेंगे। जिस तरह से हाईकोर्ट वाले मामले में हमने सरकार को समर्थन दिया है। एस०वाई०एल० का मुद्दा या इंटर स्टेट वाटर ट्रीटी का मुद्दा सरकार लेकर आए हम सरकार के साथ हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, अब तो आप बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दे रहे हैं लेकिन पिछले पांच छः साल के राज में कहां गए थे। (विघ्न) अब आप कन्कलूड करें।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, मुझे आप 5 मिनट का टाईम और दे दें। मैं अपनी स्पीच कन्कलूड कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आपको बोलते हुए एक घंटा हो गया है। आप 5.20 पर बोलने शुरू हो गए थे। (विघ्न) अपने जो भी कहना है वह लिखकर दे देना। (विघ्न) अर्जन सिंह जी, आप बोलें। डाक्टर साहब, ये बी०एस०पी० के अकेले सदस्य हैं, इनको भी बोलने का समय दें। (Interruptions) No, no, please sit down. There are also other members of opposition side who want to speak. आप इतने बूटल मैटर में न जाएं। दूसरे मैम्बर्ज ने भी बोलना है। (विघ्न)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह बजट हरियाणा के लोगों के पक्ष में नहीं इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

Mr. Speaker : Now, Ch. Arjan Singh will speak.

चौ० अर्जन सिंह (छछरौली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के ऊपर कहना चाहूंगा कि राव दान सिंह ने जो डिटेल में बातें कही हैं मैं उनसे सहमत हूं और उन बातों को दोबारा नहीं कहूंगा और इससे सदन के टाईम की भी बचत हो जाएगी। मेरे द्वारा उनकी तरह से डिटेल में नहीं कहा जाता है जिस तरह से राव दिन सिंह ने कहा है। स्पीकर सर, मुझे तो ऐसा दिखता है कि

[चौ० अर्जन सिंह]

आप भी इनैलों वालों से खुंदक रखते हो और आपको ये 9 भी ओपरे लग रहे हैं। जितना समय आप इनको सदन में बोलने के लिए देंगे ये उतना ही सदन में गलत बोलेंगे और इनकी वे सारी बातें पब्लिक में जाएंगी तथा इस बार पब्लिक इनको बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं भी बी०एस०पी० का अपोजीशन का सदस्य हूं लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहता हूं और सभी को ऐसा ही कहना चाहिए। हम आज जो कुछ भी यहां पर कह कर जाएंगे, हम से पहले ही वह बात जनता में चली जाएगी। आज जनता किसी चीज से अनजान नहीं है वह सब कुछ जानती है। (विघ्न) भाई मैं बजट का समर्थन करता हूं और जो बजट इस सरकार ने दिया है वह बहुत ही बढ़िया दिया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जितनी देर ये भाई बोल रहे थे तो मैं चुप था और अब मैं बोल रहा हूं तो इनकी भी चुप रहना चाहिए। (विघ्न)

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, माननीय सदस्य अपनी बात आपके समक्ष रख रहे हैं और ये भी सदन में विपक्ष के सदस्य हैं। इनसे पहले बोलते हुए डाक्टर साहब एक घंटा बड़े आराम से बोल रहे थे और उनको किसी ने भी इन्ट्रप्ट नहीं किया था। डाक्टर साहब, आप संसदीय परम्पराओं को निभाना शुरू कीजिए। ये भी विपक्ष के सम्मानित सदस्य हैं और आपको दूसरे सदस्यों को भी सम्मान देना चाहिए। चौटाला साहब तो आपको सम्मान देते नहीं है और जब वे यहां सदन में नहीं है तो आप हमसे ही कुछ सीख लो।

चौ० अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्हें अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है वह इन्हें बहुत ही औछी लगती है क्योंकि इनके दिन माड़े हैं। इन्दौरा जी, मैं आपसे आपकी हमदर्दी में ही कह रहा हूं कि आप जो कुछ भी यहां पर कह रहे हैं वह बात पब्लिक में जा रही है और पब्लिक अच्छा बुरा सब कुछ समझती है। यही कारण तो है कि आप 57 में से आज 9 ही रह गए हो। ऐसी बातें करके क्या आप जो 9 यहां पर हो यह भी नहीं रहना चाहते हो। आपको जो जायज बात हो वही कहनी चाहिए। आज जो आपको यहां पर बोलने का मौका मिल रहा है और आप जो यहां पर बोल रहे हो इससे तो ऐसा लगता है कि पिछली सरकार के साढ़े पांच साल के काल में आपको बोलने का मौका नहीं मिला था। आपकी सरकार साढ़े पांच, छः साल राज में रही लेकिन आपने कोई भी विकास के काम नहीं किए हैं। आज लोग इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप लोग तो आज भी यही चाहते हो कि लोग बर्बादी की कागार पर खड़े हो जाएं। (विघ्न) मैं राजनीति में जरूर हूं लेकिन राजनीतिक आदमी नहीं हूं। हमें जो बात सच्ची होती है उसको ही कहना चाहिए। आज की तारीख में हरियाणा में अमन और चैन है। मौजूदा सरकार का कार्यकाल एक साल का हो गया है। इस सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं वह पांच साल में सामने आ जाएंगी। आप इस सरकार की एक साल की उपलब्धियां देख लो । आपको जो भी बातें अच्छी लगती हैं उनके बारे में आप यहां पर नहीं बोलते हो। आपने जो काम अपने शासन काल में नहीं करे हैं उनको आज उजागर कर रहे हो। मेरे कहने का भाव यह है कि आप जो भी पब्लिक हित में बात कहेंगे वहीं बात पब्लिक को अच्छी लगेगी। अगर आप लोग ज्यादा टोका टाकी करोगे कि यह नहीं होना चाहिए वह नहीं होना चाहिए। आपकी सारी बातों को लोग बाहर सुन रहे हैं, लोगों के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हुए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इनके नेता की बात बताता हूं। सत्ता में आने से पहले इनके नेता कहते थे कि गन्ने का भाव 150 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। जब वे कुर्सी पर बैठ गए तो कहने लगे 100 रुपए प्रति क्विंटल से कम होना चाहिए। (विघ्न) इलैक्शन टाईम से पहले इन्होंने गन्ने का भाव 10 रुपए प्रति

क्विंटल बढाया था और उसके बाद 16 रुपए वापिस कर लिए। बिजली के नाम पर ये कहते थे और उस बारे में इन्होंने मुद्दा बनाया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली पानी मुफ्त देंगे। लोग भी इस बात का इन्तजार कर रहे थे कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आएगी तो बिजली पानी फ्री मिलेगा। लेकिन जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सत्ता में आ गए तो फ्री तो अपनी ऐसी तैसी में गया, ये बिजली के मीटर कहीं से ऐसे लेकर आए कि बिजली हो या न हो मीटर सारी रात चलता रहता था। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां छछरौली में एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में 3 चीजें ही पूछी जाती थीं। वहां पर लोग स्कूल के बारे में कहते थे तो कहते थे कि नहीं, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वे कहते थे कि शमशान घाट का रास्ता ठीक है। शमशान घाट में अपने आप चला जा। आप ही बताएं शमशान घाट में जाने की किसको रोज जरूरत पड़ती है। वे तो दो ही चीजें पूछते थे शमशान घाट और बढ़ते जुर्म। (विघ्न) आप मेरी बात सुने, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैं वद्ध आश्रम के बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूं। जो हमारे बजुर्ग हैं वह यह सोचकर बच्चे पैदा करते थे कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अध्यक्ष महोदय, वृद्ध आश्रम में या तो किसी की रूचि हो, पानी हो, कोई कपड़ा हो, कोई टेलीविजन धरा हो तब तो बात है लेकिन वहां ऐसा भी कुछ नहीं है लेकिन पिछली सरकार ने बजुर्गों की, मां बाप की और बच्चों की वह हमदर्दी भी खत्म कर दी जो होनी चाहिए। उनकी केवल यह पैसा खाने की योजना थी। अध्यक्ष महोदय, एक भी वृद्ध आश्रम ऐसा नहीं है जो आज सही बचा हो। वे सारे के सारे गिर लिए हैं। उनका यह ड्रामा लोगों को पसन्द नहीं आता है। जो इन लोगों ने काम किए थे उसका रिजल्ट इन लोगों ने देख लिया है। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसकी प्रशंसा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपको मालूम ही है कि अगर एक-एक आईटम को लिया जाए तो काफी समय लग जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को जल्दी समाप्त करूं। सरकार ने सबसे पहले भय मुक्त राज और इंसाफ एवं बगैर रिश्वत के सरकार चलाने का वायदा किया था और इसको वह पूरा करने जा रही है। आपको मालूम ही है कि पिछली सरकार के समय में बाढ़ ही खेत को खाती थी और जब ऐसा हो तो खेत कैसे बच सकता था। पिछली सरकार के मंत्री कानून को तोड़कर मनमानी करते थे। आपको पता ही है कि हरियाणा के जितने बड़े-बड़े उद्योग उस समय थे, वह पलायन क्यों कर गए थे क्योंकि पिछली सरकार ने लूट खसौट का काम किया था। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बुलाकर उनसे करोड़ों रुपये की डिमांड की जाती थी और अगर वह पैसा नहीं देते थे तो उसी वक्त उनको धमकी दी जाती थी। हमारी यह सरकार आज हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए जितनी कोशिश कर रही है वह काबिले तारीफ है। जो पहले बड़े-बड़े उद्योग यहां से पलायन करके चले गये थे वह आज वापस आने में अपनी रूचि दिखा रहे हैं। इसके अलावा विदेशी लोग भी हरियाणा में अपने उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं। हमारे नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने जो प्लान बनाया है उसमें रूचि दिखाकर सारी दुनिया के उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक वह सरकार थी जब उद्योग यहां से पलायन कर रहे थे। मैं आपको पिछली सरकार के मंत्रियों के बारे में बताना चाहता हूं मैं आपको हांसी की मिसाल देना चाहता हूं। पिछली सरकार के लोकल बॉडीज मंत्री ने कालोनी बसाने के नाम से एक इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट कालोनी बसायी थी लेकिन उसमें कोई भी बिजनैस नहीं हो सकता था। उस मंत्री ने अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करके उस कालोनी में प्लाट

[श्री अमीर चन्द मक्कड]

काटे थे। उसने एक पैट्रोल पम्प भी उस रिहायशी कालोनी में लगाया था। हालांकि रिहायशी कालोनी में पैट्रोल पम्प लगाने की इजाजत नहीं होती लेकिन उसने अफसरान पर दबाव देकर और एन०ओ०सी० लेकर पैट्रोल पम्प लगा दिया था। उसने म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन पर भी पैट्रोल पम्प लगा दिया था। मैंने आते ही इस बारे में एक क्वैश्चन भी दिया था लेकिन उसका अफसरों ने गलत जबाव दिया था। जब मैंने दोबारा लिखा और बताया कि यह पैट्रोल पम्प म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन घेरकर लगाया गया है तो उसके बाद उसने वह पीछे हटाकर लगाया लेकिन आज तक भी वह पैट्रोल पम्प नहीं हटाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की इंक्वायरी करवायी जाए। जिन अधिकारियों ने अनियमितताएं की हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। दुकानों के पास इतनी भीड़ रहती है कि वहां दुर्घटना होने का खतरा हमेशा रहता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। आज हर गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है। इस बजट में शिक्षा के लिए काफी पैसे का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में सरकार अपने पावों पर खड़े होने के काबिल बन गई है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 21st March, 2006.

*18.30 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 21st March, 2006.)

41254—H.V.S.—H.G.P., Chd.